

हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

5 मार्च, 1979

खंड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 5 मार्च, 1979

पृष्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(4)1
तारांकित प्र न एवं उतर	(4)2
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर	(4)24
अतारांकित प्र न एवं उतर	(4)30
ध्यानाकर्षण सूचना— कृशि उपज की कीमतों के बहुत ज्यादा गिरने संबंधी	(4)35
राजपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनराम्भ)	(4)37
वाक आउट	(4)66
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनराम्भ)	(4)67
सदस्य को निकालना	(4)67
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनराम्भ)	(4)70

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 5 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 14:00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाक प्रस्ताव

Mr. Speaker: A Minister to make the obituary reference.

वित्त मंत्री(श्री मूल चंद जैन): मान्यवर स्पीकर साहब, श्री जयरामदास दौलत राम, जो असम के भूतपूर्व गवर्नर रहे हैं का अकस्मात स्वर्गवास हो गया है। मैं उनके स्वर्गवास होने पर भाक-प्रस्ताव पे । करता हूं और यह सुझाव देता हूं कि उनके परिवार को इस भाक प्रस्ताव की सूचना दी जाये। जहां तक श्री जयरामदास दौलतराम जी के जीवन का संबंध है वह 1892 में हैदराबाद सिंध में पैदा हुए जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने 1915 में वकालत पास की और फिर कराची में 1919 तक वकालत करते रहे। 1916 के होमरूल आन्दोलन में उन्होंने भारत की और फिर 1919 के सत्याग्रह आंदोलन, यानि नानकोआप्रे ।न

आन्दोलन में 1920-21 के आन्दोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। वह कराची में जारी 1921 का जो हिंदू अखबार था उसके एडीटर रहे और उनको उस वक्त दो साल की सख्त कैद की सजा हुई। वह बम्बई लैजिस्लेटिव कौंसिल के 1926-29 तक मैम्बर रहे उन्होंने फिर 1930-34 के सत्याग्रह मूवमेंट में हिस्सा लिया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1930-34 तक जनरल सैक्रेटरी रहे। वे बिहार के 1947 में गवर्नर रहे और 1947 से 50 तक भारत में फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। बहुत से हमारे देश के चोटी के नेताओं में उनका नाम भामिल है। उनकी मौत से सारे देश को बहुत बड़ी हानि पहुची है। इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी अखबार-नवीस और स्टेटसमैन जैसा कि मैंने भुरु में उनके बारे में कहा है, कि निधन पर यह हाउस उनके परिवार के प्रति अपनी दिली सहानुभूति व्यक्त करता है और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को संवेदना संदेश भेजा जाए।

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय श्री जयरामदास दौलत राम का जो अक्समात निधन हुआ और उसके बारे में जो भाक-प्रस्ताव सदन के सामने आया है मैं भी अपने आप को उसमें भामिल करता हूं। इस देश की स्वतंत्रता के लिये अनेकों भारतीयों ने जो संघर्ष किया, अंग्रेजों की जेलों में गये उनमें श्री जयरामदास दौलतराम जी भी एक प्रमुख व्यक्ति थे और स्वतंत्रता से पहले भी उन्होंने अनेकों पदों पर देश सेवा की और भारत सरकार में वे फूड मिनिस्टर रहे। एक पुराने स्वतंत्रता

सेनानी और अच्छे स्टेटसमैन होने के अलावा वे बहुत कामयाब फूड मिनिस्टर भी थे। मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस भाक प्रस्ताव में भामिल होता हूँ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा(मेहम): अध्यक्ष महोदय, जो भाक प्रस्ताव बाबू मूल चंद जैन जी ने सदन में रखा है मैं भी इसमें अपने आप को भामिल करते हुए दो भाब्द कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, यह तो सभी जानते हैं कि मौत के हाथ बहुत लम्बे होते हैं और कोई भी जीव इससे बच कर नहीं रह सकता लेकिन अध्यक्ष महोदय जिस महान विभूति का हमारे सामने जिक है वे दे । के बहुत बड़े दे । भक्त थे। वे इस दे । के सच्चे सपूत थे। जो इस प्रस्ताव में बाबू मूल चंद जैन जी ने उनके भिन्न भिन्न क्षेत्रों के कार्यों को व्यक्त किया इससे जाहिर होता है कि वे इस दे । की सेवाओं के लिये चाहे वह अखबार का क्षेत्र हो चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र हो अपने को अर्पित करते रहे। ऐसी महान विभूति का हमारे दे । से उठ जाना, हमारे बीच से उठ जाना भाक का कारण है। मैं और कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि ऐसी ऐसी महान विभूतियों के उठ जाने के बाद कुछ नहीं बचता। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमें रास्ता दिया है, जो डायरैक् ान्ज दी है उन पर चलकर हमें फायदा उठाना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं भी श्री जयरामदास दौलत राम जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: श्री जयरामदास दौलतराम जी के बारे में इस हाउस के सभी मैम्बरों के दिल में गहरी हमदर्दी है और मैं अपने आप को इसमें भामिल करता हूँ। उनकी बेगर्ज सेवाओं और सच्चे कैरेक्टर की वजह से उन्हें महात्मा गांधी ने खुद भुद्ध कुन्दन यानी खालिस सोने का नाम दिया था। भायद बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि वह हर रोज 21 घंटे सख्त मेहनत से काम करते थे और सिर्फ तीन घंटे की नींद उन्हें काफी थी। वे गीता के उपदे 1 पर पुरा यकीन रखते थे, निश्काम कर्म के बारे में न सिर्फ वे उपदे 1 देते थे बल्कि उस पर अमल भी करते थे। उनके स्वर्गवास होने से दे 1 को न पूरी होने वाली हानि यानी इर-रीपेयरेबल नुकसान पहुंचा है। मैं इस हाउस की भावनाओं को भाोकजदा परिवार तक पहुंचाऊंगा। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस स्वर्गवास नेता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये हम खड़े होकर दो मिनट मौन धारण करें।

(इस समय सभा के सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्मा की याद में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

.....

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहिबान अब सवाल होंगे।

Upgradation of Schools

***1001. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that no Middle School has been upgraded to High/High Secondary School in the Jhajjar Assembly constituency since 1977, if, so the reasons therefore; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade any Middle School to High/Higher Secodary School in the Jhajjar Assembly constituency during the current financial year or the next financial year?

शिक्षा मंत्री(श्री हीरा नंद आर्य):

(क) जी हां, इस विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 1977 से किसी माध्यमिक स्कूल का स्तर उच्च या उच्चतर नहीं किया गया, परन्तु वर्ष 1977-78 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, तुम्बाहेड़ी का स्तर माध्यमिक तक इस विधान सभा क्षेत्र से बनाया गया।

(ख) जी हां, 1970-80 के दौरान।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि 1977-78 में झज्जर के अन्दर कोई स्कूल मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि 1977-78 में केवल 40 मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड हुए थे और 71 प्राइमरी से मिडिल अपग्रेड हुए थे इसलिए यह सम्भव नहीं था कि सभी कांस्टीच्युएंसीज में अपग्रेड किये जाते।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हर इलाके में एक स्कूल दिया गया था क्या झज्जर कांस्टीच्युएंसी में कोई स्कूल अपग्रेड किया गया या नहीं?

श्री हीरा नंद आर्य: झज्जर हल्के में 1977-78 मैं केवल एक प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल अपग्रेड किया गया है।

कैप्टन मांगे राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया था कि हम हर साल हर हल्के में दो स्कूल अपग्रेड करेंगे लेकिन मेरा हल्का जो फ्लड इफैक्टिड एरिया है उसमें कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया है। स्पीकर साहब जब भी स्कूल अपग्रेड करने को कहा गया तो दोबारा विचार किया जायेगा यह कह दिया गया। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरी कांस्टीच्युएंसी में कितने स्कूल प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई किये जायेंगे?

श्री हीरा नंद आर्य: इस समय वहां कितने स्कूल अपग्रेड किये जायेंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सारी स्टेट में 90 प्राइमरी से मिडल और 90 मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करने का विचार है।

श्री जगन नाथ: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों को अपग्रेड करते वक्त लोगों की या हल्कों की आव यकताओं को देखा जाता है या कोई काइटेरिया बनाया जाता है?

श्री हीरा नंद आर्य: लोगों की आव यकताओं को देख कर ही काइटेरिया बनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

कामरेड भांकर लाल: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिरसा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इस साल कोई प्राइमरी स्कूल से मिडल और मिडल स्कूल से हाई स्कूल अपग्रेड किया है?

श्री हीरा नंद आर्य: इस सवाल का मुख्य सवाल से कोई संबंध नहीं है। मैम्बर साहब अलग से नोटिस दे दें। जवाब दे दिया जाएगा।

डा० बृज मोहन गुप्ता: मंत्री महोदय ने बताया है कि इस साल 90 स्कूल प्राइमरी से मिडल और 90 मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करने हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह हर कांस्टीच्युएंसी में बराबर—बराबर स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे, कोई डिस्किमिने इन तो नहीं की जाएगी?

श्री हीरा नंद आर्य: मैं समझता हूं कि बराबर—बराबर अपग्रेड करने से तो डिस्कीमिने इन हो सकती है, इसलिये जहां जरूरत होगी वहां अपग्रेड किये जाएंगे।

श्री भाम ेर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल अपग्रेड करते वक्त बोर्डर एरियाज को कोई प्रैफरेंस दी जाती है या नहीं?

श्री हीरा नंद आर्य: ऐसी कोई बात नहीं है, जहां पर स्कूल अपग्रेड करने की कोई विशेष परिस्थिति हो वहां का ध्यान अवश्य रखा जाता है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल 90 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया गया। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन इलाकों के साथ ऐसा क्यों किया गया?

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब हर कांस्टीच्युएंसी में स्कूल अपग्रेड करने की बात नहीं है जहां जैनुअन होगा तो जरूर अपग्रेड कर दिया जाएगा।

श्री देवेन्द्र भार्मा: मैं तो मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि कई गांव ऐसे हैं जहां प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। क्या वहां पर सरकार का कोई प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार है?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं बनता है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, कई जगह तो मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया है कि हर कांस्टीच्युएंसी में दो-दो स्कूल अपग्रेड होंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसके अलावा एम0एल0एज0 को भी स्कूल अपग्रेड करवाने के लिये कोई कोटा दिया जायेगा या नहीं?

श्री हीरा नंद आर्य: इसमें कोटा देने की कोई बात नहीं है यह तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां उचित होगा, वहां सारी बात देख कर ही फैसला किया जाएगा।

श्री मांगे रमा गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मंत्री जी फरमा रहे हैं कि हर कांस्टीच्युएंसी में एक प्राइमरी स्कूल अपग्रेड होगा.....

श्री अध्यक्ष: यह तो कभी नहीं कहा। इन्होंने तो कहा है कि 90-90 होंगे और हर कांस्टीच्युएंसी में दो-दो होंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब मेरा तो कहना यह है कि कई बार मंत्री जी हल्कों में जा कर कह आते हैं कि फ्लां स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा लेकिन हाउस में उसके उल्ट बात कही जाती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा बाहर कही गई बात ठीक है या हाउस के अन्दर कही गई बात?

श्री हीरा नंद आर्य: हाउस सुप्रीम है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

श्री फतेह चंद विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ कांस्टीच्युएंसीज ऐसी है जहां पर इनकी कृपा दृष्टि नहीं है वहां पर कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। क्या उन कास्टीच्युएंसीज में भी कोई स्कूल अपग्रेड किया जाएगा?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी हरिचंद हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हर गांव में स्कूलों के लिये 2-2 या 3-3 लाख की बिल्डिंगज बनी हुई है। वह बच्चों के चार या छः घंटे पढ़ने के बाद खाली पड़ी रहती है। क्या उन बिल्डिंग को युटिलाइज करने के बारे में सोचेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह इस सवाल से संबंधित नहीं है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पिछले साल बाढ़हा और लौहारू इन दोनों हल्कों में कितने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं?

श्री अध्यक्ष: इनका नोटिस देना चाहिए। यह अनफेयर सवाल है।

चौधरी लाल सिंह: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो इलाके नदी नालों से धिरे हुए हैं वहां पर कोई स्पेसियल स्कूल अपग्रेड होंगे?

श्री अध्यक्ष: आपको कालका का इतना फिक्र क्यों रहता है?

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, वजीर साहब तो उस इलाके के बारे में बोल नहीं सकते हैं। इसलिये मुझे ही बोलना है क्योंकि वह इलाका मेरे साथ ही लगा हुआ है।

चौधरी गया लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जहाँ शिक्षा का अभाव है अथवा जिन क्षेत्रों में शिक्षा बहुत कम है, जैसे हसनपुर जो कि दरिया के किनारे पर है, वहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव है। क्या ऐसे इलाकों में भी कोई स्कूल अपग्रेड करने का विचार है?

श्री हीरा नंद आर्य: आव यकता के अनुसार सरकार हर एक जगह का ध्यान रखेगी।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, देहात में जब स्कूल अपग्रेड करने की बात आती है तो बिल्डिंग और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देखा जाता है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अरबन एरियाज में भी यह देखा जाएगा?

श्री हीरा नंद आर्य: यह अलग सवाल है। इसका अलग से नोटिस दीजिए। आपको सूचना दे दी जाएगी।

श्री सुमेर चंद भट्ट: अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में कितने हल्के ऐसे हैं कि जहाँ दो स्कूल अपग्रेड हैं और जहाँ दो से ज्यादा स्कूल अपग्रेड हैं?

श्री अध्यक्ष: यह सैपरेट क्वैश्चन है।

चौधरी राजेंद्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि देहातों में स्कूल अपग्रेड करते समय क्या लड़कियों के स्कूलों को

अपग्रेड करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि लड़कियों की शिक्षा में सुधार हो सके?

श्री हीरा नंद आर्य: हाउस अगर इस बात को जरूरी समझता है कि लड़कों के स्कूलों की निस्वत लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करने में प्राथमिकता दी जाए तो जब अपग्रेड करने की बात आयेगी तो हम प्रायरिटी देंगे.....

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): इस सवाल को मैं क्लीयर कर देता हूँ। लड़कियों की शिक्षा के बारे में सरकार की पालिसी यह है कि जहां से मांग आएगी, फर्स्ट प्रायरिटी लड़कियों के स्कूल को दी जाएगी।

.....

Middle and High Schools in the State

***1045. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number of Middle and High Schools respectively in the State as on the 31st December, 1978;

(b) the names of those two districts in the State wherein the number of schools at present is maximum and minimum respectively together with the number of schools therein; and

(c) the steps, if any, proposed to be taken by the Government to bring at par those two districts having minimum number of Schools with other districts?

शिक्षा मंत्री(श्री हीरा नंद आर्य):

(ए) (1)	माध्यमिक विद्यालय	790
(2)	उच्च विद्यालय	1076
(बी) (1)	माध्यमिक विद्यालयों की अधिकतम संख्या	116 (जिला हिसार)
(2)	माध्यमिक विद्यालयों की न्यूनतम संख्या	37 (जिला सिरसा)
(3)	उच्च विद्यालयों की अधिकतम संख्या	157 (जिला रोहतक)
(4)	उच्च विद्यालयों की न्यूनतम संख्या	41 (जिला सिरसा)

(सी) जिन जिलों में स्कूलों की संख्या कम है, और अगर वहां से कोई डिमांड आती है तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी संख्या दूसरे जिलों की संख्या के बराबर लाई जाएं, लेकिन यह काम एकदम नहीं हो सकता।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 157 हाई स्कूल हैं और डिस्ट्रिक्ट में 41 हैं और यह संख्या सब डिस्ट्रिक्ट्स से कम है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस डिफेंस को पूरा करने की सम्भावना है, अगर है तो कब तक यह डिफेंस पूरा हो जाएगा?

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय इस समय में निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता। लेकिन यह बात वास्तव में ठीक है कि जिला सिरसा शिक्षा के क्षेत्र में सब जिलों से पिछड़ा हुआ है।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि सिरसा जिला मिडल स्कूलों और हाई स्कूलों की दृष्टि से सब से पीछे है। इसी तरह से मेरा हलका बवानी खेड़ा भी पीछे है और इसका कारण यह था कि चौधरी बंसी लाल जब उस इलाके में जाते थे तो उन के साथ एम0एल0ए0 चाहे कांग्रेस पार्टी के थे चाहे अपोजीशन पार्टी के थे वे यह कहते थे कि जो एम0एल0ए0 मेरे साथ है उन्हीं के हल्कों में काम होगा इसलिये वे हल्के पीछे रह गए और वहां कुछ नहीं हुआ तथा स्टेट के बाकी हिस्सों में काम हो गया यही कारण है कि सिरसा जिला और बवानी खेड़ा पिछड़े हुए हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कमी कब तक पूरी की जाएगी?

श्री हीरा नंद आर्य: पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा।

चौधरी संत कंवर: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जनता सरकार आने के बाद, रोहतक और भिवानी हल्के में कितने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं?

श्री हीरा नंद आर्य: इसके लिये अलग नोटिस दें, जवाब दे दिया जाएगा।

.....

Beds in Civil Hospital at Rohtak

***1011. Shri Jai Narian:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide more beds in the Civil Hospital at Rohtak, if so, the details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा): जी हां। वर्ष 1979-80 में जनरल हस्पताल, रोहतक के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक 10 बिस्तर वार्ड तथा आप्रैान थियेटर बनाने का प्रस्ताव है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जब से मैडिकल कालेज रोहतक को यूनिवर्सिटी से अलग किया है तब से मैडिसनज की कमी के कारण उसकी बुरी

हालत हो गई है, कालेज में बैंडेज तक नहीं मिलती। क्या इस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: जरूर किया जाएगा। 20 लाख रुपये का एडी नल बजट दवाइयों के लिये पास हुआ था, इस रुपये से हर हस्पताल के अन्दर दवाइयां भेज दी गई है।

चौधरी संत कंवर: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि सिविल होस्पिटल रोहतक के अन्दर और उसके सामने से गुजरने वाली सड़क पर बरसात के दिनों में चार चार महीने तक डेढ़ डेढ़ फुट पानी खड़ा रहता है और उस पानी में से कई दिन तक गुजरना मुश्किल हो जाता है। क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने का इन्तजाम करेगी?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने मेरे ध्यान में यह बात दिलाई है। वैसे तो पी०डब्ल्यू०डी० को रिपेयर के लिये हम पैसा दे देते हैं, लेकिन चूंकि मेरे नोटिस में यह बात आई है, इसलिये इस कठिनाई को दूर किया जाएगा।

श्री मूल चंद मंगला: मंत्री महोदय ने कहा है कि बीस लाख रुपये का एडी नल बजट दवाइयां सप्लाई करने के लिये दिया है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस बीस लाख रुपये से हरियाणा के सभी हस्पतालों में दवाइयां सप्लाई

करके उनकी संतुष्टि हो जाएगी क्योंकि हरियाणा के तकरीबन सभी हस्पतालों में दवाइयों की कमी है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: यह तो मैं नहीं कह सकती कि संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन कुछ कमी को जरूर पूरा किया जाएगा और आने वाले बजट में इस उद्देश्य के लिए ज्यादा सहायता देने की कोशिश करेंगे।

श्री जय नारायण: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि जिस वक्त बरसात हो जाती है तो 10-15 दिन के लिये सिविल हस्पताल रोहतक बंद हो जाता है और काम करना बड़ा मुश्किल होता है.....

श्रीमती डा० कमला वर्मा: हस्पताल तो क्या वह सारा इलाका ही पानी के अन्दर होता है।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बीस लाख रूपया जो दवाइयों के लिए एडीशनल दिया है, उसकी डिस्ट्रिब्यूशन का क्वॉटेंटेरिया क्या फिक्स किया है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: वैसे तो पी०एच०सी० को तकरीबन बारह हजार रूपये की दवाइयां दी जाती हैं और डिस्पेंसरीज के लिए अलग कोटा है। हम इनको डायरेक्ट सप्लाय नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज के अन्दर बांट देते हैं और वहां से पी.एच.सी. और डिस्पेंसरीजों के लिये दवाइयां जाती हैं।

श्रीमती सुशमा स्वराज: क्या मंत्री महोदय बतायेंगी कि सिविल चिकित्सालय रोहतक में भौया (बैड्ज) की संख्या बढ़ाने के लिये केवल इसी चिकित्सालय को किस आधार पर चुना गया है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: सिविल चिकित्सालय रोहतक में बैड्ज की संख्या बढ़ाने के लिये हमने नहीं चुना बल्कि परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत, केंद्रीय सरकार की योजना है जिसके तहत दस बैड्ज का वार्ड और एक औप्रे इन थिएटर बनाया जाना है। इस प्रोग्राम के तहत रोहतक में भी बनाना है। यह 85 बैड्ज का हस्पताल है और दस बैड्ज का वार्ड और बन जाने से इसमें बैड्ज की संख्या 95 हो जायेगी।

श्रीमती भांति देवी: स्पीकर साहब, मैं बार बार मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात ला चुकी हूँ कि गन्नौर होस्पिटल में बहुत दिनों से लेडी डाक्टर नहीं है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि इतनी बार नोटिस में लाने के बावजूद भी, क्या कारण है कि गन्नौर में अब तक लेडी डाक्टर नहीं लगाई गई है?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का संबंध इस सवाल से नहीं है।

श्रीमती भांति देवी: मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक इसका प्रबंध करेंगे, इसके बारे में हाउस में आवासन आना चाहिए (व्यवधान)

श्रीमती डा० कमला वर्मा: जब डाक्टरज को बुलाया जाता है तो इन्टरव्यू के अन्दर लेडी डाक्टर बहुत कम आते हैं और अगर कोई आ जाए तो मैरिट में इग्नोर करके भी लेडी डाक्टर लेने का हर सम्भव प्रयत्न करते हैं ताकि हस्पतालों में लेडी डाक्टर की कमी को पूरा कर सकें। इस वक्त हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डाक्टरज मांगे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन्टरव्यूज कर लिये हैं अगर कोई लेडी डाक्टर आ गयी तो गन्नौर में लगा देंगे।

श्रीमती सुशमा स्वराज: मंत्री महोदया ने फरमाया कि सिविल चिकित्सालय रोहतक को बैडज की संख्या बढ़ाने के लिये केंद्रीय योजना के तहत चुना गया है। क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि क्या हरियाणा के सारे जिलों में यह केंद्रीय योजना लागू की जाएगी ताकि दस बैडज का एक एक वार्ड सब जिलों में बन सकें?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: योजना बिल्कुल चालू है। केवल बिल्डिंग बननी है जिसका नक्शा आर्किटेक्ट को बनाने के लिये दिया गया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज के अन्दर यह स्कीम चल रही है।

श्री दीप चंद भाटिया: स्पीकर साहब हमारे फरीदाबाद के अंदर बादशाह खान नाम का एक हस्पताल है। (विधन) उसकी बिल्डिंग तीस साल पुरानी है। बरसात के अन्दर वहां यह हालत

होती है कि वहां न तो कोई डाक्टर रह सकता है और न ही कोई मरीज रह सकता है। क्या मंत्री जी बतासंगी कि वहां नई बिल्डिंग कब तक बनाई जाएगी?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: यह प्र न मूल प्र न से संबंधित तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बता देती हूं कि कुछ दिन पहले वहां के चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर मुझे मिले थे। उन्होंने 75 हजार रूपया 31 मार्च तक इस्तेमाल करने के लिये कहा हैं। मैंने मैडिकल आफिसर को कहा है कि उस हस्पताल की छतें आदि अब य ठीक करवा ली जाएं।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि जहां तहसील हैडक्वाटर पर कोई हस्पताल नहीं है क्या वहां कोई हस्पताल बनाने की सरकार की योजना है? (विघ्न)

श्रीमती डा० कमला वर्मा: जनसंख्या, धन की उपलब्धी और मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रूरल होस्पिटल खोलने और प्राईमरी हैल्थ सेंटर अपग्रेड करने का सरकार प्रयत्न करती है।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, भाहरों के अन्दर तो सरकार स्वयं हस्पताल की बिल्डिंग बना कर देती है लेकिन मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि गांव के अन्दर जहां लोग

सरकार के नक्शे के हिसाब से बिल्डिंग बना कर देने के लिये तैयार हों वहां क्या सरकार हस्पताल खोलने की मंजूरी देगी?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: जरूर देगी।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने सोनीपत में पचास बैड वाले हस्पताल को सौ बैड का हस्पताल बनाने का एलान किया था। क्या मंत्री महोदय बताएंगी कि वहां सौ बैड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जमीन, स्टाफ और दवाइयों आदि का इंतजाम हो गया है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हो गया है।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी कहा कि जनसंख्या को देखते हुए हस्पताल खोले जाते हैं। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक तरफ तो परिवार नियोजन के द्वारा ये जनसंख्या कम करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं देने की बात करते हैं? इसका क्या मतलब है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या का अर्थ है कि वहां आस पास पांच सात गांव लगते हो ताकि काफी लोगों को सुविधा मिले। यहां जनसंख्या का तात्पर्य जनसंख्या बढ़ाने से नहीं है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, पिदले सै उन में बहिन जी ने कहा था कि तहसील गोहाना के कथरा ब्लॉक में प्राईमरी हैल्थ सेंटर की प्रपोजल है। क्या मंत्री जी बताएंगी कि वह कब तक खोल दिया जाएगा जबकि बनवास गांव वालों ने बीस हजार रूपये डिपोजिट करा दिये है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: आने वाले पांच साल प्लान में पांच प्राइमरी हैल्थ सेंटर बनेंगे। उनके लिए जो ऐप्लीकेशन आएंगी, उनमें से प्रायोरिटी बेस पर हम इसको देख लेंगे।

श्री जय नारायण: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कलानौर के लिए पच्चीस बैड का हस्पताल मंजूर किया था। क्या मंत्री जी बतायेंगी कि वह कब तक बन जाएगा?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: वर्ष 1979-80 में मुख्य मंत्री महोदय ने जो चार गांव के अन्दर 30 बैड के हस्पताल बनाने की घोशणा की है, उनका काम अब यं भुरू कर दिया जाएगा।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरे हल्का नारायणगढ़ में भाहजादपुर नाम का एक कस्बा है। उसमें एक हस्पताल है जिसका बहिन जी को पता है। उस हस्पताल के आहते में बरसात में पानी भर जाता है जिसकी वजह से कोई भी मरीज अन्दर नहीं जा सकता। क्या मंत्री महोदया उसका भी कुछ इंतजाम करेगी?

श्री अध्यक्ष: इसके बारे में आप उनसे दफ्तर में मिल लेना।

चौधरी लाल सिंह: अगर वे असैम्बली में कुछ कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनको इस बात का पता है।

Grant of Higher Pay Scale

***1067. Shri Mani Ram:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to grant higher scale of pay to those employees who have reached the maximum of the scale of their post; and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialized?

वित्त मंत्री(श्री मूल चंद जैन):

(क) जी नहीं

(ख) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

Scholarship to Harijan Students

***1074. Chaudhri Gaya Lal:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for giving scholarships at the rate of Rs. 10/- and Rs. 20/- to the Harijan students of 5th to 8th classes and 9th to 10th classes, respectively?

शिक्षा मंत्री(श्री हीरा नंद आर्य): दस रूपये से बीस रूपये वजीफा करने की कोई प्रपोजल सरकार के विचाराधीन नहीं है लेकिन सदन की इन्फर्मे टन के लिए मैं यह बता देना उचित समझता हूं कि प्राईमरी से मिडल तक कोई फीस वगैरा नहीं ली जाती। नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को आठ रूपये मासिक की दर से वजीफा दिया जाता है लेकिन इस दर को वर्ष 1979-80 में 16 रूपये कर दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि जहां वर्ष 1978-79 में वीकर सैक इंज और हरिजनों आदि के लिये पुस्तकें आदि देने के लिये 9 लाख 50 हजार रूपये देने का प्रावधान है वहां अगले वर्ष 16 लाख 87 हजार रूपया दिया जाएगा।

चौधरी गया लाल: स्पीकर साहब, वजीफे की दर 8 रूपये से 16 रूपये करने का जो एलान मंत्री महोदय ने किया है इसके लिए तो सरकार बधाई की पात्र है लेकिन एक बात मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। आज हमारे यहां प्राईमरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई वजीफा नहीं दिया जाता जबकि दूसरी स्टेटस में ऐसा नहीं है। मुझे विधान सभा की भाडयूल्ड कास्टस एवं भाडयूल्ड ट्राईब्ज कमेटी का चेयरमैन होने के नाते से दूसरी स्टेटस के लोगों से बातचीत करने पर यह पता चला है कि दूसरी स्टेटस में प्राईमरी स्कूलों में भी वजीफा दिया जाता है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वे भी इस बारे में कोई विचार करेंगे?

श्री हीरा नंद आर्य: प्राईमरी कक्षाओं में इसलिये वजीफा नहीं है क्योंकि उनमें फीस वगैरह नहीं ली जाती बल्कि फ्री ऐजुकेशन है। इसके अलावा उनको पुस्तकें भी दी जाती हैं। यहीं नहीं छात्रों को वर्दी आदि के लिये 15 रूपये भी दिए जाते हैं।

चौधरी भाग मल: अध्यक्ष महोदय, आजकल यह प्रैक्टिस है कि स्कौलरशिप साल के आखिर में दिया जाता है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में ऐसी स्कीम है जिसके तहत यह साल के आखिर में न दिया जाकर हर महीने दिया जा सके?

श्री हीरा नंद आर्य: इस पर विचार किया जा सकता है।

चौधरी राजेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि वीकर सैवराज के विद्यार्थियों को स्कौलरशिप दिया जाता है। क्या वे बतायेंगे कि आर्थिक दृष्टि से गरीब नौन-हरिजन विद्यार्थियों को भी वजीफा देने की बात सरकार के विचाराधीन है?

श्री हीरा नंद आर्य: वजीफे का अभी फिलहाल प्रबंध नहीं है। पुस्तकों के लिये आलरेडी सहायता दी जा रही है।

चौधरी ई वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, दसवीं के बाद जो वजीफा दिया जाता है वह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से

ग्रांट के रूप में आता है। मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या योगदान देती है, अगर नहीं तो कोई योगदान देने की स्कीम है?

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय स्टेट गवर्नमेंट की ओर से नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के लिये 9 लाख पचास हजार रुपये का वीकर सैव इन के लिये प्रबंध है लेकिन अगले साल के लिये 16 लाख 81 हजार रुपये का विशेष रूप से प्रबंध किया गया है ताकि वीकर सैव इन की सहायता हो सके। इसके अलावा जो हरिजन बच्चे दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा के बोर्ड के फार्म भरते हैं उनके साथ जो फीस लगती है वह उनको वापिस कर दी जाती है। उनसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, पिछले साल जींद में हरिजन लड़कों को दस हजार तख्तियां दी गई थी। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके पास कोई ित्कायत आई है कि यह तख्ती मार्किट में केवल चालिस-पचास पैसे की है जबकि वह एक रुपया चालीस पैसे के हिसाब से खरीदी गई? अगर ित्कायत आई है तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अध्यक्ष: यह सैपरेट सवाल है। इसके लिये आप नोटिस दें।

Murder Cases Registered in the State

***1085. Shir Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the district-wise total number of cases of murder registered with the Police in the State during the period from 1-4-77 to 31-12-77 and 1-4-78 to 31-12-78; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above which have been challaned in the courts after making investigation, during the period from 1-4-77 to 31-12-78?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह):

(अ) जिला	1.4.77 से 31.12.77	1.4.78 से 31.12.78
अम्बाला	14	19
कुरुक्षेत्र	17	21
करनाल	29	22
सोनीपत	13	23
रोहतक	20	23
हिसार	17	30
गुड़गावां	26	26

भिवानी	12	22
नारनौल	4	9
जींद	21	18
सिरसा	8	12
(ब) 327		

श्री फतेह चंद विज: अभी मिनिस्टर महोदय ने जवाब दिया है कि अम्बाला में 1.4.77 से 31.12.77 तक अम्बाला में 14 केसिज रजिस्टर्ड हुए और 1.4.78 से 31.12.78 तक 19 रजिस्टर्ड हुए। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में पहले पीरियड में 17 और बाद में 21 केसिज रजिस्टर्ड हुए हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि मर्डर केसिज की तादाद बढ़ती ही जा रही है और क्या सरकार कोई ऐसा पग उठाने जा रही है कि कतल की वारदातें कम हों और ला एंड आर्डर को ठीक तरह से मैनेटेन किया जा सके?

श्री बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, ये काइम अगैंसट परसन है और वह स्पोनटेनियस होते हैं। मेरे पास सन् 1966-67 से ले कर सन् 1978 तक फिगर्ज है। ये फिगर्ज घटती बढ़ती रहती है। सन् 1977-78 में जो फिगर्ज है। ये फिगर्ज 1973-74

की है स्पोनटेनियस काइम के लिये कोई व्यक्ति या सरकार बंदोबस्त नहीं कर सकती।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब जो हिनयस काइम होते है उनमें प्रोफे इनल गवाह रखे जाते है, हर केस में वही गवाह होते है क्या मिनिस्टर साहब ऐसी हिदायत देंगे कि ऐसे गवाह किसी केस में न रखे जायें? अगर ऐसे केसिज में च मदीद गवाह न हों तो उसको गवाह ने रखा जाये।

श्री बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब मैं भी बाई प्रोफेसन वकील रहा हूं। जहां तक हिनयस काइम का ताल्लुक है उनमें पार्टीज इनवाल्वड होती है वहां पर प्रोफे इनल गवाह नहीं रखे जाते है एक्साइज केसिज में जो रेडिंग पार्टी होती है उनमें तो प्रोफे इनल गवाह रखे जाते है लेकिन अब कोर्ि । । की जा रही है कि ये न रखे जाये। रूलिंग भी आ चुकी है। कोर्ि । । यही होगी कि आजाद गवाह रखे जायें।

मास्टर ि व प्रसाद: क्या मिनिस्टर महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि क्या कुछ केसिज ऐसे भी है जिनमें कातिल को पुलिस न पकड़ पाई हो?

श्री बीरेंद्र सिंह: हां ऐसे केसिज भी है।

श्री फतेह चंद विज: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बताया है कि 327 केसिज का कोर्ट में चालान हो चुका है। मैं

मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि कितने केसिज अभी तक पेंडिंग है और कितने केसिज अन-ट्रेस्ड डिकलेअर कर दिये गये?

श्री बीरेंद्र सिंह: 1.4.77 से 31.12.77 तक 181 केसिज मर्डर के हुए जिन में से 16 अन-ट्रेस्ड डिकलेअर किये गये, सात केसिज कैंसिल किये गए और तीन केसिज में इनवैस्टीगेशन जारी है। इसी तरह से 1.4.78 से 31.12.78 तक के पीरियड में 225 केसिज में से 12 केसिज अन-ट्रेस्ड डिकलेअर हुए छः कैंसिल हुए और 35 केसिज में इनवैस्टीगेशन जारी है।

चौधरी राजेंद्र सिंह: मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पुलिस से कुछ भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी हैं और जनता से बुरी तरह से पैसा लूट रहे हैं, क्या उनके मुकाबले में जो ईमानदार अफसर हैं उनको प्रमोशन दी जायेगी?

श्री बीरेंद्र सिंह: अच्छे व्यक्ति को रिवाइड दिया जाता है।

श्री जगननाथ: स्पीकर साहब, अगर किसर सरमायदार के बच्चे का खून हो जाये तो सारे देश की पुलिस अलर्ट हो जाती है, जिस प्रकार चौपड़ा के बच्चों के केस के बारे में अलर्ट हुई थी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर किसी गरीब का खून हो जाये तो क्या उस केस में भी इसी तरह से पुलिस अलर्ट होती है अभी पिछले दिनों हांसी में एक गरीब दुकानदार और उसकी औरत का उनके बच्चों के सामने बेरहमी से

कतल हुआ लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ।
उसका क्या कारण है?

श्री बीरेंद्र सिंह: इनवैस्टीगेशन तो पूरी तरह से की गई है लेकिन अभी तक कतल का पता नहीं लगा है।

चौधरी भाकरूल्ला: स्पीकर साहब मेरे घर पर 10.2.71 की चोरी हुई तकरीबन पचास हजार रूपये का माल चोरी हुआ लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। मैंने चोरों के नाम भी बताये लेकिन उन चोरों को नहीं पकड़ा गया। जब पुलिस एक सदस्य के घर होने वाले हादसे का भी पता नहीं लगा सकती तो और लोगों के साथ क्या हालत होती होगी?

श्री अध्यक्ष: परसनल केस के बारे में हाउस में पूछना उचित नहीं लगता है। आप मंत्री महोदय से दफ्तर में मिल कर बात कर लें।

चौधरी भाकरूल्ला: मैं होम मिनिस्टर से और मुख्य मंत्री जी से भी मिला हूँ?

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का सवाल से संबंध नहीं है।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब मैंने पिछले सत्र में भी सवाल किया था। एक साल पहले पपड़ना गांव में कतल

हुआ। डेढ़ दो साल के बच्चे का कलेजा निकाला गया लेकिन अभी उस कतल का पता नहीं लगा। असल कातिलों को पकड़ा नहीं जाता है और दूसरे लोगों को पीटा जाता है क्या मिनिस्टर महोदय असल कातिल का पता लगवाने के लिये कोर्ट करायेंगे?

श्री अध्यक्ष: मैं आनरेबल मैम्बर से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इंडीविजुअल केसिज को रैफर न करें क्योंकि हर इंडीविजुअल मर्डर केस की इंफर्मे टन याद रखना मिनिस्टर साहब के लिये नामुमकिन है।

चौधरी संत कंवर: क्या होम मिनिस्टर साहब बताने का कश्ट करेंगे कि 1.4.1977 से 31.12.78 तक की अवधि में पुलिस कस्टडी में कितने मर्डर हुए?

श्री अध्यक्ष: वैसे तो आपको इस सवाल के बारे में नोटिस देना चाहिए लेकिन फिर भी मंत्री जी के पास इंफर्मे टन हो और वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री बीरेंद्र सिंह: इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

तारांकित प्र न संख्या 868

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी पीर चंद इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Area of Land Belonging to Panchayats

***871. Shri Sumer Chand Bhatt:** Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state-

(a) whether it is a fact that some land belonging to village panchayats in Ambala Block is under private occupation; and

(b) if reply to part (a) above be in affirmative, whether any action has been taken or proposed to be taken to vacate such land and restore the same to the concerned Panchayats?

विकास मंत्री(ठाकुर बीर सिंह):

(क) हां

(ख) हां। अधिकतर केसों में नाजायज काबिजों से भामलात भूमि का कब्जा छुड़वाने के लिये उप मण्डल अधिकारी (ना०) अम्बाला की कोर्ट में केस दायर कर दिये हैं। भोश केसों में भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुमेर चंद भट्ट: स्पीकर साहब, मैं वजीर साहब से यह पूछना चाहूंगा कि वे कौन-कौन से गांव हैं जिनकी जमीन पर दूसरे नाजायज आदमियों ने कब्जा किया हुआ है। जो केसिज एस०डी०एम० की अदालत में दायर किये हुए हैं उन केसिज की तफसील क्या है और उन केसिज की पोजिशन क्या है जिनमें पंचायत की जमीन नाजायज दबी हुई है और उसको खाली करवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिले में 117 पंचायतें हैं जिनमें से 23 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कि लोगों ने पंचायत की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। 23 केसिज में से 13 केसिज ऐसे हैं जो एस0डी0एम0 की अदालत में दफा 7 आफ दी विलेज कौमन लैंड एक्ट के तहत चल रहे हैं। इसके अलावा 10 केसिज ऐसे हैं जो तैयार किये जा चुके हैं और जल्दी ही वे अदालत में दायर किए जा रहे हैं।

Mr. Speaker: Good answer.

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, पंचायत के केसिज में सरपंचों को और पंचों को कई बार अदालत में पैरवी के लिये आना-जाना पड़ता है जिससे पंचायत के फाइनेंसिज पर काफी बोझ पड़ता है। क्या मंत्री महोदय इस बोझ को हल्का करने के लिये उनको फ्री ट्रेवलिंग करने के लिये अलाउ करेंगे?

ठाकुर बीर सिंह: जैसा कि बूरा साहब ने बतलाया कि पंचायतों के काफी पैसे इसी आने जाने में खर्च हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कि यह पैसा नाजायज लगता है इसके बारे में मैंने अपने डिपार्टमेंट से डिसकस किया है। डिपार्टमेंट में लीगल आफिसर मुकरर किये हुए हैं। मुझे पता लगा है कि उनकी सर्विसिज का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैंने अब यही फिगर मंगवायी है कि एक लीगल आफिसर सारे साल में कितने केसिज करते हैं और कितना काम उन लोगों के पास है। मैं यह कोर्ि । । करूंगा कि यह काम भी उनको दिया जा सके ताकि

उनके पास पूरा काम हो सके और हम उन्हीं अधिकारियों से पंचायत का काम भी करवा सकें। ऐसी मेरी प्लानिंग है। इस बारे में मैं कार्यवाही कर रहा हूँ।

कंवर राम पाल सिंह: वैसे तो यह क्वै चन अम्बाला का है लेकिन एक जनरल सी प्रॉब्लम है, इसलिये मैं क्वै चन पूछ रहा हूँ। स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूँ।

श्री अध्यक्ष: पूछ लें।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, हर ब्लॉक में कई गांवों में पंचायतों की जमीनें ऐसी हैं जिनके ऊपर लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, इनके नाजायज कब्जों को छुड़वाने के लिये जो प्रोसीजर है, वह बहुत लैथी है। कई-कई साल तक केसिज पैडिंग पड़े रहते हैं। क्या मंत्री महोदय डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर इस किस्म के केसिज को डील करने के लिये अलग से कोई अफसर लगाने की कृपा करेंगे ताकि पंचायत की जमीनें जल्दी से जल्दी छुड़वायी जा सकें?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने बूरा साहब के सवाल के जवाब में बताया है हमारे लीगल आफिसरज की सर्विसिज पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है और यह बात मेरे नोटिस में है कि लीगल आफिसरज जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लगे हुए हैं, उनका पंचायतों को कोई फायदा नहीं है। मैं पहले ही डिपार्टमेंट को यह इन्स्ट्रक्शंस दे चुका हूँ कि उनके

काम के बारे में सारी फिगरज ली जायें ताकि उनकी डिप्यूटीज और अच्छे तरीके से अलाट की जा सकें। अब इस काम का इन्जाम ठीक तरह से हो जायेगा क्योंकि अब तक इसका इंतजाम नहीं किया जा सका है।

कंवर राम पाल सिंह: लीगल आफिसरज तो वहां पर लगे हुए हैं यह बात तो ठीक है कि आप उनकी सर्विसिज यूटेलाईज करेंगे लेकिन मैं तो केसिज को डिसाईड करने के लिये पूछ रहा हूं कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टरज पर एक अफसर जो सिर्फ इन केसिज को ही डिसाईड करे, लगाने के लिये तैयार है?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब विलेज कौमन लैंड एक्ट की दफा के तहत जो प्रोसीजर बनाया गया है, वह बहुत ही सिम्पल प्रोसीजर है। यह इसीलिये सिम्पल बनाया गया है ताकि इन केसिज में जल्दी से जल्दी ऐक्टिव हो सकें। सिविल केसों में जो लम्बा प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, वह इसमें इस्तेमाल नहीं होता।

कंवर राम पाल सिंह: बहुत सी दफा यह देखने में भी आता है कि केस तो तैयार हो जाते हैं लेकिन चूंकि सरपंच या पंच उसी गांव का रहने वाला होता है, वह दूसरी पार्टी के इन्फ्ल्यूएंस में आकर गवाहों को अदालत में नहीं लाता? क्या मिनिस्टर इसके बारे में कुछ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

ठाकुर बीर सिंह: इन केसिज में तो समरी केसिज की तरह से ट्रायल होकर आर्डर करके कब्जा पंचायतों को दिलाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: इन केसिज को जुडी गियल आफिसर्ज डिसाईड करते हैं या सिविल आफिसर्ज डिसाईड करते हैं?

ठाकुर बीर सिंह: ऐसे केसिज में हमने एस0डी0एम0 को पावर्ज दे रखी है, वह इन केसिज के बारे में फैसला देता है।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, एस0डी0एम0 साहब के पास इतना काम होता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता। इसलिये मेरी गुजारि । यह है कि क्या सरकार पंचायत के एस केसिज को निपटाने के लिये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्ज पर कोई अफसर अलग से लगायेगी? ताकि नाजायज कब्जों को वापिस पंचायतों को दिलवाया जा सके।

ठाकुर बीर सिंह: इसके लिये तो ऐकान ले ही रहे हैं।

Blankets/Quilts for the Prisoners in the State

***876. Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Jails be pleased to state-

(a) whether the Government has purchased blankets/quilts for the prisoners in the State during the month of December, 1978; and

(b) if so, the total amount spent thereon?

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी भोर सिंह):

(क) हां।

(ख) 1,82,280.75 रूपये

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 1 लाख 82 हजार 280 रूपये 75 पैसे की रजाइयां और कम्बल दिसम्बर हरियाणा सरकार ने खरीदे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है कि यह राजइयां और कम्बल इंदिरा कांग्रेस की एजीटे इन के दौरान पकड़े गये लोगों को देने के लिये खरीदे गये थे और उनके जेलों से जाने के बाद अब ये रजाइयां और कम्बल सिमेट कर रख दिये गये है, अगर हां तो क्यों और क्या इन्हें दूसरे कैदियों को देने की कृपा करेंगे?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, ऐसा है कि हरियाणा की जेलों की कुल कैपेसिटी 3361 आदमियों की है। पिछले साल दिसम्बर में कांग्रेस (आई) के कुछ आदमियों ने एजीटे इन की और एकदम से 2,785 आदमी जेलों में आ गये। एक आदमी के लिये या तो तीन कम्बल या फिर एक रजाई और एक कम्बल चाहिये। किसी को भी यह पता नहीं था कि इतने आदमी एकदम से आ जायेंगे। इसलिये इतनी जल्दी इंतजाम करना पड़ा।

श्री भले राम: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस (आई) वाले सत्याग्रह करके आपकी जेलों में आये थे, क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे जो आपके कम्बल या रजाइयां ही उठा कर ले गये हों?

श्री भामोर सिंह: ऐसी कोई बात नोटिस में नहीं है।

श्री जगन नाथ: जब से जनता सरकार बनी है तब से ही जेलों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा फैसीलिटीज दी जा रही है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह इस बात को ध्यान में रखकर तो नहीं दी जा रही है क्योंकि आपको भी भायद कभी जेल जाना पड़ जाये?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

कामरेड भांकर लाल: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने भी कांग्रेस (आई) सत्याग्रह के अन्दर आदमी जेलों में गये थे, उनको 'बी' क्लास दी गयी थी या नहीं?

श्री अध्यक्ष: यह कम्बलों के बारे में सवाल है। अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो दे दें। (गोर एवं व्यवधान)

डा० बृज मोहन गुप्ता: मैं मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि इस एजीटेसन के दौरान कितने कम्बल खरीदे गये, इसी तरह से कितनी रजाइयां खरीदी गयी और किन-किन कम्पनियों से वे खरीदी गयीं?

चौधरी भोर सिंह: स्पीकर साहब, 2115 रजाइयां बनवाई गयीं और 525 कम्बल खादी ग्रामोद्योग से खरीदे गये। 2115 रजाइयों के लिये कपड़ा जेल में ही पड़ा था। सिर्फ उनके लिये रूई खरीदी गयी थी।

चौधरी लाल सिंह: मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि हम तो 19-19 महीने जेलों में रहे और हमें फटे-पुराने कम्बल दिये गये और इनको नये कम्बल क्यों दिए गये? (हंसी).....

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री फतेह चंद विज: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि खादी ग्रामोद्योग से कम्बल खरीदे गये थे, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिये बकायदा टैंडर काल किये गये थे, या वैसे ही खरीद लिये गये?

चौधरी भोर सिंह: उनके तो रेट्स फिक्सड होते हैं।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब जब सत्याग्रही जेल से वापिस आ गए थे तो उन्होंने नई रजाइयां और नये कम्बल अब स्टोर में रख दिये हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन कैदियों के पास फटे हुए कम्बल भी नहीं हैं क्या उनको ये नई रजाई और नए कम्बल दिए जायेंगे?

चौधरी भोर सिंह: जहां जरूरत पड़ेगी वहां जरूर दी जाएंगी।

Livery to class IV Employees

***885. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Government has sanctioned winter uniform with jersey to class IV employees; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, whether it is a fact that this concession has not been extended to class IV employees of Irrigation Department; if so, the reasons therefor?

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा):

(क) जी हां।

(ख) प्र न के 'ए' भाग में उल्लेखित सुविधा सिंचाई विभाग सहित राज्य सरकार के सभी विभागों के नियमित श्रेणी चार कर्मचारियों के लिये भी स्वीकृत है।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सभी विभागों के श्रेणी चार कर्मचारियों के लिये विन्टर यूनीफार्म स्वीकृत है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को अभी तक वर्दी क्यों नहीं मिली है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, नियम के अनुसार, लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों को मिलनी चाहिए लेकिन सिंचाई विभाग के कुछ कर्मचारियों को अभी नहीं मिली है। संबंधित अफसरों से यह पूछा गया है कि किस कारण से श्रेणी चार के कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दी नहीं दी गई है।

Inadequate number of buses in sub depot Jhajjar

***1002. Captain Mange Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that a fleet of 33 buses provided to the sub-depot at Jhajjar is inadequate to meet the increasing requirements of the travelling public; if so, the steps taken or proposed to be taken to augment it; and

(b) whether the deteriorated condition of the buses which are plying in rural areas of the Jhajjar Assembly constituency has been improved, windows repaired and window panes replaced by new ones, if not, the reasons therefor together with the time by which these are likely to be repaired/replaced?

मुख्य संसदीय सचिव(श्री सुरेंद्र सिंह ओजला):

(क) झज्जर डिपो में 5 बसें पहले ही भेजी गई है तथा कुल बसें 38 हो गई है जो कि वर्तमान यातायात आवकता को पूरी करने के लिये काफी है।

(ख) सभी बसों की मरम्मत की जा चुकी है और इनमें विंडो पेन लगाए गए हैं। केवल दो बसें वर्क टाप में रोकੀ हुई हैं जो कि भीघ ही मरम्मत के बाद सड़कों पर चला दी जायेगी।

कैप्टन मांगे राम: स्पीकर साहब, चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने बताया है कि पांच और बसें झज्जर डिपों को भेज दी गई है और कुद बसों की मरम्मत कर दी गई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झज्जर सब-डिपों की आज भी हालत इतनी खराब है कि मेरे ख्याल से किसी डिपो की भी हालत इतनी खराब नहीं होगी और आज भी इतनी ओवर-लोडिंग चलती है कि जनता काफी परे टान हैं। वहां पर जब तक पचास बसें नहीं होंगी समस्या हल नहीं होगी। क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां पर बसों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, इस साल रोहतक डिपों में 84 नई बसें भेज दी है।

चौधरी सरदार खां: स्पीकर साहब, गुडगांव और पलवल डिपों की भी हालत काफी खराब हैं इससे पहले चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने बताया था कि वहां पर भी नई बसें भेज दी है लेकिन हालत ज्यों की त्यों खराब है। क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि पलवल डिपों के लिये वे क्या कर रहे हैं?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, हाउस के अन्दर जो भी अ यारेंस दी गई है वह बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि 84 बसें रोहतक डिपों को भेजी है वह बिल्कुल ठीक है। अगर आनरेबल मैम्बर साहिबान सब डिपोज के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं कल जवाब दे सकता हूँ लेकिन कोई भाक वाली बात नहीं है।

श्री ओम प्रकाश: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक डिपों को जो 84 बसें भेजी है उनमें से सोनीपत बस-डिपों को कितनी बसें दी गई है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: रिप्लेसमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बस अपनी आठ साल की उमर पूरी कर लेती है और अगर एक डिपों में पचास बसें है पूरी मिली हुई है और उनकी रिप्लेसमेंट की जानी है तो जैसे-जैसे कोटा हरेक डिपों का बनता है उसके अनुसार बसें दी जायेगी।

श्री भागी राम: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि सिरसा डिपों को कितनी बसें दी गई है।

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, यह इंफर्मेण्डान इस वक्त मेरे पास नहीं है अगर सैपरेट नोटिस दिया जायेगा तो सूचना दे दी जाएगी। मैं सदन की इंफर्मेण्डान के लिये बताना

चाहता हूँ कि इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में हमने पांच सौ नई बसें बनवा कर सारे हरियाणा में डाल दी है।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट जींद के डिपो की भी हालत बहुत खराब है। क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि जींद की तरफ भी सरकार का कोई ध्यान है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, यह सपलीमेंटरी मेन क्वे चन से संबंधित नहीं है, यह सैपरेट क्वे चन है। तीन चार रोज पहले मैंने बताया था कि वहां का डिपो लौस में चल रहा है।

चौधरी देस राज: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि बसों में कितनी ओवरलोडिंग करने का प्रोवीजन है?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजला: स्पीकर साहब, यह प्रोवीजन की बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने ओवरलोडिंग का प्रोवीजन किया हुआ है। असल बात तो यह है कि जितनी ओवरलोडिंग होगी उतना ही डिपार्टमेंट को फायदा होगा।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Thirty Beds Hospital in District Sirsa

***1046. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgarade the Primary Health Centre to thirty beds Hospital in district Sirsa; and

(b) if so, the name of the Primary Health Centre which is likely to be upgraded?

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा):

(क) अभी नहीं

(ख) प्र न नहीं उठता।

Roads in Kalanaur Constituency

***1009. Shri Jai Narain:** Will the Minsiter for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new roads in Kalanaur Assembly constituency of district Rohtak during the current financial year, if so, the names of roads which are likely to be completed before 28th February, 1979?

लोक निर्माण मंत्री(श्री लछमन सिंह):

(1) हां जी।

(2) प्रस्तावित सड़कों में से कोई भी सड़क का निर्माण 28.2.79 तक पूरा नहीं हो सकता है।

**Travelling Allowances to the Candidates
Belonging to Scheduled Castes**

***1075. Chaudhri Gaya Lal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether the Government has issued any instructions to the effect that the candidates belonging to the Scheduled Castes who are called for interview for appointments to the posts in various Government Departments should be allowed the travelling Allowance for the journey performed by them in this connection in the State; if so, whether these instructions are being followed by the interviewing Department/Agencies; and

(b) if not, the time by which these instructions are likely to be followed?

Revenue Minister (Shri Preet Singh):

(a) In composite Punjab instructions for allowing the Travelling Allowance to Scheduled Castes candidates who are called for interview for class III and VI posts were issued by the Government vide letter No. 1090-FRI-61/1504, dated 9/15-2-1961 and 1380-FRI(1)-62/1415, dated 22-2-1962 and these are still in vogue. Violation of the above instructions has not come to notice.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

Cases Embezzlement

***1086. Shri Fathe Chand Vij:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) the number of cases of embezzlement alongwith the total amount embezzled in the Cooperative Department during the period from 1-4-1977 to 31-12-1978; and

(b) the number of cases referred in part (a) above detected and the number among them of those taken to the courts by the Department during the said period seapratly?

**Cooperation and Dairy Development
Minister**(Chaudhri Bhajan Lal):

(a) & (b) 290 cases of embezzlement involving an amount of Rs. 35.60 lakhs were detected during the period from 1-4-77 to 31-12-78. Out of these cases, 21 cases involving an amount of Rs. 2.76 lakhs have been taken to courts.

Relief to the flood Affected People

***946. Shri Sumer Chand Bhatt:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) district-wise number of houses collapsed, partially and wholly, due to floods in the year 1978;

(b) the criteria fixed for determining the eligiblility of persons to whom relief has been given;

(c) the extent of relief given to each family and whether there has been uniformity in this regard throughout the State; and

(d) the district-wise number of families to whom the relief has been given together with the amount paid?

Revenue Minister(Shri Preet Singh):

(a & d) A statement is laid on the Table of the House.

(b) The general criteria fixed for determining eligibility of house-owners for giving relief is that he should not have been left with any habitable accomodation.

(c) Relief upto Rs. 300/- has been given to each house owner.

STATEMENT

Statement showing the District-wise number of houses damaged partially and wholly and the number of families to whom relief has been given together with the amount paid.

Sr. No.	District	Number of partially damaged houses	Number of whally damaged houses	Number of families to whom relief was given	Amount of grant given
1.	Hissar	2,397	57	57	16,900
2.	Bhiwani	3,924	1,732	3,626	3,45,000
3.	Narnaul	2,710	3,572	957	2,81,200
4.	Rohtak	1,106	1,989	1,667	5,00,000

5.	Gurgaon	8,546	6,474	8,132	10,00,000
6.	Sirsa	6	117	123	36,300
7.	Sonepat	4,057	4,347	3,827	10,99,000
8.	Kurukshetra	1,853	1,901	931	2,79,300
9.	Karnal	1,757	17,196	4,025	12,07,500
10.	Jind	780	678	1,048	2,95,100
11.	Ambala	18,133	3,647	3,801	11,24,400
	Total	45,269	41,710	28,194	61,85,600

Haryana Roadway Depot at Rohtak

***857. Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Chief Minister pleased to state-

(a) whether the Haryana depot at Rohtak is running in loss or profit at present;

(b) the total number of buses which have been added so far or are likely to be added during the current financial year in the above said Depot;

(c) the total number of buses whose windows-panes were replaced during the period as referred to in part (b) above; and

(d) whether the Govt. has taken any steps to remove the rubbish from the aforesaid Depot area?

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल):

(क) इस समय हरियाणा राज्य परिवहन का रोहतक डिपो लाभ पर चल रहा है।

(ख) इस समय तक 49 पुरानी बसों को नई बसों में बदल दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इस डिपो में 35 और नई बसें मार्ग पर डाल दी जायेंगी।

(ग) 60

(घ) हां

Recruitment of ad-hoc employees in the State

***1093. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that more than 1500 employees in the State have been recruited on ad-hoc basis;

(b) whether it is also a fact that a great number of employees referred to in part (a) above have put in more than three years service;

(c) if reply to parts(a) and (b) above be in the affirmative, whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of those employees who have put in specific number of years of service; and

(d) if reply to part (c) above be in the negative, the steps, if any, taken by the Government to ensure security of service to such employees who have been recruited on adhoc basis?

Chief Minister (Ch. Devi Lal):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) No, except that it has been decided by the Education Department to regularise the services of 11,170 stipendary teachers/masters/mistresses.

(d) Security of service of adhoc employees cannot be ensured because they are appointed in stop-gap arrangement and are to be replaced by the candidates to be selected by the Subordinate Service Selection Board. However, in order to enable them to compete in future selections by the Board, instructions were issued on 15-9-1977 to give them relaxation in age to the extent of their ad-hoc service.

Constituency-wise disbursement of funds for providing drinking water

***898. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state the amount given in the shape of grant or loan to Haryana by the World Health Organisation for providing drinking water during the period from the 4th July, 1977 to 30th September, 1978, togetherwith the amount disbursed constituency-wise for the water supply scheme in the area of Haryana?

लोक निर्माण मंत्री(श्री लछमन सिंह): भून्य

Water Supply Scheme in the State

***880. Shri Shamsheer Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state the constituency-wise number of drinking water supply schemes sanctioned and executed during the current financial year?

Public Works Minister(Shri Lachhman Singh): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

Sr. No.	Name of Constituency	Number of schemes sanctioned and executed
1.	Adampur	1
2.	Badli	5
3.	Bahadurgarh	3
4.	Barwala	1
5.	Baroda	1
6.	Bawani Khera	1
7.	Badhra	4
8.	Bhattu Kalan	1
9.	Beri	2

10.	Chhachhrauli	1
11.	Dadri	2
12.	Dabra Kalan	2
13.	Ellnabad	4
14.	Fatehabad	1
15.	Ferozpur Jhirka	1
16.	Gohana	1
17.	Gurgaon	2
18.	Hansi	2
19.	Hathin	1
20.	Kalanaur	2
21.	Kalka	18
22.	Loharu	5
23.	Meham	1
24.	Mudhal	1
25.	Narnaul	1
26.	Narnaund	2
27.	Naultha	1
28.	Nuh	1

29.	Rajond	2
30.	Rewari	2
31.	Safidon	4
32.	Salahawas	1
33.	Sirsa	1
34.	Taoru	1
35.	Yamuna Nagar	1
		80

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Civil Hospital at Hathin

236. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Civil Hospital at Hathin; and

(b) if so, the time by which the Hospital as referred to in part (a) above is likely to be constructed?

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा):

(ए) नहीं ।

(बी) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Amount for Chaupals

237. Swami Adityavesh: Will the Minister for Revenue be pleased to state the constituency-wise number of chapupls for which amount has been given during the period from 1st July, 1978 to 31st October, 1978 together-with the amount in each case?

Revenue Minister(Shri Preet Singh):

Grants for construction of Chaupals for Harijans are not given constituency-wise. Therefore, the requisite information cannot be supplied.

Distilleries and Breweries

238. Swami Adityavesh: Will the Minister for Excise and taxation be pleased to state the total number of distilleries and breweries in the State where country liquor, beer and Indian made foreign liquor is manufactured togetherwith the names of places where these are located?

Excise and Taxation Minister(Chaudhri Sher Singh):

(a) Country liqour and Indian made foreign liquor is manufactured by two distillereis in the State viz (i) Haryana Distillery at Yamuna Nagar and (ii) Panipat Cooperative Distillery at Panipat.

(b) Beer is manufactured by two breweries in the State viz(i) Haryana Breweries Ltd. at Murthal (Sonapat) and (ii) Indo-Lowen Brau Breweries Ltd. at Faridabad.

239. Swami Adityavesh: Will the Minister for Excise and Taxation be please to state-

(a) the names of ingredients which are used for the distillation of the country liquor and Indian made foreign liquor in the State; and

(b) the total quantity of the aforesaid each ingredient used for distillation in a year?

Excise and Taxation Minister(Chaudhri Sher Singh)%

(a) (i) The ingredients which are used for the distillation of the country liquor by Distilleries in Haryana State are as follows:-

Essences/Flavour used

Haryana Distillery, Yamuna Nagar		Panipat Co-operative Distillery, Panipat	
Sr. No.	Name	Sr. No.	Name
1.	Spice Triphla	1.	Aniseed
2.	Spice Mulathi	2.	Raspherry
3.	Spice Chandan	3.	Orange

4.	Spice Orange peel	4.	Pine-apple
5.	Spice Khas	5.	Amber
6.	Spice Illachi Chhoti	6.	Green Rose
7.	Spice Tej Patta	7.	Vanilla
8.	Spice Dalchini	8.	Falsa
9.	Spice Phool Gulab	9.	Cardamom
10.	Spice Anjeer	10.	Cherry Cider
11.	Spice Javitri	11.	Safron
12.	Spice Brahmi Booti	12.	Atlas Special
13.	Spice Moosli white	13.	Kesher Kasturi
14.	Spice Jaiphal	14.	Mix fruit
15.	Spice Banafshan	15.	Khas-essence
		16.	Malta essence
		Spice used	
		1	Anwala
		2	Behra
		3	Chal Chebilla
		4	Chhoti Illachi
		5	Bari Illachi

		6	Harrar
		7	Khas Khas
		8	Mulathi
		9	Orange peel
		10	Chandan Chura
		11	Taj Patta
Indian Made Foreign Spirit			
Hayana Distillery, Yamuna Nagar		Panipat Cooperative Distillery, Panipat	
There are no ingredients for the distillation of Indian made Foreign Liquor		1	Whisky
		2	Rum essences
		3	Gin essence
		4	Peat Flavour
		5	brandy essence
		6	Grape Flavour

Sugar

(b) Total quantity of the aforesaid each ingredient used for distillation in a year-

Essences/Flavour used

Haryana Distillery, Yamuna Nagar			Panipat Co-operative Distillery, Panipat		
Sr No.	Name	Quantity in Kilograms	Sr. No.	Name	Quantity in litres
1	2	3	4	5	6
1.	Spice Triphla	1875.750	1.	Aniseed	0.50
2.	Spice Mulathi	1570.300	2.	Raspherry	95.00
3.	Spice Chandan	1115.500	3.	Orange	153.50
4.	Spice Orange peel	1906.500	4.	Pine-apple	70.00
5.	Spice Khas	1723.500	5.	Amber	51.50
6.	Spice Illachi Chhoti	55.250	6.	Green Rose	51.50
7.	Spice Tej Patta	76.300	7.	Vanilla	33.00
8.	Spice Dalchini	22.100	8.	Falsa	52.50

9.	Spice Phool Gulab	69.000	9.	Cardamom	208.00
10.	Spice Anjeer	43.600	10.	Cherry Cider	43.00
11.	Spice Javitri	22.100	11.	Safron	48.00
12.	Spice Brahmi Booti	49.000	12.	Atlas Special	76.50
13.	Spice Moosli white	43.800	13.	Kesher Kasturi	13.50
14.	Spice Jaiphal	22.100	14.	Mix fruit	2.50
15.	Spice Banafshan	46.300	15.	Khas-essence	7.00
			16.	Malta essence	38.00
		8641.100			941.400
			Spice used		
			1	Anwala	1042.800
			2	Behra	814.100

			3	Chal Chebill a	30.000
			4	Chhoti Illachi	46.670
			5	Bari Illachi	342.300
			6	Harrar	1387.20 0
			7	Khas Khas	1042.00
			8	Mulathi	778.600
			9	Orange peel	741.00
			10	Chanda n Chura	931.100
			11	Taj Patta	90.500
					7246.27 0
Indian Made Foreign Spirit					
Hayana Distillery, Yamuna			Panipat Cooperative		

Nagar			Distillery, Panipat(in liters)		
There are no ingredients for the distillation of Indian made Foreign Liquor			1	Whisky	126.00
			2	Rum essences	478.50
			3	Gin essence	51.50
			4	Peat Flavour	5.00
			5	brandy essence	12.50
			6	Grape Flavour	6.50
					680.00

Sugar 187 bags or 18700kilograms.

ध्यानाकर्षण सूचना-

कृशि उपज की कीमतों के बहुत ज्यादा गिरने संबंधी

(15.00 बजे) श्री अध्यक्ष: मुझे श्री हर स्वरूप बूरा, एम0एल0ए0 से एग्रीकल्चर प्रोडयूस की कीमत और का तकारों को रेमूनरेटिव प्राइस का दिलाना यकीनी बनाने के बारे में एक

ध्यान दिलाओं नोटिस मिला है और उसे मंजूर किया जाता है। आनरेबल मैम्बर अपना प्रस्ताव पढ़ दें और एग््रीकल्चर मिनिस्टर साहब अगर जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं और यदि टाईम मांगना चाहते हैं तो टाईम मांग सकते हैं।

स्वामी आदित्यवे I: स्पीकर साहब, मैं अपने 28 तारीख के प्रस्ताव की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें मैंने कहा था कि आगरा कैनल और उसकी माइनर्ज के कारण तीस गांवों की फसल तबाह हो गई है और पचास लाख का नुकसान हुआ है। तहसील नुह और पलवल तहसील के गांवों में सब से ज्यादा नुकसान हुआ है लेकिन जो जवाब मुझे भेजा है उसमें लिखा है कि यह मामला आव यक नहीं है और पब्लिक हित का नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि आज भी नागल जाट, नाटोली, बच्चीपुर, अरौली और कोट के चारों तरफ पानी भरा हुआ है.....

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, इस प्रस्ताव के बारे में फैसला हो चुका है और इस पर अब कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। इस बारे में बात करने के लिये आप मेरे चैम्बर में आ जाएं, मैं आपको समझा दूंगा।

श्री भामोर सिंह: स्पीकर साहब, आज ही मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दिया था जिसमें मैंने कहा है कि जब सेंट्रल बजट अभी पे ही हुआ है और अभी पास भी नहीं हुआ

है उसके बावजूद हर कंज्यूमर गुड्ज चाहे वह साबुन है, टुथ पेस्ट है और चाहे दूसरी कोई चीज है, हर चीज की कीमत बहुत बढ़ गई है.....

श्री अध्यक्ष: आपका मो एन सैकेटरी साहब को मिल गया है। It is under examination. I will give my decision on that motion today. The hon. member Chaudhri Har Swaroop Bura may please read out his call attention motion.

चौधरी हर स्वरूप बूरा: मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कृषि उपज की कीमतें इतनी गिर गई है कि का तकारों पर बुरी तरह से तथा अत्याधिक प्रभाव पड़ा है। कृषि उपज में और गिरावट को रोकने के लिए तथा अर्थ-व्यवस्था में असन्तुलन को ठीक करने के लिए तथा किसानों को उनका हक दिलाने के लिये यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि वे ऐसे पग उठाए जिन से किसानों के हितों की, जिनकी फसलों अर्थात् गन्ना, कपास, आलु आदि की हालत दयनीय है, सुरक्षा तथा बचाव हो। सरकार को इन उत्पादकों की सहायता पर आना चाहिए।

कृषि उपज तथा निर्मित माल के मूल्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। जब कि एक तरफ तो कृषि उपज के भाव गिरे रहे हैं तो दूसरी तरफ, औद्योगिक माल के मूल्य बढ़ रहे हैं। यह सदन राज्य सरकार से चाहता है कि वह इस असन्तुलन को

रोकने के लिए प्रभावी पग उठाने के लिए केंद्रीय सरकार से निवेदन करे। मूल्य लगभग सारा वर्ष एक समान रहना चाहिए।

कृषि उपज के भाव आर्थिक स्तर तथा उपज परिव्यय से भी नीचे गिर गए हैं तथा उत्पादकों को बहुत भारी हानि हो रही है। इससे पहले इतनी गिरावट कभी नहीं हुई थी, किसान प्रायः भाव के रहम पर हैं। बहुत से किसान अपनी कपास 225/-रूपए से लेकर 275/- रूपये प्रति किंवटल बेच रहे हैं, जबकि गत वर्ष इसका भाव 400/-रूपए से लेकर 525/-रूपए प्रति किंवटल था। आलु संघीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 45/-रूपए से लेकर 50/-रूपए तक के सहायक मूल्य की बजाय 20/-रूपए से लेकर 25/-रूपए के दर पर बिक रहे हैं। श्रम परिव्यय बिक्री मूल्य से अधिक है। मुख्यतया इससे छोटे किसान पीड़ित हैं। उत्पादकों द्वारा घबराहट में विक्रय को रोकने के लिये राज्य सरकार को अपनी मीनरी को खुले बाजार में आ कर बेचने के लिए पैदा की गई उपज को सहायक मूल्य पर खरीदने तथा उपार्जित करने के लिए तेज करना चाहिए।

हम यह जानते हैं कि आगामी खेती का तात्पर्य है मूल्यों में गिरावट तथा कम मुनाफा। परन्तु यह इसका परिणाम नहीं है। लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति वार्षिक मूल्यों की अस्थिरता, विभिन्नता तथा उतार-चढ़ाव आदि पर निर्भर करती है तथा कृषि अन्तर्धारित (इन पुटस) तथा निकासी (आउट पुटस) के मूल्यों में भारी असंतुलन पर निर्भर करती है।

गन्ना उत्पादक गन्ने के वर्तमान मूल्य से इतने अप्रसन्न है कि वह गन्ने की फसलों को पैदा करने में घबराहट महसूस करता है। मिल क्षेत्रों के बाहर गन्ना उत्पादकों की हालत बहुत ही खराब हो रही है। वे गुड़ बनाने पर मजबूर हो जाते हैं जो कि साठ रूपए से लेकर अस्सी रूपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है तथा जो पिछले एक दशक में बेमिसाल न्यूनतम मूल्य है।

राज्य सरकार को कृषि उपज के भावों में वर्तमान गिरावट से उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबला करने के लिए तरीके सुझाने के लिए किसानों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों तथा प्रशासकों की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करनी चाहिए।

देश में गेहूँ की अत्याधिक फसल की ओर बढ़ रहा है, तथा यदि समय पर पग न उठाए गए तो इसे बेचने में भी गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब किसान अच्छा मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं।

हमें न केवल कृषि अन्तर्धारित (इन-पुटस) के मूल्य ही नीचे लाने होंगे, परन्तु का त्कारों को लाभकारी मूल्य दिलाने भी सुनिश्चित करना होगा। इसकी अनुपस्थिति में अगले वर्ष में कृषि उपज में बहुत भारी कमी होने का भय है। व्यापारियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सहायक मूल्य से कम मूल्य किसानों को नहीं देना चाहिए।

कृषि मंत्री(बिग्रेडियर रण सिंह): स्पीकर साहब, इसका जवाब आठ मार्च को दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष: 8 मार्च, 1979 को एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब इसका जवाब देंगे।

श्री फतेह चंद विज: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटेंशन नोटिस दिया था जोकि पुलों से संबंधित था और यह पुल हरियाणा को यू०पी० से मिलाते हैं, लेकिन मुझे इस के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आपका जो काल अटेंशन नोटिस है उसका संबंध यू०पी० सरकार से है, आप मेरे चैम्बर में आ जाइये तो आपको वहां इसकी पोजीशन बता दूंगा।

श्री फतेह चंद विज: ठीक है जी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now, there will be resumption of discussion on the Governor's Address. गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर जिसका अनुष्ठान होने से पहले मैं एक दो प्वायंट्स क्लेरीफाई करना चाहता हूं। 2 मार्च, 1979 को जब गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर जिसका अनुष्ठान हुआ तो उस वक्त चौधरी खुरीद अहमद, जिन्होंने गवर्नर साहब को धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया, कोई 41 मिनट तक बोले। श्रीमती सुशमा स्वराज 24 मिनट के लिये बोली।

स्वामी अग्निवे 1 जी 25 मिनट के लिये बोले और राव बीरेंद्र सिंह 40 मिनट के लिए बोले थे। आज हमारे पास तकरीबन 3 घंटे डिसकान के लिये है और कल भी तीन घंटे डिसकान के लिये है। यानि 375 मिनट का टोटल समय हमारे पास डिसकान के लिये है। 375 मिनटस में से 75 मिनट वोटिंग और गवर्नमेंट के जवाब के लिये रखे जाएंगे, इसलिये हमारे पास 300 मिनट का समय है। मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर साहिबान इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे अगर हम हरेक मैम्बर साहब को बोलने का समय तकरीबन 15 मिनट रखें तो 20 मैम्बर इस डिसकान में हिस्सा ले सकते हैं। Therefore, vide Rule 24, I would like to take the sense of the House whether 15 मिनट का समय रीजनेबल रहेगा या कि इस से ज्यादा हो? अगर इस टाइम में कोई कमी या बढ़ती करनी हो तो आप साहिबान बता दें।

आवाजें: ठीक है जी। 15 मिनट का समय हरेक मैम्बर के लिये ठीक रहेगा।

Mr. Speaker: Alright. Thank you.

श्री सुरेंद्र सिंह(तो 11म): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सदन में सरकारी बैंचिज की तरफ से काफी विस्तार से सरकार की उपलब्धियों और आने वाले सालों में सरकार की नीतियों के ऊपर रोनी डाली गई है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर ऐड्रेस को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि चौधरी देवीलाल जी ने गरीबों को और किसानों को ज्यादा से

ज्यादा रियायतें देने की कोशिश की है (तालियां) जो बात सच उसको तो कहना चाहिए। प्राइवेट कालेजों के 75 परसेंट डेफीसिट को पूरा करना, खिलाड़ियों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देना और बाढ़ पीड़ित लोगों को कर्जा देना और लगान और तकावी को माफ करना, ट्रेक्टर से टोकन टैक्स हटा लेना और छोटे समय के लिये दिये गये कर्जों पर से ब्याज की दर कम से कम कर देना, ये सब बातें काबिले तारीफ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि विद्यार्थियों को बसों में कुछ कन्सै इंज भी दिये गए है, बल्कि इससे और ज्यादा दिये जाने चाहिए। यह सारक कन्सै इंज और सबसिडी, रिलीफ जो किसानों और गरीब लोगों को दिये गये है, यह सारी राशि कोई लगभग सवा सात करोड़ है। इस के इलावा सवा छः करोड़ रुपये जमींदारों को मालिया माफी और बिजली के फ्लैट रेट्स पर कन्सै इंज के रूप में दिए गए है लेकिन अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल जी जोकि किसानों के बड़े हितैशी है, वे अपने दिल और दिमाग पर हाथ रख कर यह जरूर कहते होंगे कि अभी तक वे किसानों का उतना भला नहीं कर पाये है, जितना होना चाहिए क्योंकि जनता पार्टी में चाहे वह केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकारें है उनके अन्दर एक ऐसा घटक मौजूद है जो किसान को खुलाहाल नहीं देख सकता।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल जी इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि उनकी सरकार बनने से पहले, या केंद्र

सरकार या जनता की सरकार बनने से पहले किसानों को अपनी फसल का भाव किस कदर मिलता था। अभी अभी मेरे आनरेबल मैम्बर श्री बूरा साहब ने भी यहां पर इस संबंध में एक काल अटें इन मो इन का जिक्र किया। मैं इस वक्त इस सदन के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि जनता सरकार बनने से पहले किसान को जो भाव मिलते थे और आज आपकी सरकार में किसान को उसकी फसल के जो भाव मिलते हैं उसमें किसान को कितना नुकसान हुआ है और आपकी सरकार ने जो कंसै इंज किसान को दिया है, उस भाव के मुकाबले में असल नुकसान किसान का है या कि सरकार का। अध्यक्ष महोदय, इन की सरकार आने से पहले गन्ने का भाव 14 रूपये क्विंटल का था और गुड़ 80,90 और 100 रूपये क्विंटल तक बिका है।

अध्यक्ष महोदय, एक हजार रूपया एक टन गुड़ के पीछे घाटा पड़ा है। इसी तरह से कपास चार सौ रूपए से लेकर सवा पांच सौ रूपये तक बिकी है (विघ्न) जिस पर सौ रूपये से लेकर दो सौ रूपए प्रति क्विंटल घाटा हुआ है (विघ्न)

आवाजें: यह सब कुछ आपकी सरकार में होता था (विघ्न एवं भाोर)

श्री सुरेंद्र सिंह: उस सरकार में आप में से भी बहुत से लोग भागीदार थे। मैं उस सरकार में भामिल नहीं था।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि उस पार्टी की सरकार में आप में से बहुत से लोग हिस्सा रखते थे। तो मैं आपके द्वारा उनको यह बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी कांग्रेस में नहीं रहे बल्कि हमने तो कांग्रेस के राज में जेल काटी है।

श्री अध्यक्ष: यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सुरेंद्र सिंह: इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, सौ रूपए से लेकर डेढ़ सौ रूपए प्रति किंवटल सरसों में भी किसानों को नुकसान हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा कि जनता पार्टी की सरकार में एक इस किस्म का घटक मौजूद है जो किसानों को खुलाहाल नहीं बना सकता। भायद मेरे भाई इस बात से नाराज हो लेकिन मेरे पास इसका सबूत है। अध्यक्ष महोदय, जब किसान अपने खेत में कपास तैयार करता है तो हमारी केंद्रीय सरकार यह फैसला करती है कि हम पोलिस्टर इम्पोर्ट करेंगे। आम कपड़े को तो छोड़िये कहते हैं खादी में भी पोलिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। पिछले साल सारे हिन्दुस्तान में 70 लाख कपास की गांठें पैदा हुईं और एक गांठ में 170 किलो कपास होती है। आप इससे अंदाजा लगायें कि किसानों को कितना घाटा हुआ और अगर इसी तरह से चलता रहा तो किसान किस प्रकार से बच सकता है? इसी तरह से सरसों का भाव भी डेढ़ सौ रूपये किंवटल घटा दिया गया है। जब किसानों ने मेहनत करके सरसों पैदा की तो केंद्रीय सरकार ने यह फैसला कर लिया कि हम लाखों टन ऐडिबल आयल इम्पोर्ट

करेंगे। तो इस तरीके से किसान की प्रोडक्ट इन कहां जाएगी (विधन) हमारे जनसंघ के भाई भायद बुरा मनाएंगे. (गोर)

आवाजें: यहां पर जनसंघ का नाम की कोई पार्टी नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती डा० कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी माफत सदन में बताना चाहती हूं कि यहां पर जनसंघ नाम की कोई पार्टी नहीं है, यहां पर तो जनता पार्टी है। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो वह जनता पार्टी के नाम से करें।

श्री सुरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि.....
.....

Mr. Speaker: I would request the hon. Member to withdraw the word 'Jan Sangh'. There is no 'Jan Sangh' as the Health Minister has stated.

Shri Surrender Singh: I do according to your wishes. But the situation remains the same.

श्री भाम गोर सिंह: अध्यक्ष महोदय अगर यहां पर जनसंघ नाम की कोई पार्टी नहीं है तो किसी को इस बात का नोटिस ही नहीं लेना चाहिए था। यह तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। (हंसी)

Mr. Speaker: That is no point. I would request the hon. Member not to mention 'Jan Sangh' as there is no 'Jan Sangh' now.

श्री सुरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय मैंने घटका नाम इसलिये जिया कयोंकि इन्होंने नाम बताने की मांग की थी। आज मैं चौधरी देवीलाल जी से मांग करता हूं कयोंकि आज तक इन्होंने कितनी सरकारें अपने हाथ से बनाई और कितनी ही अपने हाथ से तोड़ी लेकिन आज जो सरकार है उसके ये खुद मालिक है.....

.....

मुख्य मंत्री(चौधरी देवीलाल): क्या इसे भी तोड़ दें।
(हंसी)

श्री सुरेंद्र सिंह: चौधरी साहब, इस कुर्सी पर बैठना बहुत मुश्किल होता है, यह कुर्सी जल्दी से टिकने नहीं देती। खैर, मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारि । करूंगा कि उनको याद होगा जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने अपने खास दोस्त श्री प्रकाश सिंह बादल के साथ करनाल में सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह के लिये इनकी मांग भी जायज थी। मांग यह थी कि गेहूँ का भाव 150/-रुपए प्रति क्विंटल मिले। आज चौधरी देवी लाल जी की सरकार हरियाणा में है और श्री प्रकाश सिंह बादल की सरकार पड़ौस के राज्य पंजाब में है। दोनों प्रांत फूडग्रेन्ज के लिहाज से सरप्लस है और ये केंद्रीय सरकार तथा दूसरी प्रांतों को अनाज देते हैं। क्या चौधरी देवी लाल जी इस बात का फैसला करेंगे कि किसान अपनी फसल को दो साल के लिये नहीं तो एक साल के लिये अपने घर में रख सकें और इस दौरान किसान को अपना गुजारा करने के लिये बच्चों की पढ़ाई के लिये

और कपड़ा वगैरह खरीदने के लिये इन्ट्रैस्ट फ्री लोन दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो बिड़ला और टाटा को अनाज खरीदने के लिये खुद किसान के खेतों में आना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय इसके बावजूद भी अगर किसान की फसल के भाव नहीं बढ़ते तो मैं चौधरी देवी लाल और बादल साहब से गुजारि । करूंगा कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर दें, हम भी इस काम में उनका साथ देंगे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्ष के क्षेत्र पर आता हूँ। आज यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स में बड़ा अन-रैस्ट है। खास कर रोहतक वि विद्यालय में बड़ा अन-रैस्ट है। रोहतक यूनिवर्सिटी तो अभी रिकगनाइज्ड भी नहीं है। कल को एक लड़का अगर यहां से ग्रेजुएशन करके बाहर जाता है तो उसको और कहीं दाखला भी नहीं मिल सकेगा। इसके बाद एक बात और है कि हमारे सरकारी बैंचिज पर बैठे भाई अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि पुरान मुख्य मंत्री के समय में तमाम पैसा भिवानी में कितना पैसा लगा और सारे हरियाणा में कितना पैसा लगा। आज मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि आप चंडीगढ़ से निकल कर दिल्ली जाए, रेवाड़ी जाएं या कहीं भी जाएं तो आपको सड़क के किनारे पर ही पिछली सरकार के काम नजर आ जाएंगे। चौधरी लाल सिंह जी जो बार-बार कहते हैं.....

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह जो सड़कों के ऊपर टीन के खोखों के ऊपर रंग करके चाय पिला रहे थे यह क्या चीज है.....

Mr. Speaker: This is no point of Order. I would request the hon. Member not to waste the time of the House like this, otherwise I will deduct that much time when he speaks.

श्री सुरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पिछली सरकार द्वारा किये हुए कार्य बता रहा था। आप जवाहर लाल नेहरू कैनल को देखें। इरीगे इन के लिये यह सब से बड़ा प्रोजैक्ट है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भिवानी जिला बनने से पहले इसका एक भी गांव इस प्रोजैक्ट में भामिल नहीं था और बाद में यह प्रोवीजन की गई कि जो 20-25 गांव सतनाली के इलाके के हैं उनको इसमें ऐड कर लिया जाए क्योंकि यह स्कीम मैक्सिमम इलाके को इरीगेट करेगी। इसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं जैसे बड़खल लेक है, चकवर्ती लेक है। इसलिये आपका यह फर्ज है कि पिछली सरकार के टाई में जो अच्छे काम हुए हैं उनको आप अच्छा कहें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब सरकारी बेंचिज की तरफ से चौधरी लाल सिंह जी या दूसरे सदस्य कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर तो भोर पैदा हो गया या देवता पैदा हो गया। (विधन) सुशमा बहिन जी ने भी कल अपनी तकरीर में एक बात कही थी कि अगर किसी प्रांत का इतिहास बनता है तो हम लिखने को तो लिख देते हैं कि हमारे प्रांत इतनी

सड़कें बनी इतनी बिजली लगी और पता नहीं क्या-क्या हुआ लेकिन वास्तव में इतना काम नहीं होता। फिर भी यह बात दुरुस्त है कि जो इन्सान कुर्सी पर बैठता है उसको इतिहास में बहुत बड़ी जगह मिलती है। और देखा जाता है कि अगर उसने सारे प्रान्त को बराबर समझ कर काम किया है तो इतिहास में उसको पूरा स्थान मिलता है। अध्यक्ष महोदय अब मैं भिवानी की चर्चा करूंगा। भिवानी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है और वहां पहले यह हालत थी कि उस इलाके में गर्मी के मौसम में तीन दिन तक पानी नहीं दिया जाता था। यह ठीक है कि आज भिवानी में अस्पताल है, स्टेडियम है, मिनी सैक्रेटरियेट है, वहां पर सड़कें हैं और वहां पब्लिक हेल्थ का भी कुछ काम हुआ है लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वहां कौवे बोला करते थे। भिवानी के अस्पताल की बिल्डिंग आज इतनी खूबसूरत है कि उस जैसी खूबसूरत बिल्डिंग सारे हरियाणा प्रांत में नहीं है और वहां पर राजस्थान तक के मरीज इलाज करवाने आते हैं। लेकिन महज यह बहाना लगाकर कि भिवानी जिले में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है इसलिये अब वहां पर पैसा खर्च न किया जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि भिवानी जिले के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वह सब पूरे किया जायें। इसी तरह से वहां पर एक सरकारी जिला लायब्रेरी थी जिसका नाम पंडित नेकी राम भार्मा लायब्रेरी था लेकिन उसका नाम बदल कर सरकारी पुस्तकालय रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं पंडित नेकी राम भार्मा हरियाणा के बहुत बड़े

फ्रीडम फाईटर थे और उनका नाम इस लायब्रेरी के साथ जुड़ा रहना चाहिए था। यह भी हो सकता है कि चौधरी साहब को इस बात का पता ही न हो कि भिवानी की लायब्रेरी का नाम बदल दिया गया है.....

चौधरी देवी लाल: इसका वही नाम रहेगा।

श्री सुरेंद्र सिंह: इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले के कुछ नौजवान हरियाणा सरकार की सर्विस में है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि दूसरे जिलों के नौजवान हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस में है लेकिन आज भिवानी के उन नौजवानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। सोनीपत की भूगर मिल में जितने भिवानी जिले के लड़के लगे हुए थे उन सबको निकाल दिया गया है। (व्यवधान)

श्रीमती भांती देवी: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से भाई सुरेंद्र से पूछना चाहती हूँ कि अगर इनकी बात में कोई सत्यता न हो तो क्या यह अपने आप को दोषी मानेंगे? इस वक्त सोनीपत के अन्दर भिवानी के अनेकों लड़के सर्विस में है (व्यवधान)

स्थानीय भासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, भिवानी के लड़कें तो करनाल की भूगर मिल में भी लगे हुए हैं और वहां के लड़कें तो हर जगह लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनके साथी वजीर सबसे ज्यादा टी० ए०, डी० ए० लेते हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली में आर० एस० एस० की रैली थी और अखबारों में आज एक ब्यान आया है.....

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, गवर्नर ऐड्रेस में आर०एस०एस० की चर्चा नहीं होनी चाहिए। सदस्य अपने विषय से बाहर जा रहे हैं, इसलिये अच्छा रहेगा कि विषय के अनुसार ही बोलें।

श्री सुरेंद्र सिंह: क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए। Chaudhri Bansi Lal is not a member of the House but you have been referring to and rebuking him like any thing. That is way you have been bahaving. (Interruptions)

श्रीमती कमला वर्मा: हमने किसी के लिये कुछ नहीं कहा हमने तो सिर्फ यह कहा है कि भिवानी में आलरेडी काफी पैसा खर्च हो चुका है।

Mr. Speaker: I will request the Hon'ble Member not to bring in unnecessary things.

Shri Surrender Singh: I withdraw from the point she is initiating. लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम किसी राजनैतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आज हमारी पार्टी पर एक आर० एस० एस० के जनरल सैक्रेटरी ने इल्जाम लगाया है कि गांधी जी का मर्डर करवाने में

कांग्रेस का हाथा था लेकिन क्या जिस आदमी को यह प्राईम मिनिस्टर मानते हैं, जिस आदमी को ये मुल्क का नेता मानते हैं क्या वे यह नहीं कहते हैं कि गांधी जी की हत्या आर० एस० एस० के एक वर्कर ने की थी? (व्यवधान)

मास्टर रिाव प्रसाद: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, क्या मेरे साथी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ने कब यह कहा कि गांधी जी की हत्या आर०एस०एस० ने की है?

Mr. Speaker: Chaudhri Surrender Singh, please wind up your speech.

Shri Surrender Singh: I would have definitely done so but they are not cooperating.

Mr. Speaker: Please wind up your speech.

श्री सुरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूँ। भिवानी में जितनी टूटी हुई बसें हैं उतनी कहीं भी नहीं है। आम तौर से यह देखा गया है कि बसों की सीटें टूटी हुई हैं और इसलिये मजबूरी में लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है क्योंकि बैठने के लिये कोई सीट नहीं है। हालत यहां तक खराब है कि बसों में छतें भी नहीं हैं और अगर बारिश आ जाये तो लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप एक हजार नई बसें लें ताकि अन-एम्प्लायमेंट खत्म हो और किसान

के खेत तक आप की बसें जायें क्योंकि जब किसान की सरकार है तो किसानों के लिये यह सुविधा होनी चाहिए और भिवानी जिले में बहुत किसान रहते हैं (विघ्न) हमारे जिले के दो चार आदमी ऐसे हैं जो केवल जी० टी० रोड तक का ही टी० ए०, डी० ए० क्लेम करते हैं। (विघ्न)

एक सदस्य: कौन से मैम्बर हैं?

श्री सुरेंद्र सिंह: मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वे इस समय हाउस में हाजिर नहीं हैं। मैं एक और बात तो गाम के बारे में कहना चाहता हूँ जहाँ मैं नुमाइंदा हूँ। स्पीकर साहब, मेरे हल्के का बहुत कम ध्यान रखा जाता है और इस का सबूत यह है कि मेरे कहने से वहाँ का एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है। मैंने शिक्षा मंत्री जी से इस हल्के के एक स्कूल को प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक अपग्रेड करने के लिए कहा था लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ। मैंने पिछली बार हाउस में भी कहा था.....

.....

शिक्षा मंत्री(श्री हीरा नंद आर्य): इ रवाल स्कूल तो गाम हल्के में अपग्रेड हुआ है।

चौधरी देवी लाल: इ रवाल स्कूल इस साल अपग्रेड किया है।

श्री सुरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये जो सुझाव मैंने दिया है कि उनको इन्ड्रैस्ट फी लोन दिया जाए,

जिससे कि उसका गुजारा चल सकें और यदि उसको अपनी फसल बेचने के लिये एक साल वेट भी करनी पड़े तो कर सके। इसके इलावा और आप किसानों को अगली फसल के लिये पानी दें, कर्जा दें। इस बात के लिए अगर आप को पंजाब सरकार से, बादल जी से बात करनी पड़े तो कर लें इससे किसान की फसल का भाव बढ़ेगा।

Mr. Speaker: Please finish your speech now.

श्री सुरेंद्र सिंह: आखिरी बात मैं न ाबंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। न ाबंदी हो लेकिन स्टेट का एक्सचेकर खत्म न किया जाये। जो भाराब पीता है उसको पीने दो, जो नहीं पीता वह बे ाक न पीये। मैं कहना चाहता हूँ कि न ाबंदी करने से रेवेन्यू का नुकसान नहीं होना चाहिए। यही मेरी गुजारि ा है।

श्री जगन नाथ:(बवानी खेड़ा अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, सब से पहले मैं इस गवर्नर ऐड्रेस के लिये मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सचिवों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और गवर्नर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हाउस में खड़े होकर एक डेढ़ घंटा अपना अभिभाषण सुनाया। राज्यपाल महोदय साल के बारह महीने में एक दिन आकर हाउस में यह पढ़कर सुना जाते हैं उनकी जिम्मेदारी इतनी ही है (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) गवर्नर चाहे महाराष्ट्र का हो या और किसी स्टेट का हो

* ** *** ****

* ** *** ****

* ** *** ****

राव बीरेंद्र सिंह: प्वायंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहब, इस बात को एक्सपंज किया जाये ।

श्री जगन नाथ: आप मुख्य मंत्री रहे है आपने भी गवर्नमेंट बनायी थी ।

श्री उपाध्यक्ष: गवर्नर वाली बात एक्सपंज की जाये ।

श्री जगन नाथ:

श्री उपाध्यक्ष: आपको कहा गया है कि गवर्नर को डिसकस न करें ।

श्री जगन नाथ: मैं कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के अन्दर जितने भी बड़े बड़े कमी उन थे जैसे सूरी कमि उन, रेड्डी कमी उन और कपूर कमी उन जिनको बने हुए दो दो साल हो गए है, उनका कोई जिक्र नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि इनमें जिनके खिलाफ भी मुकदमें चल रहे है या तो उन आदमियों को माफ कर दिया जाए या उनके खिलाफ मुकदमों को वापिस ले लिया जाए अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इन पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए । मैं इन से कहना चाहता हूं कि

जो बालसमंद का श्री घन याम दास है क्या वह गरीब है? वह तो दे आ का और कलकते का बड़े से बड़ा बिजनैसमैन है। श्री डी० डी० पुरी क्या गरीब है? वह भी दे आ का और हरियाणा का सबसे बड़ा बिजनैसमैन है। इन्हें तथा फूलचंद आदि को आप लोगों ने पदमश्री दिलवाया था। आप चौधरी देवी लाल जी के मकान पर जाएं तो आपको कोई बिजनैसमैन दिखाई नहीं देगा। इसके विपरीत चौधरी बंसी लाल जी के मकान पर सिवाय बिजनैसमैन के किसी आम आदमी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिये यह कहना कि इन्होंने कुछ नहीं किया बिल्कुल गलत बात है। कुछ क्यों नहीं किया, आप खुले फिरते हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि तीस साल से शिक्षा के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब से प्रौढ़ शिक्षा शुरू हुई थी आज भी उसी तरह से ही चल रही है। जितना पैसा प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च किया जाता है यदि उतना ही पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाए तो सारे बच्चे पढ़ जायेंगे। इस तरह से कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा और यह प्रौढ़ शिक्षा की बीमारी खत्म हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि दे आ में कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मैं पब्लिक स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूँ। यह जितने भी पब्लिक स्कूल हैं यह बिल्कुल खत्म होने चाहिए। हमारे चौधरी चरण सिंह जी, बाबू जगजीवन राम जी

और हमारे प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं कि पब्लिक स्कूल नहीं होने चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय यह होने भी नहीं चाहिए क्योंकि इन पब्लिक स्कूलों के अन्दर बड़े बड़े सरमायेदारों के और बड़े बड़े अफसरों के लड़के पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी नौकरियों में भी इन्हीं के लड़के कामयाब होते हैं। किसी किसान, मजदूर का लड़का तो बाइचांस ही किसी बड़ी नौकरी में आ सकता है। मैं कहूंगा कि पढाई का स्तर सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। पढ़ने का मौका सभी बच्चों को मिलना चाहिए और यही नहीं बल्कि उनके कपड़े भी यानि युनिफार्म स्कूलों के अन्दर एक जैसी होनी चाहिए। जिससे एक दूसरे के बढ़िया कपड़े देख कर किसी बच्चे के मन में हीन भावना न आए। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि दे 1 से भी और इस प्रान्त से भी सारे पब्लिक स्कूलों को खत्म करना चाहिए जिससे पढाई का स्तर एक समान हो। इसके बाद मैं खेलकूद के बारे में कहना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर महोदय, पिछले दिनों इस स्टेटे के कुछ स्पोर्टसमैन मेरे पास आए थे। मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की थी और उस समय वहां चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और शिक्षा मंत्री जी भी वहां मौजूद थे। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में मैं, शिक्षा और ऐजुकेशनल सैक्रेटरी भी शामिल थे। इस कमेटी का यह काम था कि वह यह देखें कि स्टेट के अन्दर किस ढंग से स्पोर्टस को बढ़ावा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय स्टेट में ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम होने चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री जी जहां भी जाते हैं स्पोर्टस के बारे में जोर भी देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल तौर से स्टेट

वहीं की वहीं खड़ी है। सारे का सारा पैसा फिजूल ही जाता है। इस काम के लिए यूज नहीं होता। राई स्कूल के अन्दर 85 परसेंट पैसा स्पोर्टस के नाम से खर्च हो जाता है उस स्कूल का नाम भी स्पोर्टस स्कूल है लेकिन इसके अन्दर भर्ती कैसे होती है? जिसके अलजबरे में नम्बर ज्यादा हों और मैथेमैटिक्स में नम्बर ज्यादा हों और जो मैरिट पर हों उनको इस स्कूल में दाखिला मिलता है। एक तरफ तो वह स्पोर्टस स्कूल और दूसरी तरफ आन मैरिट पर लड़के भर्ती किए जाते हैं। स्पोर्टस कि हिसाब से वह स्कूल वैस्ट जर्मनी के पैटर्न पर बना था और इसका मकसद था कि वहां गांव के छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जाए। उनकी कोचिंग प्रोपर हो, उनकी डाइट प्रोपर हो और उनकी सिलैव इन भी प्रोपर हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही उस स्कूल को चलाना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर साहब, कैबिनेट में डिसक्स होने के बाद यह फैसला हुआ कि शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। लेकिन आज तक उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। इसलिये राई स्कूल को या तो पब्लिक स्कूल बना दें या जो पैसा वहां खर्च होता है वह बराबर सारी स्टेट में खर्च होना चाहिए। पिछले दिसम्बर में उमरा गांव की हाकी की टीम जोन से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक जीतती गई और उसके खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ। जब स्टेट की हाकी की टीम का सिलैव इन हुआ तो उस गांव के हाई स्कूल का एक भी लड़का नहीं लिया गया। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। इसलिये उस कमेटी को ज्यादा से

ज्यादा सजा देनी चाहिए। हरियाणा में जो पैसा स्पोर्ट्स पर खर्च होना चाहिए, वह पैसा स्पोर्ट्स पर खर्च नहीं होता है। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवी लाल जी ने जो चौपालों का कार्यक्रम भुरू कर रखा है और बन भी रही है, यह एक बहुत सराहनीय कदम है। गांव में गरीब हरिजन के पास इतनी जगह नहीं होती है। यदि कोई बारात आ जाए या कुछ आदमी आएँ तो उनके लिए बड़ी समस्या होती है। बड़े बड़े गांवों में एक-एक मील के फासले पर पाने बने हुए हैं, उन गांवों में एक पाने वाले दूसरे पाने में नहीं जा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। भिवानी में एक गांव बहुत बड़ा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा चौपाल होनी चाहिए मैंने डी० सी० साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हम एक चौपाल से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। इसलिये मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि 4 या 5 हजार वह दे दें और उतने ही गांव वालों से ले लें फिर चाहे गांव में 10 चौपाल क्यों न बनानी पड़े। भिवानी के बारे में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने कहा और मैं भी कहना चाहता हूँ। कई भाई रूलिंग पार्टी वाले कहते हैं कि भिवानी के अन्दर बहुत कुछ बन गया है। वहां एक बड़ा रैस्ट हाउस है वह बड़े बड़े आदमियों के सिवाय किसी के काम नहीं आता है। वहां पर जितने भी डिवैल्पमेंट के काम थे, जैसे हस्पताल के, स्टेडियम के और बेकरी के, यह सारे के सारे बंद हैं और इनके ऊपर पहले भी काफी पैसा खर्च हो चुका है, परन्तु वह पूरे नहीं हुए हैं। यदि यह पूरे नहीं हुए तो सारे का सारा पैसा फिजूल में जाएगा। यह दोनों मंत्री महोदय

भी सुन रहे हैं और इन्हें पता भी है कि जितने भी वहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 के हिसाब से और नहर के हिसाब से डिविजन थे वह सारे के सारे उठा लिये गये हैं। मैं सुंदर नहर के बारे में भी कहना चाहता हूं कि उस नहर का एरिया सारे का सारा भिवानी में पड़ता है उसका थोड़ा सा एरिया हिसार में पड़ता है। उसके डिविजन को भी उठा लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उस डिविजन के उठाने से एरिया के लोगो को तकलीफ होगी न कि एक हल्के के लोगो को होगी। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि सारे जिले के हित को देखते हुए ये डिविजन नहीं उठाएं जाने चाहिए क्योंकि हमने कोई बुरा नहीं किया है। वहां पर डिवैल्पमेंट का काम होना चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी की हकूमत के अन्दर हमने ही उनसे सब से ज्यादा लड़ाई लड़ी थी। यहां के लोग डी0आई0आर0 के तहत अन्दर गए, दफा 107 और 151 के तहत अनद गए और मीसा के अन्दर गए। कहने का मतलब यह है कि यहां के किसी भी आदमी ने किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाई और सब से ज्यादा कुर्बानियां की है। इन तकलीफों को देखकर इनका जो डूय है जो हिस्सा बनता है वह मिलना चाहिए और दूसरे जिलों के मुकाबले में लाना चाहिए। जहां तक पर-कैपिटा इन्कम का ताल्लुक है, भिवानी की पर-कैपिटा इन्कम सबसे कम है। पीने के लिये पानी नहीं, हस्पताल नहीं और लोगो की माली हालत बहुत खराब है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि लोहारू, सिवानी, तो गाम, बाढ़ड़ा के इलाके सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए और

जो स्कीमें बीच में इनकम्पलीट पड़ी है, उनको पूरा किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

चौधरी संत कंवर सिंह(हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने हमारी असैम्बली को जो ऐड्रेस किया है, उसके लिये मैं गवर्नर साहब का धन्यवाद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजी इन के मैम्बरान की तरफ से जनता पार्टी की सरकार पर बड़ी टीका टिप्पणी की गई। राव बीरेंद्र सिंह जी ने आंकड़े देकर बताया कि जनता सरकार ने, मेरे ताऊ जी की सरकार ने किसानों के लिये क्या क्या काम किए, इनकी आलोचना की गई। लेकिन इन्होंने यह बात नहीं सोची कि हरियाणा के अन्दर जितनी बाढ़ जनता सरकार बनने के बाद आई और जितना नुकसान इस बाढ़ से हरियाणा का किया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, इतनी तबाही हरियाणा में पहले कभी नहीं हुई और उस तबाही का जिस तरीके से चौधरी देवी लाल की सरकार ने मुकाबला किया, संसार में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती और किसान को हर सम्भव सुविधा दी गई। डिप्टी स्पीकर साहब, जब बाढ़ आई तो उसका निरीक्षण करने के लिये हमारे सी०एम० साहब, गांव गांव में घूम रहे। राव बीरेंद्र सिंह को भायद इस बात का पता नहीं, क्योंकि जब वे सी०एम० थे तो उन्होंने इस तरीके से दौरे नहीं किए थे जिस तरीके से चौधरी देवी लाल जी ने किए हैं। पानी के अन्दर ट्रैक्टरों में बैठकर, उन गांवों में गए जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। गांव में

जाकर लोगों को दवाईयों का इन्तजाम किया, खाने का इन्तजाम किया, पंजुओं के लिये चारे का इन्तजाम किया और जो कुछ भी सम्भव हो सका, लोगों की सहायता की और लोगों को बाढ़ से बचाया गया। मेरी कांस्टीच्युएंसी में नयावास नाम का गांव है। उस गांव में एक मंजिल के तमाम कच्चे घर पानी में डूब गए थे। माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर श्री बीरेंद्र सिंह जी पिछले साल वहां पर गये थे और सारे हालात का अनुमान लगाया गया। वहां के लोगों ने कहा कि चौधरी साहब हमें इस गांव से निकाल कर किसी दूसरी जगह बसा दिया जाएं, हम पिछले 10 सालों से पानी में डूबते आ रहे हैं, किसी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। चौधरी देवी लाल जी ने उनको आवासन दिया कि अगले साल तुम्हारे मकानों में पानी नहीं आएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस गांव में पानी से एक-एक मंजिल मकान डूब जाया करते थे उसमें चौधरी देवी लाल जी के आवासन के मुताबिक एक बूंद भी बाढ़ का पानी दाखिल नहीं हुआ और जो फसल पहले खराब हो जाया करती थी वह खराब नहीं होने दी। इस वक्त तमाम इलाके में हरी आशाढ़ी की फसल खेतों में खड़ी है। बाढ़ को रोकने के लिये जो काम इस सरकार ने किया इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। जो कुकर्म पिछली कांग्रेस सरकार ने किए थे अगर उन कुकर्मों को ठीक करने की कोशिश करते तो दो साल तो उन कुकर्मों को ठीक करने में लग जाते, लेकिन चौधरी देवी लाल जी प्रदेश की तरक्की के कामों में जुट गए उन्होंने तिकड़मबाजी की राजनीति को नहीं

अपनाया जिस तरह से पहले के मुख्य मंत्रियों ने अपनाई थी। जब चौधरी बंसी लाल और श्री बनारसी दास गुप्ता रोहतक में जाया करते थे तो ये भाई कहते थे कि भिवानी के साथ डिसकिमिने इन किया है और हमें पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली। रोहतक और सोनीपत के लोग यही कहा करते थे कि हमारे साथ डिसकिमिने इन किया गया है लेकिन आज रोहतक और सोनीपत के लोग यही कहा करते थे कि हमारे साथ डिसकिमिने इन किया गया है लेकिन आज रोहतक और सोनीपत के अन्दर अगर आप लोगों को पूछें तो यही कहते हैं कि चौधरी देवीलाल जी की सरकार ने जितना पानी हमें दिया है, इतना कभी नहीं मिला। नहरी पानी के बारे में लोग कहते थे कि हमारे साथ डिसकिमिने इन किया गया है, लेकिन आज वहां पानी पहुच गया हैं। जहां तक बिजली का ताल्लुक हैं, कांग्रेस सरकार के जमाने में किसानों को समय पर कभी बिजली नहीं मिली। जब किसानों को बिजली देते थे तो दिन की बजाये रात को देते थे, रात को ट्यूबवैल्ज चलाते थे कैं र चलते थे थ्रैसर चलते थे लेकिन चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि किसानों को दिन रात हर वक्त बिजली मिलेग कभी बिजली जाती ही नहीं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जब करनाल में ऐजीटे इन किया था तब बहुत से लोगों ने उस ऐजीटे इन में हिस्सा लिया और चौधरी देवी लाल जी उस वक्त अपोजी इन में थे। यह कहा करते थे कि ट्रैक्टर बैल-गाड़ियों की तरह है जिस तरह बैल गाड़ियां आती-जाती है उसी तरह ट्रैक्टर आते-जाते है

इसलिये ट्रैक्टरों पर टोकन टैक्स नहीं होना चाहिये। ये कहा करते थे कि अगर मेरी सरकार आयेगी तो ट्रैक्टरों पर टैक्स नहीं होगा और बैल-गाड़ियों की तरह ट्रैक्टर चला करेंगे। आज चौधरी देवी लाल जी ने ट्रैक्टर का टोकन टैक्स तथा सवा छः एकड़ तक का मालिया मुआफ कर दिया। यही नहीं, हर फील्ड में अगर आप देखें पिछले दो साल के अर्से में जनता पार्टी की सरकार ने, चौधरी देवी लाल जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद, बहुत सराहनीय काम किए हैं। जब से आजादी आई है आप इतिहास उठाकर देखें आंकड़े देने वाले लोग कांग्रेस का पिछले तीस साल का इतिहास देखें दो साल के अर्से के अन्दर जितना काम इस सरकार ने किया उतना पिछली सरकार ने नहीं किया। इतनी बाढ़ के बावजूद जो प्रगति हरियाणा की चौधरी देवी लाल के आने के बाद हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर साहब, यह किसानों की सरकार है। किसान चूंकि गरीब हैं इसलिये सरकार किसान की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही, लेकिन हरिजन इससे भी ज्यादा गरीब हैं। हरिजनों की भलाई की तरफ भी यह सरकार पूरा ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार तो जानती ही नहीं थी कि हरिजन ज्यादा गरीब हैं, क्योंकि वे इन लोगों के बीच में नहीं रहते थे, वे रईसों की दुनिया में रहते थे। लेकिन चौधरी देवी लाल जी हरिजनों के बीच में रहते हैं। इन्होंने चौपालें बनाने के लिए लोगों से पैसा इक्ठठा करवाया और उत्साहित करने के लिये यह ऐलान कर दिया कि जितना पैसा गांव के लोग इक्ठठा करके देंगे उतना ही सरकार देगी। आज

हालत यह है कि तमाम हरिजनों के लिये चौपालें बनाई जा रही हैं और सरकार की तरफ से पूरी सहायता दी जा रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। यह समस्या हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। गरीब घरों के लड़के जो बी०ए०, एम०ए० या मैट्रिक पास कर चुके हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिये। चौधरी देवी लाल जी की सरकार पहली सरकार है जिसने एक स्कीम बनाई है कि दो लड़के तीन लड़के या चार लड़के इक्ट्ठे होकर अगर काम करना चाहें तो सरकार 10 हजार से लेकर 1 लाख तक कर्जे के रूप में सहायता देगी ताकि वे पढ़े-लिखे नौजवान गांवों में छोटे छोटे कारखाने खोल सकें। इसके साथ ही साथ 15 परसेंट सबसिडी देने की व्यवस्था भी की गई और चौधरी देवीलाल जी ने पार्टी मीटिंग में यह बात कही कि जो हम लोन दे रहे हैं जो सबसिडी दे रहे हैं अगर कोई गरीब लड़का दस परसेंट पैसा नहीं दे सकता तो हम सबसिडी की राशी पहले देंगे ताकि वह दस परसेंट दे सके और लोन ले सके। यह ऐलान सी०एम० साहब ने पार्टी मीटिंग में किया कि सबसिडी पहले देकर सरकार उसकी फ़ैक्टरी लगवा देगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कई बातों का जिक्र किया। छात्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1970 में कांग्रेस सरकार ने जिस सरकार को वे अपनी पार्टी की सरकार कहते हैं और जिस पार्टी की बुराई राव बीरेंद्र सिंह जी कर रहे थे, 1970 में रिवाड़ी रेलवे स्टेशन पर कालेज के विद्यार्थियों पर सरेआम गोलियां चलाई। इनको याद होगा 30

जनवरी की बात है और इस संबंध में असैम्बली में बड़ा हंगामा हुआ था। यह उस पार्टी के कारनामों है जिस पार्टी की गोद में ये बैठे हैं। चौधरी देवी लाल ने स्टूडेंट्स के लिये किया है कि 60 मील से भी यदि कोई विद्यार्थी भाहर में पढ़ने जाता है तो उसे बस में कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। इतनी सुविधा इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दी थी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप वाइंड अप कीजिए।

(16.00 बजे) चौधरी संत कंवर: उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने जो जो काम किए हैं उन बातों की तरफ अगर विरोधी पक्ष ईमानदारी से ध्यान दे तो इनको विरोध करने के लिये कोई बात रह नहीं जायेगी। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब मैं एक दो बातें और कह कर अपना स्थान ले लूंगा। चौधरी देवी लाल जी का ध्यान मैं एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज भी बहुत से पब्लिक स्कूल हमारे प्रदेश के अन्दर चल रहे हैं लेकिन इन स्कूलों के अन्दर किसी गरीब घर का बच्चा पढ़ नहीं सकता। इनमें तो एम0एल0ए0, वजीर आई0ए0एस0 और आई0सी0एम0 वालों के बच्चों पढ़ सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि जो बच्चे पब्लिक स्कूलों में अच्छी शिक्षा पाते हैं वे ही आमतौर पर कम्पीटिशन में कामयाब होते हैं, गरीब घर के बच्चे इनमें कामयाब नहीं होते। उपाध्यक्ष महोदय जब तक हमारे प्रदेश के अन्दर समान शिक्षा नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि समाजवाद की बात करना महज एक मजाक

होगा। इसलिये मुख्य मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि चौधरी देवी लाल जी जहां अपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं वहां यह काम और कर दें कि आज हरियाणा के अन्दर जो पब्लिक स्कूल हैं उन स्कूलों को ऐसे स्कूलों में परिवर्तित कर दें जहां समान शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो, जहां गरीब का बच्चा भी पढ़ सके और अमीर का बच्चा भी पढ़ सके। मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब ऐसा अवयव करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी की फराखदिली के एक मिसाल मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मेरी कांस्टीच्युएंसी में एक गांव खेड़ीसात है। वहां से रोहतक से दिल्ली वाला नेटल हाई-वे गुजरता है। उस गांव के पास एक मोड़ पड़ता है जहां चार खम्बे हैं। वहां अक्सर ऐक्सीडेंट होते रहते हैं। उस गांव वालों ने चीफ मिनिस्टर साहब के नाम एक दरखास्त दी कि वहां एक बल्ब लगा दिया जाए। चौधरी साहब ने उस एक बल्ब की दरखास्त को देखकर केवल यह फैसला नहीं किया कि वहां एक बल्ब लगा दिया जाये बल्कि तमाम गांव के लिये स्ट्रीट लाईट मंजूर कर दी गई। भायद राव बीरेंद्र सिंह जी को इस बात का पता नहीं कि अब तमाम गांव के अन्दर स्ट्रीट लाईट लगवा दी जाएगी। (विघ्न) जहां तक राव साहब की इस बात का ताल्लुक है कि उधर बैठे एम0एल0एज0 के कहने पर काम नहीं होते बल्कि इधर बैठे एम0एल0एज0 के कहने पर काम हो जाते हैं, मैं इनसे यह बात कहना चाहता हूं कि

अपोजी 1न में बैठे एम0एल0एज0 के कहने पर किसी सरकार ने इतने काम नहीं किये होंगे, जितने इस सरकार ने किए हैं। जब इन बैंचों पर ये लोग बैठा करते थे तब काम नहीं होता था लेकिन चौधरी देवीलाल ने बगैर इनके कहे बराबर काम किया है। बाढ़ के दिनों इनको बुलाया गया लेकिन ये नहीं आए। चीफ मिनिस्टर साहब ने मंत्रीगण ने और जनता पार्टी के एम0एल0एज0 ने सिर पर टोकरियां उठा-उठा कर बाढ़ पीड़ित इलाकों में काम किया लेकिन ये बुलाने के बावजूद उस प्रोग्राम में भागिल नहीं हुए। यही नहीं इनको यह याद होना चाहिये कि उस वक्त बिना किसी भेदभाव के तमाम एम0एल0एज0 की कांस्टीच्युएंसी में एक-एक स्कूल मंजूर किया गया था और अब दो-दो किए जा रहे हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था कि जिस वक्त हमारे मुख्य मंत्री जी वजीर साहिबान और दूसरे एम0एल0एज0 गांव में काम करते हैं उस वक्त राव साहब इन्दिरा जी की कोठी में होते हैं ये गांव के अन्दर नहीं पहुंचते और उसके बाद गलत तरीके से, डिस्कमिने 1न का नाम लेकर जब इन्हें कोई और बात कहने को नहीं मिलती, सरकार का विरोध करते हैं। इन भाबदों के साथ, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं राज्यपाल के अभिभाशण की प्र ांसा करता हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि गवर्नर ऐड्रैस अगले साल के लिये सरकार की एक पालिसी होती है। लेकिन

बड़े अफसोस की बात है कि इस गवर्नर ऐड्रेस को इन्होंने एक रूटीन बनाया हुआ है। ये गवर्नर ऐड्रेस को लिख देते हैं और गवर्नर साहब असेम्बली में उसे पढ़ जाते हैं। मैं गवर्नर जात की पूरी कदर करता हूँ लेकिन गवर्नर साहब के इस ऐड्रेस में कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टैप नहीं उठाया गया है जिससे हरियाणा की काया पलट जाए। जितने पैसे हरियाणा में खर्च किए जाते हैं ये सारे हरियाणा के लोगों की खून पसीने की कमाई होती है। यह कोई बात हुई कि चालीस करोड़ रूपया तो फ्लड के कामों पर खर्च हो जाए लेकिन कोई टाईम बाउंड प्रोग्राम न बनाया जाए कि फलां तारीख तक हरियाणा में फ्लड मुक्कमल तौर पर रोका जाएगा। पिछली बार इसी विधान सभा भवन में गवर्नर ऐड्रेस में यह पढ़ा गया था और सी० एम० साहब ने भी यह यकीन दिलाया था कि अगला जो सीजन बरसात का होगा उसमें फ्लड की जहमत नहीं होगी, रहमत होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जहमत हुई रहमत नहीं हुई। मेरे छोटे भाई चौधरी संत कंवर ने अभी कहा कि इस बार बाढ़ से सारा हरियाणा तबाह हो गया लेकिन मैं पिछली बात को छोड़ता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इन अफसरों के ऊपर कंट्रोल करके ऐसा काम किया जाए कि अगले साल हरियाणा में फ्लड देखने को न मिले। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मिनिस्टर ठाकुर बीर सिंह जी हमारे इलाके में ऐलान करके आए थे कि अगली फसल आने तक किसी गरीब किसान से मालिया या तकावी वसूल नहीं की जाएगी लेकिन अफसोस की बात

है कि लोगों को अपने जेवर गिरवी रख कर पांच रूपये सैंकड़ा ब्याज पर पैसे लेकर मालिया देना पड़ा। (विघ्न)

विकास मंत्री(ठाकुर बीर सिंह): कोई मालिया नहीं लिया गया।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं नहरों की बाबत कहूंगा। पंजाब से तो पानी जब मिलेगा तब देखेंगे लेकिन मौजूदा पानी भी मुक्कमल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बड़ी कमाल की बात है कि हमारे एस0ई0 साहब कहते हैं कि हमें पानी की जरूरत नहीं जबकि तहसील कैथल के इलाके के सारे खेत सूखे पड़े हैं। इसके लिये तो कोई कै 1 प्रोग्राम बनाया जाना चाहिये। कांग्रेस की यहां बड़ी बुराई की जाती है। मैं कहता हूं कि बुराई करनी है तो करो लेकिन साथ ही कुछ काम करके तो दिखाओ। (विघ्न) मैं तो कहना चाहता हूं कि यह जनता सरकार कांग्रेस सरकार की गलतियों की पैदावार है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेसी तो नए कांग्रेसी हैं पुराने कांग्रेसी तो उधर बैठे हैं। चौधरी देवी लाल जी, जैन साहब और चौधरी भजन लाल जी आदि सबसे बड़े कांग्रेसी थे। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस काम के लिय आप कै 1 प्रोग्राम बनाओं क्योंकि हरियाणा की जनता आपके साथ है। चौधरी साहब को इसी सै 1 न में यह ऐलान कर देना चाहिये कि एक साल के अन्दर-अन्दर हरियाणा की एक खूड जमीन बगैर

पानी के नहीं रहेगी और न ही हरियाणा में आयंदा फ्लड आएंगे। यह बात गवर्नर ऐड्रैस में होनी चाहिए थी। यह तो इन्होंने बड़ा थोथा सा ऐड्रैस दे दिया। (विघ्न)

डिप्टी स्पकीर साहब, बड़ी खुशी की बात है कि ऐग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। हमें यह भी खुशी है आज सैंटर में भी और यहां भी ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर किसान है। रात दिन दुआएं तो किसान को दी जाती हैं लेकिन किया बहुत कम जाता है। इलधर की सरकार हलधर की जड़ में बैठ गई है।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ ही जेल में रहा हूँ और उनके साथ ही गिरफ्तार हुआ था। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी पहले किसानों के लिये 150 रूपया क्विंटल का भाव गेहूं का मांगते थे और इसी तरह से गुड़ का भाव भी 150 रूपये क्विंटल मांगते थे लेकिन आज उनके राज में दोनों चीजों के भाव गिरे हुए हैं।

जब सन् 1967 में एस0वी0डी0 की सरकार आयी तो उस समय दोनों चीजों के भाव बड़े अच्छे थे। वह सरकार भी चौधरी देवी लाल जी की ही बनायी हुई थी। सन् 1967 में यह बात प्रचलित हुई थी कि राव आया तो भाव भी आया राव गया तो भाव भी गया इसी तरह से आपको भी मिसाल कायम करनी चाहिए

कि देवी लाल आया तो भाव आया और देवी लाल गया तो भाव गया। आज मैं दहिया की खाप से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि तीन और चार रूपये के भाव से कैरार पर गन्ना डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दिल चाहता है कि इस गन्ने को सुखा कर आग लगा दी जाये तो अच्छा रहेगा। आज देश के अन्दर कोई भी चीज ले ले सब चीजों के भाव बढ़े हैं, हर चीज की महंगाई हो रही है। लेकिन जो चीज किसान पैदा करता है उसका कोई भाव नहीं बढ़ा है। न ज्वार का भाव बढ़ा और न ही कपास का भाव बढ़ा लेकिन जो चीजें कारखानों में पैदा होती हैं उनमें गुड़ और चीनी को छोड़ कर सब चीजें महंगी हैं। आज नमक से लेकर कपड़ा तक सब चीजें महंगी हैं। वे लोग मन चाहे भाव लेते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपके जरिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी चीजें कारखानों में पैदा होती हैं उन सब के भावों पर कंट्रोल किया जाये और उनके भावों को मुकर्रर किया जाये। जो लोग नाजायज तौर पर पैसा कमा रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज किसानों को अनाज का भाव नहीं मिलता है, इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। सरकार सारे अनाज को खुद खरीदे, जो भी घाटा हो उसको सरकार बरदागत करे। सरकार जिस तरह से कारखानेदारों को घाटा होने पर सबसिडी देती है उसी प्रकार से जमींदारों को भी सबसिडी दी जानी चाहिये। आज अगर किसान कमजोर होता है तो देश

कमजोर होता है। आज फौज के अन्दर कौन भर्ती होता है? वह किसान का बेटा होता है। कान्ति और सुरे । फौज में भर्ती होते हैं। इसलिये सब से पहले किसान की भलाई की ओर ध्यान देना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं आपके सामने बेरोजगारी की समस्या के बारे में भी अपने विचार बताना चाहता हूँ। बेरोजगारी की हरियाणा में ऐसी हालत है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। आज कितने ही बच्चे हरियाणा में बरोजगार हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार की ओर सह कुछ लघु उद्योग लगाये जा रहे हैं लेकिन इतने लोगों की बेरोजगारी इन लघु उद्योगों से दूर नहीं हो सकती।

जहां तक ट्रांसपोर्ट की हालत का संबंध है वह तो और भी दयनीय है। बसों के भी ो टूटे हुए हैं, खिड़कियां और छतों की बुरी हालत है, बैठने के लिये कोई सीट ठीक नहीं। कैथल डिपो में 134 बसें चलती हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि कोई बैठ नहीं सकता। अभी पीछे 13.2.1979 को वहां के जी0एम0 को चीफ मिनिस्टर साहब ने बदल दिया है। उन्होंने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। वहां के जी0एम0 के खिलाफ 11.2.79 को पुलिस थाने में पर्चा दर्ज हुआ। चोरी किया हुआ काफी माल उसके यहां से बरामद हुआ है। उसके कब्जे से फिल्टर, बैंक लाइनर्ज, टोप-गैरेज, ब्रेक आयल और फाइन बैल्ट आदि चोरी की पकड़ी गई है। इस तरह से हजारों रूपये का

सामान वहां से बरामद हुआ है लेकिन मुझे यहां हाउस में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस केस में वहां के छोटे मुलाजिमों को भी फंसाया गया है। मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि वे मौके पर आई0जी0 साहब को भेज कर इनक्वायरी करवाये उनसे और भी सामान मिलने की उम्मीद है। उसको गिरफ्तार किया जाये और उसको मुअतिल किया जाये। आप यह सुन कर हैरान होंगे कि कैथल डिपों में 134 बसें है लेकिन वहां पर दस महीने के अन्दर 13 लाख रूपये का घाटा हुआ है। वहां का जो जी.एम. थ वह तो कहता है कि मेरे सैक्रेटेरियट में अपने आदमी बैठे है, मेरे अपने रि तेदार है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिये इस आदमी के खिलाफ इन्क्वायरी पूरी तरह से होनी चाहिये और हेड आफ दि डिपार्टमेंट है उसको रिवर्ट किया जाये क्योंकि जो भी हेरा-फेरी हुई वह किसी के साथ मिलकर हुई है।

हमारे डिपों की बसों की हालत तो इतनी खराब है कि छोटे बच्चे और औरतों का तो बैठना ही मुश्किल हो गया है। मैं सरकार के समाने यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो छोटै रूटस है उन पर पढ़-लिखें नवयुवकों को परमिटस दिये जाये ताकि उनको भी कुछ धंधा मिल सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये रिजर्वे इन के विशय में भी अर्ज करना चाहता हूँ। कास्ट बेसिज पर रिजर्वे इन नहीं होनी चाहिये क्योंकि जिस तरह से पहले और रिजर्वे इन हुई

है उसी प्रकार आज सभी जगहों से अलग-अलग जातियों के लिये रिजर्वे इन की मांग आ रही है। मैं इस बारे में अर्ज करूंगा कि केवल दो जातें होनी चाहियें एक गरीब और दूसरी जात अमीर। यदि रिजर्वे इन होती है तो इकोनोमिक बेसिज पर होनी चाहिये। जाति के आधार पर रिजर्वे इन बंद होनी चाहिये। दूसरे जो सरकार ने रिजर्वे इन इन प्रोमो इन रखी हुई है यह भी बंद होनी चाहिये।

एक बात और भी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि भादी ब्याह में बहुत ज्यादा रूपया खर्च किया जाता था। इस पर कंट्रोल करने के लिये पब्लिक रिले इन्ज डिपार्टमेंट की ओर से पब्लिसिटी की जाये, प्रचार करना चाहिये ताकि लोग इस मौके पर ज्यादा पैसा न खर्च करने की आदत बनायें।

डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल और बादल साहब की बड़ी पक्की दोस्ती है। दोनों नजदीक गांवों के रहने वाले है लेकिन पंजाब को जो हमारा रावी व्यास का पानी का हक है, वह देना चाहिये। इस मामले में हरियाणा की जनता को एक होकर लड़ना चाहिये और पानी का हक लेना चाहिये। जो हैड-वर्क्स है और बी0एम0बी0 है उसमें जितना हमारा हक है वह पूरा मिलना चाहिये। बादल साहब हमारे चीफ मिनिस्टर की दोस्ती का नाजायज फायदा न उठायें। इस बारे में चौधरी देवी लाल को कोई कदम उठाना चाहिये, हम सब उनके साथ है।

आज हरियाणा में ला एंड आर्डर की हालत यह है कि रोजाना चोरियां होती हैं लेकिन बरामदगी बिल्कुल नहीं होती। होठियां सिंह सरपंच साकिन सातकस को कैथल बस स्टैंड के ऊपर दिन दिहाड़े लूटा गया। इसी तरह से हमारे ए० आई० जी० (सी०आई०डी०) को पी०डब्ल्यू०डी० रैस्टहाउस में लूटा गया। पुलिस अफसर को अगर लूट लिया जाता है तो आम आदमी का जीवन कैसे सेफ हो सकता है।

आवाजें: सारा पैसा और माल रिकवर हो चुका है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मुझे एक ऐप्लीकेशन मिस राधा सचदेवा की मिली है। उसमें बड़े सीरियस ऐलीगेशन लगाये गये हैं। मैं इसको सदन की मेज पर रखना चाहता हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब इस बारे में इन्कवायरी करायें और कन्सर्नड अफसर को सजा दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष: आप इसे आफिस में दे दें। इसे ऐग्जामिन करवा लेंगे। अगर जरूरत समझी गई तो सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

चौधरी देवी लाल: सदन की मेज पर रखने की बजाय आप मुझे दे दें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): इसको आठ तारीख को पर्सनल हियरिंग दी हुई है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब सड़कों की बहुत ही बुरी हालत है। बरसात अधिक होने से और फ्लड आने से सारी सड़कें टूट गई हैं। उनकी रिपेयर करवाई जानी चाहिये थी परन्तु अभी तक नहीं हुई है। अगर इसी तरह ये सड़के रहीं तो और भी ज्यादा खराब हो जायेंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अफसर क्या कर रहे हैं। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे हल्के में चार सड़कें मंजूर हुई थी परन्तु आज तक एक भी पूरी नहीं हुई है।

ऐजुके ान की भी बहुत खराब हालत हैं। ऐजुके ान को ने ानेलाइज किया जाना चाहिए। कैथल के अन्दर एक जाट हाई स्कूल है, उसमें बी०एड० क्लासिज भी है। उस स्कूल का मैनेजमेंट एक आदमी के हाथ में है। पहले उसका मैनेजमेंट मेरे हाथ में था परन्तु मेरे से जबरदस्ती छीना गया था जिसके बारे में हमारे सी०एम० साहब को भी मालूम है। इसलिये सरकार को चाहिये कि उसका मैनेजमेंट अपने हाथों में ले। वह आदमी वहां से लाखों रूपया खा रहा है।

चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सिरसे जिले में तो 144 गांवों में ड्रिंकिंग वाटर स्कीम मंजूर की है परन्तु मेरे हल्के में एक भी स्कीम लागू नहीं की है। इसलिये मेरे हल्के की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

ऐनीमल हसबैंडरी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मिल्व कैटलज की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जाये। आर्टीफिियल इनसैमीने इन सैंटर्ज को बंद किया जाये क्योंकि यह नाकामयाब है। इंडस्ट्रीज की बाबत मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी सीलिंग होनी चाहिये। एक आदमी के पास सीलिंग से ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिये। जो गांवों में इंडस्ट्रीज लगाने की बात की जाती है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो माल छोटी इंडस्ट्रीज में तैयार हो सकता है उसे बड़ी इंडस्ट्रीज में बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बारे में मैं तो यहां तक कहना चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्रीज का महकमा डाक्टर मंगल सैन से छीन कर बिग्रेडियर रण सिंह जी को दे दिया जाये ताकि वे गांव के रहने वाले होकर गांव वालों के साथ इन्साफ कर सकें। (गोर व व्यवधान)

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पोहल साहब अभी-अभी ऐनीमल हसबैंडरी के बारे में बोल रहे थे।***** (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, वे गलत बात कह रहे हैं। मैं इसको औब्जेक्ट करता हूँ। या तो उन्हें ये भाब्द विदद्दा करने के लिये कहा जाये वरना ये भाब्द एक्सपंज किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष: झोटे वाली बात एक्सपंज की जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: यू०पी० में, हिमाचल प्रदेश में और सैंटर में आजकल झगड़े बढ़ रहे हैं। आर०एस०एस० का अलग से जिक्र आ रहा है। रोज अखबारों में जनसंघ का और आर०एस०एस० का जिक्र आता है। इसलिये मैं चौधरी साहब से यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई हरियाणा का भला करना चाहते हो तो आपको अपने एडवाइजर बदल देने चाहिए। आपकी तो एडवाइस सैंटर में भी चलती है जब आपकी एडवाइस चौधरी चरणा सिंह जी जैसे बड़े आदमी लेते हैं तो आपको अपने लिये एडवाइजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो एडवाइजर मिश्रा है उसको हटा दिया जाये। आपके लिये दो एडवाइजर ही काफी हैं। आप चौधरी साहब, ऐसा कीजिये कि कांग्रेस (आई), बी०के०डी० और लाईक माइंडिउ लोगों की मिनिस्ट्री बनाइये। हम आपका साथ देंगे। (हंसी व भाोर) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं टीचर्ज के बारे में कहना चाहता हूँ। जो भी आने साईंस और मैथीमैटिक्स मास्टर्ज सिक्स मन्थस बेसिज पर रखे हुए हैं, उन सब को रैगुलेराईज किया जाये। इसके अलावा अगर आप किसान का कुछ भला करना चाहते हैं तो भाहरों में जितनी भी मंडियां हैं उन सब को तोड़ कर गांवों में मंडियां खोल दें। चौधरी साहब से एक बात मैं न आबंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। चौधरी भजन लाल जी अभी यहां बैठे थे, परन्तु पता नहीं अब कहां चले गए हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि अगूर की

भाराब बननी चाहिये। यहां पर न गाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां कैथल में 28.11.1978 को एक पेट्रोल पम्प पर से डीजल की ब्लैक करता हुआ एक आदमी गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में सिटी पुलिस ने उसको रिहा कर दिया। इसके अलावा खाद का एक बैग जिसका वजन 50 किलों होना चाहिये साढ़े बयालिस किलो ही निकलती है और उसके ऊपर भी 7-8 रूपए ब्लैक होती है। यह बरदा त होने वाली बात नहीं है। इस अभिभाषण में कहीं भी गरीब और अमीर के फर्क को कम करने की बात नहीं नजर आती है।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइये। आपका समय समाप्त हो चुका है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: बस जी, मैं आखिरी बात कह कर बैठ ही रहा हूं। एक बिल लाकर किसानों के सारे कर्जे सरकारी और प्राईवेट माफ किये जायें। इसके अलावा किसानों के साथ एक और डिस्कमिने तन है। उनकी जमीन के ऊपर तो सीलिंग है लेकिन भाहरी जमीन पर कोई सीलिंग नहीं है। चौधरी साहब को 18 एकड़ जमीन की कीमत लगा कर उसके बराबर की जायदाद पर सीलिंग भाहरों में भी लगानी चाहियें ऐसा अगर सरकार कोई बिल लायेगी तो हम सब मुझे आ ता है, उसे जल्दी से जल्दी पास करेंगे।

चौधरी गया लाल(हसनपुर अनुसूचित जाति): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भारी वर्षा के कारण आयी तबाही का वर्णन किया गया है। यह तबाही जिला गुड़गांव, रोहतक, इन दो जिलों में ज्यादा आयी। गुड़गांवां जिला में नुंह और फिरोजपुर मेवात के इलाके हैं, और 15-20 साल से यह इलाका यो ही तबाह होता रहा है। पिछली सरकार ने इतने बड़े इलाके की तरफ जहां पर कि हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती थी, कोई ध्यान नहीं दिया। वह इतना बड़ा क्षेत्र इतनी खराब हालत में हो गया, इतनी गरीबी आ गयी कि वहां का किसान भी मजदूरी करने पर उतर आया। आप हमारे यहां जाकर देखेंगे तो आपको कहीं पर वह रिक् गा चलाता हुआ मिलेगा, कहीं पर मिट्टी खोदता हुआ मिलेगा और कहीं पर रोड़ी कूटता हुआ मिलेगा। यह हालत पिछले 20 सालों के अन्दर वहां के किसान लोगों की हो गयी थी। इस तबाही को देखसते हुए, इस फ्लड को देखते हुए हमारे चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने इस तरफ पूरा ध्यान दिया। आज हजारों एकड़ जमीन जो वहां पर पानी में डूबी रहती थी वहां पर तीस किलोमीटर लम्बा नाला 18 करोड़ रूपया खर्च करके बनाया गया है। इससे सारा वह तबाह ादा इलाका बच गया है। यह इस सरकार ने उस क्षेत्र के लिये एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अब उस जगह पर जहां पर पहले पानी ही पानी खड़ा रहता था मैंने खुद जाकर देखा है, हरी-भरी लहलहाती हुई फसलें नजर आ रही है। इससे पोहलू साहब जैसे इन भाइयों को यह पता चल जाना चाहिये कि हमारी यह सरकार किसानों का

कितना ध्यान रखती है। खासतौर पर जनता सरकार ने अपने बनने के बाद खेती की तरफ पूरा ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने प्रधानता कृषि को दी है क्योंकि हमारा प्रदे 1 कृषि प्रधान प्रदे 1 है और इसलिये बजट का 65 से 70 प्रति 100 हिस्सा जो एक बड़ा भारी हिस्सा है, खेती के ऊपर लगने का प्रावधान करने का विचार किया है। यहां पर खेती को सुधारने के लिये पानी की तबाही से तबाह गुदा इलाके को बचाने के लिये काफी ड्रेनें और लिंक ड्रेनें निकाली गयी है। जहां पहले पानी नहीं पहुंचता था वहां पर एम0आई0टी0सी0 से या दूसरे नलकूपों को भारी तादाद में बिजली देकर पानी पहुंचाया है। जहां पहले किसानों को दिन में कभी बिजली मिलती ही नहीं थी, वहां पर अब दिन में 18-18 घंटे बिजली देकर किसानों का भला किया है। 18 हजार नलकूपों को पिछले साल बिजली दी गयी है और अब भी 18 हजार नलकूपों को बिजली देने के लिये प्रावधान करने का विचार गवर्नर साहब के ऐड्रेस में बताया गया है। इसके अलावा, सरकार ने 20,000 किलोमीटर लम्बी नालियां बनाने का भी प्रावधान करने का विचार बताया है। जहां पर पहले पानी पहुंचता नहीं था, वहां पर इससे पानी पहुंच सकेगा और इससे किसानों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा 40,000 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिये भी राज्यपाल महोदय ने अपने इस ऐड्रेस में कहा है। इसके लिये बिजली के काफी यूनिट्स तैयार किये जाने के बारे में ताकि खेतों को और कारखानों को बिजली दी जा सके, भी प्रावधान करने का विचार बताया गया है। इससे मैं समझता हूं कि खेती

में ज्यादा इजाफा होगा और भारी तादाद में पैदावार होने से गरीबी दूर होगी। सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिये जितना काम किया है उससे किसान की दशा बदल जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। इसके साथ ही साथ इसी बाढ़ के बारे में मेरा एक सुझाव है कि जहां सरकार ने किसान के फायदे के लिये बाढ़ को रोकने के लिए इतने अच्छे कदम उठाए हैं और वे सराहनीय हैं लेकिन दूसरा भारी समुदाय जो चालीस प्रतिशत के करीब बाकी रहता है, जिनके कच्चे मकान हैं, चाहे वे हरिजन हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या दूसरे भाई हैं उनके बारे में मैं अपना सुझाव रखना चाहता हूँ। सरकार चाहे कहीं से भी पैसा लाए, रिजर्व बैंक से लाए या वर्ल्ड बैंक से लाए और जिनके कच्चे मकान हैं और जो हर साल फ्लड से तबाह हो जाते हैं उनके लिये सरकार कुछ न कुछ अवसर करे। उनकी हालत तो ऐसी है कि जब वे मकान बनाते हैं तो उसमें केवल दो-एक महीने रहते हैं और फिर बारिश होने से वे गिर जाते हैं और वे बेचारे चार-छः महीने आसमान के नीचे बैठकर दिन काटते हैं। फिर वे अपना मकान बनाते हैं और दो एक महीने उसमें रहते हैं और फिर वे फ्लड से गिर जाते हैं। ऐसी उनकी हालत है। मेरा इस बारे में सुझाव है कि जितने भी हरियाणा में कच्चे मकान हैं उनको पक्का बनाने के लिये सरकार खुद हर जगह कालोनी बनाए और थोड़ी सस्ती किस्तों पर उन लोगों को वे मकान दे दिए जाएं ताकि हर साल की परेशानी से वे गरीब लोग बच जाएं। वरना हालत ऐसी होती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वे लोग सिर्फ दो महीने अपने मकान में

रहते हैं और फिर फलड से वे मकान गिर जाते हैं और फिर खुले आसमान के नीचे एक छान में उनको गुजारा करना पड़ता है। मैं जनता सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर जरूर ध्यान दे। यह जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा काम होगा। उपाध्यक्ष महोदय जैसे कि मैंने बताया है कि मेरी सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये खेती की तरफ प्राथमिकता दी है और इसके साथ ही साथ कुटी उद्योग की तरफ भी ध्यान दिया है। कांग्रेस सरकार जो कि हरिजनों की बड़ी खैर-ख्वाह बनती थी, पिछले तीस सालों में कोई काम नहीं किया। हजारों साल से यहां का दस्तकार जिस तरह से काम करता था आज भी वह उसी तरह से करता है। गांव का जुलाहा जिस तरह से पहले पुराने ढंग की खड्डी लगाकर कपड़ा बुनता था आज भी उसी ढंग से बनाता है। मोची जिस तरह से पहले जूते बनाता था आज भी उसी ढंग से बनाता है लकड़ी का काम करने वाला वही पुराने तरीके से काम करता है। इसी तरह से लोहे का काम करने वाला लुहार पुराने तरीके से कुल्हाड़ी बनाता है लेकिन पिछली सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि इन बैकवर्ड क्लास के लोगों को और दस्तकारों को नई ट्रेनिंग देकर उनकी आर्थिक हालत को सुधारा जाए। आज जनता सरकार ने इस बात का ध्यान किया है और कुटीर उद्योग के लिये चार यूनिट, दो यूनिट और तीन यूनिट की बात की है जिसमें दो तीन पढ़े लिखे नौजवान मिलकर कोई उद्योग धंधा आरम्भ कर सकते हैं जिसके लिये एक लाख रूपया सरकार देगी। उसमें दस हजार रूपया सबसिडी भी रखी गई है

और पहले जो रूपया इंडस्ट्री लगाने वाले के जिम्मे रखा था वह भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने खत्म कर दिया है। यह बहुत बड़ा काम है। मैं इसके बारे में एक सुझाव दूंगा कि जहां कुटीर उद्योग स्थापित करने की तरफ सरकार इतना ध्यान दे रही है वहां पर इन उद्योगों में काम करने वाले जो नौजवान लड़कें हैं उनको काम सिखाने के लिये उद्योग सेंटर खोले जाएं और ऐसे उद्योग सेंटर हर तहसील में और हर बड़े गांव में खोले जाएं और जो लड़के आधुनिक उद्योगों के बारे में सीखकर उन सिखलाई सेंटर से निकलें उन्हीं को कर्जा दिया जाए ताकि वे लड़के आधुनिक तरीके की फैक्ट्री आदि खोल सकें तभी ये कुटीर उद्योग कामयाब होंगे अन्यथा हालत यह होगी कि जब कोई नौजवान किसी ट्रेड के बारे में जानता ही नहीं होगा और वह सरकार से पैसा ले लेगा तो वह उस काम में फेल हो जायेगा और सरकार का पैसा भी खत्म हो जाएगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के सिखलाई सेंटर खोले जाएं और जो लड़के आई0टी0आई0 से सीखकर निकलें या जो इस प्रकार के सिखलाई सेंटरों से सीख कर निकलें उन्हीं को सरकार की तरफ से कर्जा मिले। तभी यह स्कीम कामयाब होगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। शिक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई नई बात नहीं है। वही पुराने ढर्रे की बात है जो कांग्रेस के जमाने में थी। डिप्टी स्पीकर साहब, शिक्षा इस देश की नींव

है। अगर कोई दे टा ि िक्षा के मामले में पीछे है तो वह किसी भी मामले में पीछे है तो वह किसी भी मामलें में कामयाब नहीं हो सकता है और वह गरीबी से ऊपर नहीं उठ सकता है। ि िक्षा के लिये जरूरी है कि लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ें। हरियाणा प्रदे टा में और खास तौर से ग्रामीण इलाके में लड़कियां लड़कों की निस्बत केवल दस या पंद्रह परसेंट ही पढ़ी लिखी मिलेगी। मैं ि िक्षा के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि हर कालिज के साथ एक छात्रावास अव य होना चाहिये। गांवों में प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल से पढ़कर जब कोई लड़की हाई स्कूल या कालिज में पढ़ना चाहती है तो कोई मां बाप अपनी लड़की को किसी दूसरे के पास कैसे रख सकता है और यही कारण है कि लड़कियों की ि िक्षा में दिक्कत आती है। हर कालिज या हाई स्कूल के साथ छात्रावास अव य होना चाहिये। जब तक लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तब तक दे टा ऊपर नहीं उठ सकता है। एक लड़के के पढ़ने से एक व्यक्ति पढ़ता है लेकिन एक लड़की के पढ़ने से पूरा परिवार पढ़ता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां कालिज हो वहां पर छात्रावास जरूर बनाया जाये ताकि लड़कियां सेफ इज्जत से रह सके और ि िक्षा प्राप्त कर सके। तकनीकी ि िक्षा के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। सिर्फ इतना ही दुबारा कहना चाहता हूं कि अगर कुटीर उद्योग को कामयाब करना है तो सिखलाई सेंटर आधुनिक ढंग के खोले जाएं जिससे कि एक गांव का मोची उसी ढंग के जूते बना सके जैसे कि बाटा कम्पनी बनाती है। एक लुहार उस

ढंग के पुर्जे बना सकें जिस प्रकार के पुर्जे बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरीज बनाती है। इसलिये यह जरूरी है कि कुटीर उद्योग को कामयाब करने के लिये सिखलाई सेंटर अब य खोले जाएं (व्यवधान)।

जनता सरकार ने हरिजनों के लिये चौपालें बनाने का जो प्रोग्राम बनाया है यह बड़े उपकार का काम किया है और पिछड़ा हुआ तबका इस जनता सरकार का बड़ा आभारी है। जो पिछड़े हुए लोग है उनके यहां अगर मेहमान आ जाते थे या कोई बारात आती थी तो रहने के लिये कोई जगह नहीं होती थी लेकिन अब इन चौपालों के बन जाने से बारात और मेहमानों की समस्या हल हो जायेगी। सरकार ने इन चौपालों की स्कीम तो बना दी है लेकिन पैसा अभी नहीं आ रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस काम की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये।

काम के बदलें में जो अनाज देने की स्कीम है यह बेरोजगार को रोजगार देने की एक अच्छी स्कीम है और सरकार ने ऐसा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। पहले मजदूर को चार या पांच रूपये मिलते थे अब जनता सरकार के द्वारा काम के बदले अनाज देने की स्कीम से मजदूर को गेहूं मिलेगा तो उसको डयोढ़ी मजदूरी मिल जायेगी क्योंकि उसको गेहूं सस्ता मिलेगा और गांव में जब तालाब खुदेंगे सड़कें बनेगी तो बेरोजगारों को काम मिलेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत बढ़िया स्कीम है और सराहनीय काम है।

सरकार ने जलधर स्कीम का भी जिक्र किया है और यह जनता सरकार पूरे हरियाणा में जहां पानी खारी है और चाहे वे पीने के लिये खारा है या खेती के लिये खारा है वहां पर सरकार पानी देगी। यह भी सरकार का बहुत अच्छा काम है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

कामरेड भांकर लाल(सिरसा): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मेरे दूसरे कई साथियों ने भी सरकार की गतिविधियों के बारे में चर्चा की है। राज्यपाल महोदय का जो भाषण होता है उसको हमारी सरकार चीफ मिनिस्टर साहब की सलाह से बनाती है और राज्यपाल महोदय तो केवल उस ऐड्रेस को पढ़ देते हैं। अभिभाषण के पीछे हमारी सरकार की भावनाएं होती हैं यानि कि हरियाणा सरकार ने इस अभिभाषण को बनाकर राज्यपाल महोदय को दिया और उन्होंने यहां पर आ कर पढ़ दिया। सबसे पहले मैं आने इन सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस जनता सरकार को बड़ी कुर्बानी और कान्ति के साथ बनाया है और हमारी इस जनता सरकार ने जो फ्लड का काम किया है उसके लिये वह वाकई बधाई की पात्र है (तालियां) ऐसा करना कोई आसान बात नहीं है कि इतना भारी फ्लड हरियाणा के अन्दर आ जाए और सरकार अपनी कोर्णों से तबाही से बचा लें।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज कल इस दे 1 में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वे किसानों की समस्याएं हैं। आज इस दे 1 का किसान बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। किसान की सरकार को हर तरह से मदद करनी चाहिये जोकि अन्न भगवान को पैदा करता है। आपको पता होना चाहिये कि अगर किसान अन्न ज्यादा पैदा करेगा तो दे 1 खु 1हाल होगा और अन्न तभी ज्यादा पैदा होगा जबकि सरकार हर तरह से किसानों की दिल से मदद करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसके साथ-साथ जो दूसरे गरीब लोग हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिये। अगर एक ही तबके की नुमाइंदगी कोई सरकार करेगी तो दे 1 के अन्दर वह सरकार ठीक ढंग से नहीं चल सकेगी। सरकार को दूसरे गरीब तबके जैसे गरीब मजदूर जो कि खेतों में काम करता है, देहात के अन्दर काम करने वाले लोग जिनके पास जमीन नहीं है झुग्गी झोपड़ी वाले लोग मुजारे खानाबदो 1 लोग, देहातों में रहने वाले सैंसी, बावंरिया और दूसरे पिछड़ी जाति के लोग, इन सभी गरीब लोगों पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार छोटे उद्योगों की बात करती है। मैं भी कहता हूँ कि छोटे उद्योगों की जो बात है वह ठीक है पर उन छोटे उद्योगों को फायदा छोटे लोगों को नहीं हो रहा है बल्कि इन उद्योगों का फायदा बड़े-बड़े जमींदार, सरमायेदार और पूंजीपति उठा रहे हैं। आज जो गरीब हरिजन

गांव के अन्दर पिछड़ा हुआ है, वह इसका बिल्कुल फायदा नहीं उठा रहा है। इसलिये सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब लोगों का भी उत्थान हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं चौपालों की बात भी कहना चाहता हूं जोकि हरिजनों के कल्याण की बात है। हमारे हरियाणा के अन्दर काफी चौपालें बनी हैं, जोकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की देन है, यह उन्होंने बहुत सूझबूझ का काम किया है, मगर इस काम में नुकस क्या है? जब तक इस सरकार को उसके नुकस नहीं बताये जाएंगे तब तक सरकार अंधेरे में रहेगी। मुहल्ले के अन्दर चौपालें बनती हैं। अलग अलग कुनबे होते हैं, सैंसी कहते हैं यहा पर चौपाल बनाओ हरिजन कहते हैं कि यहां पर चौपाल बनाओ और दूसरे लोग कहते हैं कि यहां पर चौपालें बनाओ लेकिन चौपालें बनती हैं उन लोगों की मर्जी पर जिन के पास रहने के खाने के पीने के ओर अपना जीवन निर्वाह करने के साधन हैं। वहां पर किसान, गरीब, मजदूर हरिजन और दूसरे छोटे तबके के लोग जिस जगह को चौपालों के लिये सिलक्ट करते हैं, उन जगहो पर चौपालें नहीं बनाई जाती और बड़े-बड़े सरमायेदार खाते-पीते लोग जिन जगहों को सिलेक्ट करते हैं वहां पर चौपाले बना दी जाती हैं। मेरी अपनी राय है कि सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि कौर खु । होगा, कौन नाराज होगा सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय 50-60 प्रति 100 के करीब

ऐसी चौपालें है जोकि अभी अधूरी ही है जहां पर केवल पत्थर ही लगे है।

डिप्टी स्पीकर साहब, भाहरों के अन्दर रिक् गा वाले, टेले वाले और ट्रक ड्राइवर वगैरह बसते है और झुग्गी झोपड़ियों और रेढ़ी खौंमचने वाले लोग बसते है छोटे दुकानदार है, जो बेचारे सारा दिन तकड़ी से काम करते है, ऐसे लोगों को भी सरकार अगर छोड़गी तो वह सरकार कोई अच्छे वातावरण में नहीं रह सकेगी। इसलिये इस सरकार पर मेरा इलजाम है, कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। (गोर एवं व्यवधान) इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सड़कों की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सरकार सड़कों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करती है, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मेरे सिरसा हल्का के अन्दर एक भी सड़क पिछले 12 महीनों के अन्दर पूरी नहीं की गई है, सभी सड़कें अभी तक अधूरी ही पड़ी हुई है। इस के इलावा डिप्टी स्पीकर साहब मेरे हल्के के अन्दर कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है। मेरे हल्के के अन्दर घग्घर नाली चलती है उसके अन्दर 20-25 गांवों का एक हिस्सा है जो आगे को है वहां पर तो बांध बांधा गया है और इधर पंजाब वाले बांध बांध रहे है। उसमें 14-15 गांव दक्षिण की ओर है और 16 गांव पूर्व की ओर है। मैं इन गांवों के नाम बता सकता हूं। ये है:- नेजाडेला, बुडामाना, साहरनी, किराडकोट,

मलेवाला नगौका, बुर्जकर्मगढ़, फरमाई, पनिहारी और मासहवाला ये कुछ गांव हैं, वहां पर बांध नहीं बांधा गया है। जब घग्घर नाली में पानी आएता तो ये सारे के सारे गांव तबाह हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी हमारे चीफ मिनिस्टर पर होगी। हमें जानबूझ कर छोड़ा गया है क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब मेरे हल्के से नाराज है। इसलिये उन्होंने मेरे हल्के को छोड़ रखा है न वहां कोई स्कूल बनाया है और न ही कालेज। मेरे हल्के के अन्दर बाबा आदम के जमाने का एक पुराना हस्पताल है जिसकी हालत बहुत खस्ता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब चौटाला के अन्दर नया हस्पताल बन सकता है तो सिरसा जो जिला हैडक्वाटर है वहां पर क्यों नहीं बन सकता? कहीं खेलने-कूदने की जगह बन रही है तो वह चुटाला में बन रही है, कहीं हस्पताल बन रहा है तो वह चुटाला के अन्दर बन रहा है और कहीं होटल बन रहा है तो वह चुटाला के अन्दर बन रहा है। सिरसा जिले का बजट का 75 प्रति शत खर्चा चुटाला के अन्दर खर्च हो रहा है। मैं यह इल्जाम इसलिये लगा रहा हूं कि आज मुझे सरकार की तरफ से छोड़ा जा रहा है, मेरे से नफरत की जा रही है। मैं यह बात साफ तौर पर कह रहा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जागीरदारों के जो मुजारे हैं उनकी बेदखलियां हो रही हैं। जिनके पास सरप्लस जमीन है वह हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। जिला सिरसा के अन्दर बड़े-बड़े जागीरदार हैं, बड़े-बड़े लैंड लार्ड हैं। ये सारे चौधरी देवी लाल के रि तेदार हैं, इसलिये इनकी जमीन सरप्लस में नहीं आ रही

है। जो कोई एक आध विरोधी होगा उसकी जमीन सरप्लस में आ रही है। मैं यहां पर किसी की खुद गामद करने के लिये नहीं आया। मैं जनता पार्टी का आदमी हूँ और मैं इसलिये आया हूँ कि जनता पार्टी ठीक काम करे और हमारा नेता हरियाण के अन्दर ठीक काम करे। मैं ने आकपे सामने बातें तो और भी करनी थी लेकिन समय कम होने के कारण इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता। अन्त में इतना जरूर कहूंगा कि जनता पार्टी को ताकत में लाने की हमारी सब की जिम्मेदारी है। हम जनता पार्टी के सिपाही है इसीलिये मैं जो कुछ कह रहा हूँ यह जनता पार्टी को ताकत में बने रहने के लिये कह रहा हूँ। एक बात मेरी और है.....

श्री उपाध्यक्ष: भांकर लाल जी आपका समय हो चुका है, अब आप बैठिये (विधन)

कामरेड भांकर लाल: दोस्तों मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुजारों की बेदखली बंद होनी चाहिए और सरप्लस खुलनी चाहिए और भाहरी गरीब लोगों को जो पीछे रखा गया है उनको साथ रखा जाए। आज आप कारखानों में देखें, वहां पर छंटनियां हो रही है। आज दादरी के अन्दर जो सीमेंट फ़ैक्टरी है उसमें मजदूरों की हालत बहुत बुरी है। इसके अलावा दो-दो हजार तक ऐडहौक बेसिज पर लगे हुए मास्टर बैठे है उनको रैगुलर किया जाये। इन मास्टरों की हालत आज बहुत खराब है मेरे कहने का मतलब यह है कि सब की तरफ देखा जाए, एक

तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि

***** (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये अब आपका समय हो चुका है।

Expunged as ordered by the chair.

चौधरी संत कंवर: किसी से ***** नहीं लिया गया, लोगों ने अपनी मर्जी से दिया था।

कामरेड भांकर लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता।

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो ***** इक्ठे करने के बारे में कहा गया है यह लफ्ज ऐक्सपंज होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: जबरदस्ती चंदे वाली बात कार्यवाही से निकाल दी जाए।

श्री जगन नाथ: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि गवर्नर ऐड्रेस पर और बजट पर जब बोलते हैं तो दोनों पक्षों को हिसाब से टाईम दिया जाता है। लेकिन अपोजि उन के तीन आदमी बोल चुके हैं और इधर से उस हिसाब

से टाईम नहीं दिया जा रहा है। इसलिये आप हमें भी हिसाब से टाईम दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: हिसाब से ही चल रहे हैं।

(17.00 बजे) Shri Inderjit Singh(Jatusana): Mr. Deputy Speaker, I thank you very much for giving me time to speak on the Governor's Address. I also thank the Governor for delivering his Address. At the same time, Mr. Deputy Speaker, I would like to debate some of the discrepancies that have appeared to me in this Address. The first discrepancy that has come to my notice is the omission of the transfer of the Fazilka and Abohar areas to Haryana which, I think the Government has conveniently forgotten to mention.

श्रीमती भांति देवी: मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगी कि वे हिंदी में बोलें।

श्रीमती सुशमा स्वराज: मैं आपके द्वारा इनसे कहूंगी कि जिस वक्त इन्होंने वोट मांगे थे, क्या वे अंग्रेजी में बोल कर मांगे थे। ये या तो हरियाणवी में बोलें या हिंदी में बोलें।

श्री भाम ोर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह मेडन स्पीच है, इनको एनकजमेंट दी जानी चाहिए। रूलज में इस बात की पाबंदी नहीं है कि कोई सदस्य हिंदी में ही बोलें।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुर ीद अहमद पदासीन हुए)

Shri Inderjit Singh: I would request the hon. Members not to interrupt me. If I speak in English it is not that I have any disrespect for any hon. Member of the House (Interruptions). It is so because I may be able to express myself better. (Interruptions).

श्रीमती भांति देवी: चेयरमैन साहब, मेरी आनरेबल मैम्बर से रिक्वैस्ट है कि वह हिंदी में बोले क्योंकि यह हमारी स्टेट की भाशा है और इसी बेसिज पर हरियाणा प्रान्त बना था।
(तोर)

Mr. Chairman: Please take your seats. I would request the hon. Members not to interrupt his and let him continue his speech.

Shri Inderjit Singh: I would like to exercise my right and I would speak in English (Interruptions).

श्रीमती भांति देवी: माननीय सदस्य हिंदी में बोले
(विघ्न)

Mr. Chairman: This is no point of order. Both the languages are the languages of the House and any member can speak in any of these languages. I would, therefore, request the hon. Members to please take their seats (Interruptions). No member has the right to obstruct any member like this.

श्री सुरेंद्र सिंह: बहन जी, आप भी अंग्रेजी में बोल लेनार। अंग्रेजी भी हाउस की भाशा है और अगर यह आनरेबल

मैम्बर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको क्या एतराज है।
चेयरमैन साहब भी तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। (विघ्न)

Mr. Chairman: I know much better. Everybody knows it. Please take your seats.

Shri Inderjit Singh: Mr. Chairman, as I was saying-----

चौधरी गंगा राम: हाउस के अंदर यह वि वास दिलाया गया था कि सारी कार्यवाही हिंदी में चलेगी क्योंकि यह स्टेट की भाशा है लेकिन इस अ योरेंस का पालन नहीं हुआ।

Mr. Chairman: This is no point of order. Please take you seat.

चौधरी गंगा राम: आप पिछली प्रोसीडिंग्ज निकाल कर देख लीजिए, उसमें अ योरेंस दिया गया था कि हाउस में हिंदी भाशा का ही प्रयोग किया जायेगा।

Mr. Chairman: You are taking the time of the House. This is no point of order. Please take your seat.

Chaudhri Ganga Ram: It is a point of order.

Mr. Chairman: This(English) is also the language of the House. It is being used and it can be spoken. Please take your seat.

चौधरी गंगा राम: हम आपके हाउस की कार्यवाही चलने में पूरा कोआप्रे तन दे रहे हैं लेकिन यहां पर दिये गये अ योरेंस का पालन नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: किसी मैम्बर को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह कौन सी भाशा का इस्तेमाल करे। (विघ्न)

श्रीमती भांति देवी: हाउस में अ योरेंस दिया गया था कि हिंदी भाशा का प्रयोग किया जायेगा। (विघ्न)

श्री सभापति: यह गलत बात है ऐसा कोई अ योरेंस नहीं दिया गया था दोनों भाशाएं हाउस की भाशाएं हैं और कोई भी मैम्बर कोई भी भाशा का इस्तेमाल कर सकता है।

चौधरी गंगा राम: चेयसरमैन साहब, सारे हाउस की कार्यवाही हिंदी में चलनी चाहिए और माननीय मैम्बर को भी हिंदी में बोलना चाहिए। (विघ्न)

Mr. Chairman: Mr. Ganga Ram, please take your seat. No such assurance has been given that every member will speak in Hindi. It is the choice of the member to speak in whatever language he wants to speak. There should be no more points of order on this issue. Please take you seat now.

चौधरी गंगा राम: चेयरमैन साहब, हाउस की कार्यवाही हिंदी में चलनी चाहिए और सब मैम्बर्ज को हिंदी में बोलना चाहिए। (विघ्न)

Mr. Chairman: You cannot restrict the member to speak in a particular language.

चौधरी गंगा राम: आपने वि वास दिलाया है कि इसका पालन होगा, हिंदी में कार्यवाही होनी चाहिए। (विघ्न)

Mr. Chairman: There are more than 100 rulings in this House that any language of the House can be used.

चौधरी गंगा राम: चेयरमैन साहब, हम आपको कोआप्रेट कर रहे हैं लेकिन मैम्बर को हिंदी में बोलना चाहिए। (विघ्न)

Mr. Chairman: I cannot force any member to use any particular language.

श्री भामोर सिंह: चेयरमैन साहब, हाउस में डिसिप्लिन तो आपको एनफोर्स करना पड़ेगा। (विघ्न)

Mr. Chairman: I would request the hon. Members to maintain discipline and abide by the rules of the House.

चौधरी गंगा राम: चेयरमैन साहब, यह ऐसा नहीं करके सारे प्रान्त की बेइज्जती कर रहे हैं.....

Mr. Chairman: Please take your seat. I am on my legs.

चौधरी गंगा राम: चेयरमैन साहब, आप उनको कहें कि हिंदी में बोलें। (विघ्न)

Mr. Chairman: Either you take your seat or I will have to name you.

चौधरी गंगा राम: चेयरमैन साहब, आप यह आर्डर निकाल सकते हैं कि जब कोई मैम्बर बोले तो वह हिंदी में ही बोले। (विघ्न)

Mr. Chairman: Please take your seat. मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वह कौन सी भाशा इस्तेमाल करे दोनों भाशाएं हाउस की भाशाएं हैं।

चौधरी गंगा राम: यहां कहा गया था कि कार्यवाही हिंदी में होगी। (विघ्न)

Mr. Chairman: Please take your seat first. If any member does not observe the discipline of the House, I will have no alternative but to name him. I draw the attention of the hon. Member to Rule 77 which reads-

“Subject to the provision of Article 210 of the Constitution, the proceedings of the Assembly shall be conducted in Hindi or in Punjabi or in the English language.”

This is the rule of the House.

श्रीमती भांति देवी: चेयरमैन साहब, अगर रूलज को भी देखा जाये तो इसमें हिंदी लैंगुवेज का नाम पहले आया है। (विघ्न)

श्री सभापति: आप बैठिये।

वित्त मंत्री(मूलचंद जैन): चेयरमैन साहब, मैं आपकी इज्जत से हाउस के सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि वह इस कंट्रोवर्सी में न पड़ें सरकार पर यह पाबंदी है कि सरकार का सारा काम हिंदी में होना चाहिए लेकिन अगर कोई सदस्य दूसरी भाशा में बोलना चाहता है तो उस रूल के अन्दर कोई पाबंदी नहीं है। (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है.....

Mr. Chairman: The Minister for Parliamentary Affairs is speaking. The member should have the patience to listen him first.

श्री मूल चंद जैन: अगर अपोजी उन के भाई अंग्रेजी में बोलकर अंग्रेजी के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो मेरे साथियों को क्यों एतराज है। उनको अंग्रेजी से प्यार दिखाने दें। इसलिये मैं अपने साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले में सैंटीमेंटल न हों। अगर कोई अंग्रेजी से प्यार दिखाना चाहता है तो उसे दिखाने दें और माननीय सदस्य को अपनी स्पीच करने दें।

श्री जगन नाथ: चेयरमैन साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये चाहे पंजाबी में बोलें, चाहे अंग्रेजी में बोलें इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए लेकिन कोई भी मैम्बर हाउस के अन्दर अपना भाषण पढ़कर नहीं सुना सकता कोई अपना प्वायंट

कंसल्ट कर सकता है लेकिन अपनी स्पीच पढ़कर नहीं बोल सकता।

Mr. Chairman: You cannot say that he was reading. He was not allowed to proceed even (Interruptions). A member cannot read his written speech. He can, however, consult his notes.

श्रीमती सुशमा स्वराज: आपने अभी यहां रूल पढ़कर सुनाया, इसमें यह लिखा है कि असैम्बली की कार्यवाही हिंदी, पंजाबी अंग्रेजी किसी भी भाशा में चल सकती है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जी ने भी कहा है कि किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। रूलज के मुताबिक आपकी बात सही है लेकिन मैं आपके द्वारा भाई इंदरजीत सिंह से कहना चाहती हूँ कि रूलज के मुताबिक वे अंग्रेजी बोल सकते हैं लेकिन नैतिकता या मोरैलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए और क्योंकि हमारी स्टेट की भाशा हिंदी है और इसी आधार पर हमारा प्रान्त बना था तो मैं। रिक्वैस्ट करूंगी कि हाउस की कार्यवाही हिंदी में चलनी चाहिए। (विघ्न)

Mr. Chairman: When there are explicit rules of the House, the rules of morality and of good conscience do not prevail and they cannot contravene the rules of the House.

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मैं भाई इंदरजीत सिंह को याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हरियाणा राज्य बना था और स्वयं राव बीरेंद्र सिंह ने यहां पर संघर्ष किया था

कि हिंदी भाषी क्षेत्र होने के कारण हरियाणा राज्य बनाया जाए, आज वह नैतिकता आपके सामने कहां है। आपको चाहिए कि आप जो भी संबोधन करें वह हिंदी में करें।

Mr. Chairman: Please take you seat.

वाक आउट

श्रीमती सुशमा स्वराज: कम से कम आपको उस नैतिकता का ख्याल रखकर हिंदी में बात करनी चाहिए (गोर) अगर रूलज आपको इजाजत नहीं देते तो कम से कम नैतिकता का ख्याल रखकर ही हिंदी में बात करनी चाहिए। रूलज की टैक्नीकैलिटी हिंदी के बोलने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कम से कम नैतिकता के कारण इनको हिंदी बोलनी चाहिए। (विघ्न)

श्री सभापति: आप तारीफ रखिए।

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, आप इनको हिंदी में बोलने के लिये कहें।

श्रीमती भांति देवी: सभापति महोगदय, रूलज के हिसाब से हिंदी पहले आती है।

श्री सभापति: मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। मैम्बर की मर्जी है चाहे वह किसी भी भाशा में बोले।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अगर आप उन्हें हिंदी में बोलने के लिये नहीं कहते हैं तो मैं बाहर चली जाती हूँ।

Mr. Chairman: You are taking the time of the House unnecessarily. The hon. Member may be allowed to continue his speech.

(At this stage Shrimati Sushma Swaraj and Shrimati Shanti Devi staged a walk out).

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराम्भ)

Shri Inderjit Singh: Mr. Chairman, I was saying that certain discrepancies have come to my notice in this Address which I would like to mention. It appears to me that the Government has conveniently forgotten to mention anything about the transfer of Fazilka and Abohar areas to Haryana in this Address for which an award was given in 1969. More than nine years have passed since this award was given but these areas have not so far been included in Haryana. It was given on the basis that the Hindi speaking areas of Punjab will come to haryana and the Punjabi speaking areas will go to Punjab. It was linked with the fact that there are certain boundary disputes between Haryana and Punjab which were to be settled by a commission (Interruptions).

सदस्य को निकालाना

चौधरी संत कंवर: आन ए प्वायंट आफ आर्डर।
चेयरमैन साहब, हम भी इस चीज को मानते हैं कि यहां पर हिंदी

भाशा का ही प्रयोग होना चाहिए लेकिन कई भाई जो हिंदी बोलने की दुहाई दे रहे हैं वे कई बार क्लबों में जा कर खुद अंग्रेजी में बोलते हैं (गोर)

श्री सभापति: आप बैठिए। यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

स्वामी आदित्यवे T: चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य को हिंदी में ही बोलना चाहिए (गोर)

श्री सभापति: स्वामी जी, आप बैठ जाइए। आप रूलज में देख लीजिए (गोर) इनमें सब कुछ दिया हुआ है। मैं रूलज के अगेन्सट कुछ नहीं कर सकता और मैम्बरों को मजबूर नहीं कर सकता कि वे किस भाशा में बोलें।

स्वामी आदित्यवे T: सभापति जी, जब सब सदस्य हिंदी जानते हैं तो सब को हिंदी में ही बोलना चाहिए (गोर)

श्री सभापति: स्वामी जी आप तारीफ रखिए। मैं किसी सदस्य को मजबूर नहीं कर सकता कि वह कौन सी भाशा का इस्तेमाल करे (गोर)। If he chooses to speak in English, he can do so. आप माननीय सदस्य को अपनी स्पीच जारी करने दीजिए।

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब, यहां पर दो स्वामी बैठे हैं। एक स्वामी जी बिहार से आए हैं और दूसरे आंध्र प्रदेश से आए हैं (गोर)

(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

Mr. Chairman: Please do not disturb the hon'ble Member and let him continue his speech. You are wasting the time of the House (Interruptions) मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप बैठिए। आप किसी को भी मजबूर कर सकते हैं लेकिन बराबर के किसी मैम्बर को कोई दूसरा मैम्बर इस हाउस में मजबूर नहीं कर सकता कि वह कौन सी जवान इस्तेमाल करेगा। यह मैम्बर की फ्री च्वाएस है। आप गवर्नमेंट को पाबंद कर सकते हैं लेकिन किसी मैम्बर को पाबंद नहीं कर सकते (गोर)। मैम्बर साहिबान आप बैठिए। मैं खड़ा हूँ (गोर) स्वामी जी आप अपनी सीट पर बैठ जाएं (गोर)।

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, आप इनको कहें कि ये हिंदी में बोले.....

श्री सभापति: स्वामी जी आप तारीफ रखिए I am on my legs (Noise स्वामी जी आप बैठ जाएं।

स्वामी आदित्यवे I: जब ये हिंदी में बोल सकते हैं तब इनको हिंदी में बोलने में क्या कठिनाई है?

Mr. Chairman: I have been requesting you to please take your seat. But you are not obeying the Chair. अगर आप हाउस की प्रोसिडिंग्स को नहीं चलने देना चाहते तो I will have to name you. There is no other alternative with me. This is the question of running of the House. Please sit down (Interruptions). Please take your seat (Interruptions).

स्वामी आदित्यवे I: चेयरमैन साहब, आप मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

Mr. Chairman: I have no other alternative but to name Swamiji. He may please leave the House.

स्वामी आदित्यवे I: हिंदी के प्र न पर अगर आपका यह आदे I है तो मैं हाउस से चला जाता हूँ (तोर एवं व्यवधान)

(इस समय स्वामी आदित्यवे I सदन से चले गए)

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है (तोर)

Mr. Chairman: Please take your seat. No point of order on this now.

श्री भाम तोर सिंह: चेयरमैन साहब***** सदन से जाना चाहते हैं। (तोर)

चौधरी गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, भाम तोर सिंह जी ने कहा है कि

*****बाहर जाना चाहते है। यह स्वामी जी की इंसल्ट है। इसलिये इनको अपने भाब्द वापिस लेने चाहिए।

Mr. Chairman: This is no point of order. इन्होंने कुछ नहीं कहा है।

चौधरी गंगा राम: चेयरमैन साहब, इन्होंने कहा है कि *****बाहर जाना चाहते है।

Mr. Chairman: I did not hear it from anybody else. Only you are saying this. Shri Inderjit Singh may please continue his speech.

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है (तोर)

Mr. Chairman: I have given my ruling on this. I cannot entertain any more point of order on this. Please take your seat and allow the hon. Member to continue his speech (Interruptions).

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब, स्वामी अग्निवे । आंध्र प्रदे । के है और एक स्वामी जी बिहार के है। ये स्वामी अग्निवे । और स्वामी आदित्य वे । वहां बिहार में और आंध्र में जाकर तो हिंदी का नाम लेते नहीं है और हरियाणा में हिंदी के ठेकेदार बन गए है। यहां पर किसी को अंग्रजी बोलने नहीं देते है.....

Mr. Chairman: Please take your seat. This is no point of order. (Interruptions). You cannot force the Chair to accept your point of order.

अध्यक्ष महोदय के आदे ानुसार कार्यवाही से निकाल दिए गए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराम्भ)

Shri Inderjit Singh: Mr. Chairman, I was saying that the award to transfer Fazilka and Abohar areas to Haryana was given in 1969 and this was linked with the transfer of other areas and it was decided at that time that there would be a boundary commission appointed which will decide as to which of the other areas are to go to Punjab and which are to come to Haryana. Now this dispute apart, Fazilka and Abohar areas were awarded to Haryana but I do not know how in this Address no mention has been made thereof and these places have been totally ignored. What is happening now? These areas are with Punjab and in the schools everybody is being taught Punjabi with the result that in another five years' time Punjab will claim that these areas should not go to Haryana because the population of these areas is Punjabi speaking. This is why I would request the Government that it should make a statement that the transfer of these areas to Haryana will be got affected and these areas will not be ignored. This is most important. If the Government has not been able to take the areas which had been awarded to Haryana more than nine years back, how can we expect that it would be able to get its share in Ravi-Beas

waters and Their Dam Power (Interruptions) which are matters of only three years old.

श्री दीप चंद भाटिया: चेयरमैन साहब, मेरे साथी ठीक ही कह रहे हैं कि इनको हिंदी में बोलना चाहिए (व्यवधान)

Mr. Chairman: Please take your seat.

Shri Inderjit Singh: I do not understand why these members are agitated over my speaking in English. I am also an equally elected member as anybody else and can exercise my right to speak in English.

The next point is about the law and order situation in the State. Several members have spoken on it and I do not want to elucidate much on this. I would, however, like to cite one instance which will prove my point and indicate the law and order situation in the State. Sometime back, as you know, the Defence Minister of India accompanied by Professor Sher Singh, Central State Minister, came to Rohtak. They were stoned and lathi-charged by the people in the very presence of the police. When they were to go back to Delhi from Rohtak after they were free from their programme, the roads were blocked and even the Police could not keep the roads open with the result that they had to be sent to Delhi through circuitous route (Interruptions).

Shri Verender Singh: While as Prime Minister when Smt. Indira Gandhi came to Rohtak, she was shown black flags.

Shri Inderjit Singh: What I mean to say is that even the Police could not keep the roads open for them to go to Delhi through the route they had come.

The other point that has been missed in the Governor's Address is about population control. Nothing has been mentioned about it. We all realise that India is a very fast growing country in population and something must be done to check population growth. Everytime the House meets, mention is made about the emergency excesses and that the people were forcibly sterilised and vasectomised etc. in the discussion. I do not say that the things done during the emergency were right. The forcible sterilisation and vesectomisation etc. was bad. But same thing is happening now in spite of the fact that the Government has been saying that forcible sterilisation will not take place again and assurances have been given to this effect. How is it? I have got a telegram with me which came to me yesterday saying that one Shri Dhani Ram, a young man of 23 years and unmarried, was forcibly sterilised at Nahar on 13-12-1978 (Interruptions.)

Mr. Chairman: How is it that he was sterilized in December, 1978, but you got the telegram only yesterday. It becomes irrelevant at all. What does it say, please read out.

Shri Inderjit Singh: Regarding this case the Chief Medical Officer had ordered an enquiry on 9-2-1979. That is why the telegram has come now.

Mr. Chairman: Please wind up now.

Shri Inderjit Singh: What I want to say is that what is happening is a direct challenge to the Government. In this very House assurances have been given that there will be no forcible sterilisation etc. yet the same thing is happening. I would like to place this telegram on the Table of the House. (Interruptions).

Rao Birender Singh: This is a definite case which has been stated.

Mr. Chairman: Please give it to office. We will have to examine it if it can be placed on the Table of the House.

(At this stage the telegram was handed over to the Chairman)

Mr. Chairman: This is not authenticated. It cannot be laid on the Table of the House. Please try to wind up now.

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair)

Shri Inderjit Singh: The next point is about flood control. It is very nice that the Government has made some arrangements for controlling the floods. But no mention has been made about Mohindergarh at all in this Address. Nor has any mention been made about the taming of the Sahibi Nadi which causes a lot of havoc in the area.

Shri Verender Singh: Whenever I go to Mohindergarh, you are never available (Interruptions).

Shri Inderjit Singh: Another thing which I would like to talk of is the Government's much publicised food for work programme. Before I continue any further on this I would like to make a point that before partition i.e. before Independence there was a system called the 'Begar system'. Under this system the big land-lords used to have bonded labour and the people were given 'anaj' for the work done. (Interruptions) That system is also called 'Paitia' which means giving of food to fill the belly for the work done.

Mr. Speaker: Please wind up.

Shri Inderjit Singh: The same very thing i.e. 'Begar system' which was abolished by law has been revived by the Government when it is said that 'anaj' will be given for the work done. The Government should give money for the work done. If it cannot give the people money for the work done, it is an insult to human dignity. With these words, I would like to thank you again and resume my seat.

मास्टर रिाव प्रसाद(अम्बाला भाहर): स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ विचार व्यक्त करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई भाक नहीं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र किया है, उन में बिल्कुल भी अति योक्ति नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा है। स्पीकर साहब, जब से जनता सरकार सत्ता में आई है, तब से भाायद भगवान इसकी परीक्षा ले रहा है। इस वर्ष और पिछले वर्ष भी भगवान ने जनता सरकार को कठिनाइयों में डाला है। हरियाणा के कुद जिलों में बाढ़ आई और अम्बाला जिले में जिन

स्थानों पर कभी भी पानी नहीं पहुंचता था, बाढ़ के आने से वहां भी पानी पहुंच गया है, बाढ़ ने बड़ी दूर-दूर तक आक्रमण किया। जब हम इन इलाकों के लोगों के पास जाते थे तो लोग यह कहते थे कि कांग्रेस राज में जब कभी ऐसी कठिनाई का सामना करने का मौका आया, बाढ़ के प्रकोपा का सामना करने का अवसर आया तो कांग्रेस सरकार हमारे साथ झूठे वायदे करती थी। स्पीकर साहब, अम्बाला जिला बार्डर का जिला है। इस जिले के किसान यह कहते थे कि हमारे बराबर के गांव को, जो पंजाब में पड़ता है, इसकी फसल बाढ़ आने से उजड़ गई थी, उसको पंजाब सरकार से पैसा मिल गया है लेकिन हरियाणा की सरकार हमारे साथ झूठे वायदे करती रही और किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया। स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार, जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र है कि जिस-जिस गांव में बाढ़ का पानी आया, सब लोग वहां पहुंच गए और लोगों की तकलीफों की जांच की, सुविधाएं दीं और जिन लोगों के कच्चे मकान गिर गए थे उनको फौरी तौर पर तीन-तीन सौ रूपये की ग्रांट दी गई। स्पीकर साहब, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को समय पर ग्रांट दी गई है। डी०सी०, एस०डी०एम०, तहसीलदार, बैंकों के मनेजर या बैंक का कोई अन्य कर्मचारी जो इन्चार्ज होता था, इन सब लोगों ने गांव गांव में जाकर लोगों को पैसा दिया। कांग्रेस राज में कभी समय पर पैसा नहीं देते थे और जब कभी देते थे तो जितना सैंकान होता था उस में से कुछ हिस्सा देते थे, कुछ मिल जाता था, कुछ इधर उधर हो जाता था और लोग

कहते थे कि हमें कर्जा पूरा नहीं मिला। जनता सरकार ने इस बार लोगों को पूरी सहायता दी। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि बरसाती नदियों से बाढ़ आई और जैसे बाढ़ का पानी देहातों को बहा कर ले गया वैसे ही बाढ़ को रोकने के लिये हरियाणा सरकार ने भिन्न भिन्न स्थानों पर बांध और ड्रेनेज का प्रबंध किया। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष और इस वर्ष हरियाणा के ऊपर भगवान की तरफ से बाढ़ का प्रकोप हुआ और इस प्रकोप को रोकने के लिये जनता सरकार सफल रही है। इस प्रकार कठिनाईयों पर काबू पाने के लिये लगभग 138 करोड़ रूपया खर्च करने का प्लान बनाया है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि सारे का सारा हरियाणा गांवों में बसता है, यह ठीक है कि हरियाणा में कुछ इलाके ऐसे दिखाई देते हैं जिन की आबादी भायद एक लाख से अधिक हो गई होगी लेकिन जिस समय 1966 में हरियाणा बना उस समय यहां केवल एक भाहर ऐसा था जिसकी आबादी एक लाख से अधिक थी बाकी सब छोटे छोटे कस्बे थे। उसके बाद गांव के लोग भाहरों में बसने लगे और वहीं पर उन्होंने अपना काम धंधा भुरू किया। परिणामस्वरूप जनता पार्टी की यह सरकार यह विचार कर रही है कि जिन नगरों की आबादी एक लाख से अधिक हो गई है वहां म्युनिसिपैलेटी की बजाय कारपोरे उन का प्रावधान कर दिया जाए।

स्पीकर साहब, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार किसानों की बहबूदी के लिये काफी कुछ कर रही है।

लेकिन सभी सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि ऐजीटे इन के वक्त चौधरी देवी लाल जी ने कहा था कि किसानों की जो मुख्य फसल है गेहूं उसका भाव 150 रूपये विंटल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत मिलनी चाहिए लेकिन सुरेंद्र जी को मालूम होना चाहिए कि चौधरी देवी लाल जी के सामने सारा हरियाणा है। उन्होंने सोचा कि अगर अनाज मंहगा कर दिया गया तो चारों ओर से आवाजें आएंगी कि हमारी तनख्वाहें और महंगाई भत्ता आदि बढ़ना चाहिए। इन्होंने सोचा कि बजाय किसान के अनाज के कीमत बढ़ाने के उनको उनकी जरूरत की चीजें कम रेट पर मुहैया कर दी जाएं जैसे कि पानी सस्ते दामों पर मिल जाए, बिजली का फ्लैट रेट कर दिया गया और दूसरी चीजों पर भी रिलीफ दिया जा रहा है। पहले यह होता था कि अधिक पैसा खर्च करने के बाद भी किसान को उसकी चीज का पूरा पैसा नहीं मिलता था लेकिन अब उसे पहले की निस्बत उसकी चीजों का भाव भी अधिक दिया जा रहा है और उसकी जरूरत की चीजें भी सस्ते दाम पर उसको मुहैया कराई जा रही है। भायद सुरेंद्र जी जब बोल रहे थे वे इस बात को भूल गए कि उनके राज में ग्रीस मिला हुआ डालडा घी 13-14 रूपये किलो मिलता था, चीनी 5-6 रूपये किलो मिलती थी। यही हाल दालों और दूसरी चीजों का था इनको तो इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी कि जनता पार्टी की सरकारने घी का रेट साढ़े नौ रूपये किलो से बढ़ने नहीं दिया, चीनी बहुत सस्ती है और दालों आदि के रेट भी बढ़ने नहीं पाए है। यहां गरीब हरिजन भी

रहता है और दूसरे गरीब लोग भी रहते हैं जिनकी बड़ी मुश्किल से पांच छः रुपये दिन से ज्यादा आमदनी नहीं है, उन सबका ध्यान रखते हुए और किसान का भी ध्यान रखते हुए चौधरी देवी लाल जी ठीक दिना में कदम उठा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं हाउस को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमें किसान की बहबूदी में कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि खेती बाड़ी के ऊपर ही हमारी सारी इकोनोमी निर्भर है। यदि खेती बाड़ी का विकास होगा तो किसान का लाभ होगा और उनके लाभ में सबका लाभ है लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हरियाणा के अन्दर किसानों के अलावा, दुकानदार भी रहते हैं, गरीब हरिजन और दूसरे लोग भी रहते हैं। उनका ध्यान रखा जाना भी अति आवश्यक है।

स्पीकर साहब बेरोजगारी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। इसको दूर करने के लिये जनता पार्टी की सरकार ने कुछ योजनाएं अपने हाथ में ली हैं जैसे कि पशु पालन योजना, डेरी विकास की योजना और मछली पालन की योजना। लेकिन इसके बारे में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके सारे के सारे सदस्य सर्विस में हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके एक सदस्य को भी नौकरी नहीं मिलती। सरकार अगर मंहगाई भत्ता बढ़ाती है तो सर्विस वाले परिवार के तो सभी सदस्यों को मंहगाई भत्ता मिल जाता है और उनका गुजारा बड़े आराम से हो जाता है लेकिन

दूसरी तरफ 10-12 व्यक्तियों वाले परिवार को, जिनका कोई व्यक्ति सर्विस में नहीं है, इस तरह की कोई मदद नहीं मिलती। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यदि वह इस बात पर विचार कर ले कि ज्यादा नहीं तो पति पत्नी में से केवल एक व्यक्ति ही सर्विस में रह सकता है तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी कुछ मात्रा में दूर हो सकती है वैसे तो इन हाथों को काम चाहिए और उस दिना में हमारी जनता पार्टी की यह सरकार अग्रसर हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर ऐड्रेस के अन्दर थोड़ा सा जिक्र बच्चों की शिक्षा के बारे में भी किया गया है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि पिछले वर्ष हर एक कांस्टीच्युएँसी में एक-एक स्कूल अपग्रेड किया गया और जिन गांवों में स्कूल नहीं है वहां स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं। इस वर्ष हर कांस्टीच्युएँसी में दो स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे यानि एक प्राइमरी से मिडल और एक मिडल से हाई स्कूल बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय इसमें कोई भाक नहीं कि इस तरह प्राइमरी और मिडल स्कूल अपग्रेड होने से लोगों को काफी लाभ होगा। जो बच्चे तीन चार मील दूर दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं या जिन बच्चों को स्कूल दूर होने की वजह से उनके मां बाप स्कूल नहीं भेजते थे, वे अब अपने ही गांव में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। स्पीकर साहब, गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार प्राइवेट कालेजिज को 75 परसेंट से लेकर 84 परसेंट तक ग्रांट देगी और

जिन कालेजों की मैनेजमेंट बीमार है उनको भाायद गवर्नमेंट टेक ओवर करने का भी विचार करे। लेकिन अध्यक्ष महोदय प्राइवेट कालेजिज के अलावा कुछ प्राइवेट स्कूलज भी है जिनका डैपुटे 1 न 2 जनवरी को मुख्य मुत्री महोदय से मिला था। उसी दिन एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर्ज के नुमांयदो से बातचीत की थी। जिसमें इनको यह बताया गया था कि किस तरीके से प्राइवेट में काम करने वाल बी0एड0 टीचर्ज को 600 रूपये की रसीद लेकर के दो-अढ़ाई सौ रूपया दिया जाता है और दो अढ़ाई सौ रूपये तनख्वाह वालों को केवल सौ रूपया देकर के काम चलाया जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब को यह सुन कर के हैरानी हुई थी कि जिन लोगों के लिये सरकार ग्रांट देती है उन तक वह पहुंच नहीं पाती बल्कि मैनेजमेंट के द्वारा जो अत्याचार होते है या ज्यादा पैसों की रसीद लेकर के जो कम पैसे दिए जाते है यह बात दूर होगी और उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस का भी प्रबंध किया जाएगा लेकिन गवर्नर ऐड्रैस में इस बात का जिक्र नहीं आया। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं क्योंकि उस मीटिंग में वे भी बैठे थे कि आने वाले 7 तारीख को जो बजट पे 1 होने वाला है उसमें मुझे पूरी आ 11 है कि उसमें जहां प्राइवेट कालेजिज का जिक्र होगा वहां प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर्ज की तकलीफों को दूर करने के बारे में भी कोई अनाउंसमेंट अव य होगी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं ओर कहना चाहता हूँ। यह अच्छी बात है कि गांव को कुछ न कुछ रिलीफ दिए जाने की बात यहां की जाती है लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यहां गांव के साथ साथ कुछ भाहर भी है। भाहर के बिना गांव और गांव के बिना भाहर चल नहीं सकते। इनमें तालमेल अव य होना चाहिए। इन दोनों का यदि विकास समान रूप से होगा तभी हरियाणा का विकास होगा। गवर्नर महोदय भायद भाहरों का जिक्र करना अपने अभिभाषण में भूल गए है। स्पीकर साहब, बाढ़ के दिनों में जहां गांव में नुकसान हुआ है वहां भाहरों के अन्दर म्युनिसिपैलेटीज की सड़कें आदि भी टूट गई है और वहां की गंदी बस्तियों में रहने वाले हरिजन भाइयों और गरीब लोगों का भी काफी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले बजट में नगरपालिकाओं की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्पीकर साहब, मुख्य महोदय ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और पानी का प्रबंध होना चाहिए ताकि हरियाणा की प्यासी धरती एवं प्यासे मानव को पानी मिल सके। स्पीकर साहब, अम्बाला भाहर की आबादी एक लाख से ज्यादा की है। वह हरियाणा का प्रवेश द्वार है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहां पानी का इतना कहत है कि जनवरी और फरवरी के महीने में भी सुबह अढ़ाई और तीन बजे हमारी माताएं और बहिनें हाथ में बाल्टी लेकर नलके के पास बैठती है और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस तरह खाली बाल्टी लेकर वे आती है उसी

तरह खाल बालटी लेकर वे चली जाती है। इस समस्या का मुख्य मंत्री जी को पता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले बजट के अन्दर इस बात को ध्यान में रखते हुए अम्बाला की नगल लिफ्ट स्कीम के लिये विशेष राशि मुकर्रर की जाएगी। मुझे विश्वास है कि अम्बाला भाहर की पानी की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा नगल स्कीम के द्वारा अम्बाला को जल्द से जल्द पानी दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलते हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गये हैं आप जल्दी से समाप्त करें।

मास्टर टिव प्रसाद: अभी मेरा समय बाकी है। मैं बहुत ही जरूरी बात अर्ज करने जा रहा हूँ। स्पीकर साहब, जनता सरकार ने व्यापारियों को राहत देने का वायदा किया था और हमारे वित्त मंत्री जी ने भी कहा था कि इनको राहत मिलनी चाहिए। मार्किट कमी इन अब डेढ़ परसेंट से दो परसेंट कर दिया है जिससे आढ़ती लोगों को लाभ हुआ है। इसी प्रकार से जो सरचार्ज सरकार ने बढ़ाया था वह भी वापस ले लिया है इससे भी व्यापारियों को लाभ हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप का टाईम पूरा हो चुका है। इसलिये आप समाप्त करें।

मास्टर टिव प्रसाद: मैं केवल एक मिनट में समाप्त करने जा रहा हूँ। सरकार ने जो दो परसेंट से तीन परसेंट

मार्किट फीस बढ़ाई है इससे सरकार को काफी नुकसान हुआ है। अम्बाला भाहर की मंडी बिल्कुल पंजाब के बार्डर पर है जिसके कारण वहां का व्यापार अब पंजाब की मंडियों में जा रहा है दो से तीन परसेंट मार्किट फीस बढ़ाने से जो हरियाणा सरकार को आमदनी होनी थी अब वह व्यापार पंजाब को ट्रांसफर हो जाने से काफी नुकसान हो रहा है। हरियाणा को बहुत घाटा हो रहा है इसलिये मैं जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते से निवेदन करता हूं कि व्यापारियों को अधिक से अधिक राहत दी जानी चाहिए ताकि हरियाणा का व्यापार हरियाणा की मंडियों में रहे। मैं अपने नेता से भी यह निवेदन करूंगा कि व्यापारियों पर से टैक्स कम किये जाएं ताकि ट्रेड बढ़े। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस अभिभाषण की ताईद करता हूं।

राव नारायण(साहलावास): स्पीकर साहब, आज गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर हाउस में डिसकशन चल रही है मैं भी अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस ऐड्रेस में कोई विशेष बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने इस डोक्यूमेंट को तैयार कर दिया और गवर्नर साहब ने हाउस में पढ़ दिया।

जनता सरकार आने के बाद हरियाणा में दो बार फ्लड आया। फ्लड के दौरान बहुत अच्छा काम सरकार की तरफ से किया गया है लेकिन जो कुछ सरकार ने मेरे एरिया में फ्लड के लिये कार्य किया है उसके बारे में मेरा अपना एक सुझाव है। कैप्टन मांगे राम और मेरी कांस्टीच्युएँसी में फ्लड बड़ी आसानी

से रोका जा सकता है। अगर रिवाड़ी झञ्जर रोड़ को ऊंचा करवा दिया जाये और कलवर्टस को बंद कर दिया जाये तो सारी तहसील झञ्जर बच सकती है। जब यह पानी फैलता है तो बेरी तक चला जाता है और फिर झञ्जर पर आ कर अटैक करता है। इसको आसानी से रोका जा सकता है। केवल एक-दो करोड़ रूपये के खर्चे से यह सारा एरिया बचाया जा सकता है। वहां पर इतने गहरे डिप्रैशन है कि वहां पानी जाने के बाद वापिस नहीं आता है। पानी वहीं पर खड़ा रहता है। उसको पम्पिंग सैट्स से ही निकालना पड़ता है।

सरकार ने जिन गांवों में दस-दस फुट ऊंचे रिंग बांध बनाये हैं उनका उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। रिंग बांधों का वहीं पर फायदा होता है जहां पर पानी बहता चला जाये। जिन गांवों में दस रोज से ज्यादा दिनों तक पानी खड़ा रहता है वहां पर पानी अन्दर की तरफ रिस कर बांध के लेवल तक पहुच जाता है। गांवों में रिंग बांध बनाते समय को डिस्ट्रिक्ट इन नहीं की गई इस विषय में कोई विचार नहीं किया गया कि कहां पर रिंग बांध लगाया जाना चाहिए और कहां पर नहीं लगाया जाना चाहिए। हर गांव पर रिंग बांध लगा दिया गया। पिछले दिनों खलीलपुर का रिंग बांध टूट गया था।

स्पीकर साहब, मैं यह कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि हमारी गवर्नमेंट की पंजाब की 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी लेने में फेल्योर रही है। जवाहर लाल नेहरू कैनल जिससे हमारे

रेगिस्तानी एरिया को जो झज्जर के साउथ में है और महेंद्रगढ़ के इंटीरियर को पानी मिल जाना चाहिए था लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है। यह सारा एरिया ख क पड़ा हुआ है। जब तक इस एरिया को पानी नहीं मिलेगा तब तक हमारे इलाके की तरक्की नहीं हो सकती। जिस एरिया में नहर का पानी नहीं लगता है उस एरिया में वाटर सप्लाई स्कीम भी चालू नहीं हो सकती। साहलावास एरिया की सारी बैल्ट में खारी पानी है। रिवाड़ी तहसील के तीन चौथाई एरिया में खारा पानी हैं। चकबंदी के टाईम पर इस एरिया का नाम ही ब्रैकि ट चैक रखा हुआ था। इसी तरह से महेंद्रगढ़ एरिया में भी खारी पानी है। बेरी कांस्टीच्युऐंसी और कैप्टन मांगे राम जी की कांस्टीच्युऐंसी में भी खारी पानी है। वहां पर न तो वाटर सप्लाई स्कीम ही चल सकती है और न ही वहां इरीगे टन हो सकती है। यह एरिया बैकवर्ड का बैकवर्ड ही रहेगा। इस एरिया की तरक्की के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पानी को लेने के लिए हमारी सरकार सेंट्रल सरकार पर जो भी दबाव डाल सकती है, दबाव डाले और जल्दी से जल्दी इस पानी को लिया जाये। स्पीकर साहब जो झज्जर का एरिया उसके साउथ में पड़ता है उसमें और महेंद्रगढ़ जिले में जनता गवर्नमेंट आने के बाद कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम चालू नहीं की गई है और न ही वहां पर कोई रोड्ज की तरक्की हुई है। मु किल से दो-चार गांवों में ही सड़कें बनी है। जितनी और कांस्टीच्युऐंसीज में बनी है उतनी नहीं बनी है।

हमारी गवर्नमेंट की इस बारे में भी बड़ी फेल्योर रही है कि थिन डैम का अपना हिस्सा नहीं ले सकी है। इस थिन डैम में हमें पूरा हिस्सा लेना चाहिए और इस मामले को पूरी तरह से परसू करना चाहिए।

हमारे एरिया में बिजली भी बड़ी लो वोल्टेज पर दी जा रही हैं। आम तौर पर बिजली चली जाती है और किसानों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसानों को आमतौर पर रात को बिजली दी जाती है जिसके कारण ठीक तरह से सिंचाई नहीं हो पाती है इसलिए दिन के समय में बिजली दी जानी चाहिए।

हमारी सरकार ने यह बड़ा भारी सराहनीय कार्य किया है कि सवा छः एकड़ तक का मालिया माफ कर दिया है। यह काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था लेकिन अभी तक माफ नहीं किया था। अन-इकोनोमिक होल्डिंग पर मालिया माफ करके सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है।

सरकार ने जो ट्रैक्टरों का टोकन टैक्स माफ किया है, यह भी बहुत ही अच्छा काम किया है। कोआप्रेटिव भूगर मिलज को जो सबसिडी सरकार की तरफ से दी गई है और किसानों को गन्ने का ठीक रेट दिया है वह भी बड़ा सराहनीय कार्य है। लेकिन बौंडिड एरिया के लोगों को तो फायदा हुआ है मगर अस्सी फीसदी गन्ना बाहर है उनको कोई फायदा नहीं है। बा-रसूख

आदमी बाहर से गन्ना खरीद कर किसी के नाम से मिल में सप्लाई कर देते हैं और जो वहां के लोग होते हैं उनको पूरा गन्ना मिल में देने नहीं दिया जाता है। वे लोग मिनिस्ट्रों से यश किसी और अन्य लोगों से मिले हुए होते हैं जिसकी वजह से यह फायदा उठाते हैं। इस किस्म को स्केन्दल पिछले साल भी हुआ था। इस बारे में मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस बात का ख्याल रखे कि इस साल ऐसा स्केन्दल न होने पाये।

ट्रांसपोर्ट के अन्दर अभी बसिज की बहुत कमी है। हमारी किसान-ओरीएंटिड गवर्नमेंट है और हम हरेक किसान की भलाई के लिये काम करना चाहते हैं लेकिन रूरल एरियाज को जो बसें जाती हैं उनमें इतनी ओवरकाउडिंग होती है कि हमारी मातए-बहिनों को उनमें बैठने के लिये भी जगह नहीं मिलती। कई दफा ता यहाँ तक हो जाता है कि फी पर पाँव रखने को भी जगह नहीं होती। वहाँ पर इतनी ओवर-काउडिंग होती है कि यह हमारे लिये भार्म की बात है।

प्रोहिबिशन की बाबत मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसे एकदम से लागू करना चाहिये। यह काम फेज्ड प्रोग्राम के तहत कभी पूरा नहीं होगा। जब तक आप इसे एकदम से लागू नहीं करेंगे यह काम हरियाणा के अन्दर मुश्किल से ही कामयाब होगा इसलिये आप भाराब को फौरन बंद करे। गवर्नमेंट से यही मेरा अनुरोध है। स्पीकर साहब यह ठीक है कि पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ाई गयी है लेकिन फिर भी ला एंड आर्डर की सिचुएशन इतनी

तसल्लीबख्भा नहीं है जितनी होनी चाहिये। अभी अभी बावल के अन्दर एस0डी0ओ0 के यहां डाका पड़ा है। इससे पहले जींद के अन्दर एस0डी0ओ0 के यहां भी डाका पड़ा था और औरतों की बेइज्जती भी हुई थी। आपकी हिसार बार एसोसिए इन ने इस बारे में एक रेजोल्यू इन भी पास किया है कि ला एंड आडी की सिचुए इन अच्छी नहीं है और यह इंडियन एक्सप्रेस 3 मार्च के अन्दर निकला हुआ है। एक बात जो मैं गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि एमरजेंसी के दिनों में जिन लोगों के साथ विकेटेमाईजे इन हुई थी खास कर गवर्नमेंट सर्वेंटस के साथ वह आज तक वैकेट नहीं हुई है और वह हो भी नहीं सकती क्योंकि आपके अफसर वहीं है जिन्होंने वह विकेटेमाईजे इन की हुई है। जब वह नोटिंग करके भेजते हैं तो जो उन्होंने पहले काम या होता है उसको जस्टीफाई तो करना ही होता है वे जस्टीफाई करके भेजते हैं। और फाईल उसी तरह से उल्टी लौट आती है। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि एक सैपरेट कमेटी होनी चाहिये जो ऐसे केसिज का फैसला करे। कुरु इन रोकने के बारे में बहुत कुछ प्रोपगण्डा होता है। चौधरी साहब ने सरकार बनते ही एक नारा लगाया था कि पानी का प्रबंध भ्रष्टाचार बंद लेकिन अब आम पब्लिक के अन्दर टाक होती है तो लोग यह कहते हैं आजकल तो भ्रष्टाचार का प्रबंध पानी बंद की बात हो रही है क्योंकि पानी तो हमें पंजाब देता नहीं। हमारे नहरें खु क है। हमारी नहरों में पानी नहीं है और अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। कुरु इन के बारे में मैं आपको सालहावास की

ही मिसाल दूंगा। वहां के और सदर थाना रिवाड़ी के तो मैं इनस्टांसिज दे सकता हूं कि वहां पर हम मामले के अंदर कुर्रान होती है। मैंने चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से दो दफा कहा भी था। एक दफा मैंने झाड़ली में कहा था जब वे वहां पर आये थे और दूसरी दफा जब वे नाहड़ में आये थे तब भी कहा था। उन्होंने मुझसे यह वायदा किया था कि आप जिस आदमी का नाम ले दोगे उसी को वहां पर लगा दूंगा। मैंने एक थानेदार मांगा उसका नाम नीचे से चला लेकिन पता नहीं आगे जाकर क्यों कैंसिल हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश से यह कुर्रान कभी नहीं जा सकती जब तक कि यह ऊपर से बंद नहीं होगी। हमारी टौप हैवी एडमिनिस्ट्रेटन है। हमने एम0एल0एज0 को आफिसर्ज दे रखें है। वे इतना टी0ए0/डी0ए0 बनाते है यह आम पब्लिक में टाक होती है। आपको यह तो पता है कि हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है। पुराने पंजाब का पांचवा हिस्सा है। उस वक्त पांच मिनिस्टर्ज हुआ करते थे। अब कितने मिनिस्टर्ज है? पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर उस वक्त पंचा हुआ करते थे। पिछली दफा हमारे यहां तीन मैम्बर थे लेकिन अब फिर पांच कर दिये है पहले एस0एस0एस0 बोर्ड के तीन मैम्बर होते थे लेकिन वे भी पांच कर दिये है जबकि तीन से काम चल सकता था। चंडीगढ़ और अबोहर-फाजिल्का का जिक्र यहां कभी नहीं आता पंजाब वाले तो रोज दावा करते है कि चंडीगढ़ हमारा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट आफिसर्ज को यह हिदायत कर रही है कि बाहर जाओ। पीछे एक लेटर सरकुलर जारी हुआ था जिसमें

डायरैक्टोरेटस को अपनी-अपनी जगह तला ा करने के लिये कहा गया था। बिजली बोर्ड के लिये तो हुक्म हो ही चुके है। इससे पब्लिक के अन्दर एक ऐप्रीहें ानर सी पैदा हो गयी है एक डर सा पैदा हो गया है कि कहीं चंडीगढ़ तो हम पंजाब वालों को नहीं दे रहे है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह तो एक पैकेज डील है। फाजिल्का और अबोहर का नाम क्यों नहीं लेते? हमारी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी होनी चाहिये कि हमें फाजिल्का और अबोहर मिलना चाहिये। हमारे हल्के के अन्दर एक कालेज है। वह कालेज किसान लोग ही चलाते है। 10 साल से किसान लोग चंदा करके उस कालेज को चलाते आ रहे है। वहां पर 30र किलोमीटर के रेडियम के अन्दर कोई भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है। मैं आपके जरिये सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसे गवर्नमेंट कालेज बनायें क्योंकि यह असली किसानों का कालेज है उसके साथ बे ़ुमार जमीन पड़ी है। आप बे ाक वहां पर स्टेडियम बनाइये या कुछ और ताकि वहां पर इम्पूवमेंट हो सके। हमारे यहां कोसली में मंडी सन् 1935 के अन्दर टेक-अप हुई थी लेकिन उसकी आज तक भी डिवैल्पमेंट नहीं हो पाई है। उसकी डिवैल्पमेंट के बारे में क्या कहते है? कहते है कि वहां पर बोली कम लगती है। अध्यक्ष महोदय वहां के लोग गरीब है इसलिये वहां पर बोली तो कम लगेगी ही। उन प्लाटस को बेचा जाये ताकि लोग वहां पर मकान बनायें और मंडी चले। इन भाब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी हुक्म सिंह(दादरी): स्पीकर साहब, गवर्नर साहब, के अभिभाषण में फ़्लड का जिक्र किया गया। फ़्लड पिछले दो साल से हरियाणा में आये। चौधरी देवी लाल की सरकार ने लोगों के मुफ़ाद के लिये क्या काम नहीं किया? उनका खाना दिया गया, उनको कपड़ा दिया गया, उनको दवाइयां दी गयी और खेती करवाई गई। बीज और खाद उनको दी गयी। देवीलाल की सरकार ऐसा इन्जाम करने जा रही है कि जिससे हरियाणा के अन्दर कभी फ़्लड न आयें। फ़्लड आया, यह तो एक भगवान की मेहरबानी हो गयी। क्योंकि 30 साल तक कांग्रेस के राज में कभी इतनी बारी नहीं हुई। बड़े आदमी कहते हैं जहां पर प्रजा का राजा पापी और दुष्ट होता है वहां पर कभी बारी नहीं होती। फ़्लड इनके टाइम में इसलिये कैसे आ सकते थे। इनके समय में तो भिवानी जिले में भी अकाल पड़ता था। लेकिन अब चौधरी देवीलाल की सरकार के आने के बाद बारि इतनी हो गयी कि फ़्लड आ गये। हमारी सरकार एक साल में ऐसा इन्तजाम कर देगी कि फ़्लड का नामोनि तान भी नहीं रहेगा। स्पीकर साहब बिजली की बाबत कांग्रेस के राज में यह पोजी तान थी कि खम्बे थे तारें थीं लेकिन बिजली नहीं थी इनके तीस साल के राज की हालत यह थी कि तारें थी खम्बे थे लेकिन बिजली नहीं थी लेकिन अब 24-24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य राव बीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि बिजली गांवों में नहीं मिलती। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे गांव में रहते कहां हैं। वहां पर तो 24-24 घंटे बिजली मिलती रहती है। कांग्रेस के राज

में यह होता था कि रात को बिजली मिलती थी। एक किसान कहता था कि आई तो दूसरा दो मिनट बाद ही कह देता था गई। लेकिन एक बात मैं अपनी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ। किसान जब गेहूँ निकालता है तो उसको थ्रैसर के लिये अलग से टैस्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसकी परमिशन अलग से लेनी पड़ती है। मेरी प्रार्थना यह है कि जिस बिजली से ट्यूबवैल चलता है थ्रैसर भी उसी बिजली से चलता है इसलिये इसमें कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जाता। उसे इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वह थ्रैसर से गेहूँ निकाल ले।

(18.00 बजे) दूसरी बात यह है कि अगर किसान एक महीने के अन्दर अपना बिजली का बिल अदा नहीं करता तो उसका कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए क्योंकि हर किसान की सिक्क्योरिटी जमा रहती है। इंडस्ट्रीज के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री का मालिक समय पर बिजली का बिल जमा नहीं करता तो उसका कनेक्शन नहीं काटा जाता। इसी तरह से किसान का कनेक्शन भी बिजली का बिल अदा न करने पर नहीं काटा जाना चाहिए। यह मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक महीने में ही किसान के ट्यूबवैल का कनेक्शन न काटा जाए। स्पीकर साहब, जनता पार्टी के दो साल के भासन में इतनी पैदावार बढ़ी है जितनी कांग्रेस के तीस साल के भासन में भी नहीं बढ़ी। कांग्रेस सरकार ने अमरीका और रूस से अनाज मंगवाकर लोगों को खिलाया है। लेकिन इन दो सालों में इतनी

पैदावार बढ़ी है कि मंडियों में भी रखने की जगह नहीं है। आज तो हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि विदेशों से मंगवाना ता दूर की बात रही हम विदेशों को भेजने की हालत में है। जब ज्यादा पैदावार होती है तो मंडियों में अनाज ज्यादा आता है और आज हालत यह है कि मंडियों में अनाज डालने की जगह नहीं है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि किसान के अनाज की एक दिन में बोली नहीं लगती। कई कई दिन के बाद बोली लगती है जिससे कि किसान का काफी नुकसान होता है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि चार-पांच गांवों को इक्ठ्ठे मिलाकर एक खरीद का सेंटर खोल दिया जाए ताकि किसान को अपनी पैदावार बाहर में न लानी पड़े और वह अपनी पैदावार गांव में ही बेच सके।

स्पीकर साहब, मैं ला एंड आर्डर की बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा में ला एंड आर्डर की कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अमन की बात है। छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। ला एंड आर्डर की पोजीशन बिल्कुल खराब नहीं है। पुलिस का पूरा प्रबंध है। राव साहब ने हाउस में एक टेलीग्राम दिखाया था कि जब्री नसबंदी की जा रही है। जब जब्री नसबंदी हो रही थी और नसबंदी न कराने पर गोली चलाई जा रही थी लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा था तो राव साहब उस वक्त पार्लियामेंट में बैठकर इंदिरा के जय के नारे लगा रहे थे। इन्होंने उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठाई थी। उस वक्त तो हालत यह थी कि बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा था।

लाखों गरीब लोगों की और खासकर हरिजनों की नसबंदी की जा रही थी लेकिन इन्होंने उस वक्त क्यो नहीं दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठकर यह कहा कि हरियाणा में लोगों के साथ ज्यादाती हो रही है और आज ये टेलीग्राम पे आ करते है। इसमें कोई सच्चाई की बात नहीं है। स्पीकर साहब जनता सरकार से मेरी एक और प्रार्थना है कि हरियाणा के सैक्रेटेरियट में फोर्थ क्लास एम्पलाईज के ग्रेड रिवाइज हो गये है जिससे कि उनको लोन वगैरह लेने और दूसरी सुविधाओं के बारे में सहूलियत हो गई है लेकिन जो दूसरी जगह या फील्ड में फोर्थ क्लास के एम्पलाईज है उनके ग्रेड रिवाइज हो गये है जिससे कि उनको लोन वगैरह लेने और दूसरी सुविधाओं के बारे में सहूलियत हो गई है लेकिन जो दूसरी जगह या फील्ड में फोर्थ क्लास के एम्पलाईज है उनके ग्रेड रिवाइज नहीं हुए है जिससे कि उनको वे सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो कि सैक्रेटेरियट के फोर्थ क्लास के एम्पलाईज को है। मेरी प्रार्थना है कि उनके ग्रेड भी सैक्रेटेरियट के फोर्थ क्लास के एम्पलाईज की सतह पर होने चाहिए। उनको इंक्रीमेंट भी पचास पैसे लगता है। मैं समझता हूं कि एक साल में पचास पैसे इंक्रीमेंट लगना कोई अच्छी बात नहीं है कम से कम एक रूपया इंक्रीमेंट अवश्य लगना चाहिए। आफिस रिवाइज करने की बात कही गई है और राव राम नारायण ने भी कहा है कि बिजली बोर्ड या दूसरे दफ्तरों की बिल्डिंग के किराये पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है अगर ये दफ्तर हरियाणा में रिवाइज कर दिए जाए तो लाखों रूपया महीने की बचत हो सकती है और यह पैसा हरियाणा की वेलफेयर पर

खर्च किया जा सकता है। इससे लोगों को भी काफी सुविधा होती है क्योंकि हरियाणा के लोगों को हरियाणा बिजली बोर्ड के दफ्तर में या दूसरे दफ्तरों में काफी आना पड़ता है जिससे कि उनको काफी परेशानी होती है। अगर दफ्तर में या दूसरे दफ्तरों में काफी आना जाना पड़ता है जिससे कि उनको काफी परेशानी होती है। अगर दफ्तर यहां से शिफ्ट कर दिए जाए तो स्टेट का पैसा भी बच जाएगा और लोगों को सुविधा भी हो जाएगी कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम चंडीगढ़ से अपने दफ्तर हरियाणा में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा चंडीगढ़ पर कब्जा खत्म हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ पर कब्जा खत्म होने वाली बात में कोई जान नहीं है और कांग्रेस वाले इस किस्म का गलत प्रचार कर रहे हैं। इस किस्म की कोई बात नहीं है।

स्पीकर साहब, अब मैं एम0आई0टी0सी0 की बात करता हूँ। स्पीकर साहब, पक्की खालें बनाई जा रही है लेकिन इनमें घटिया किस्म का मैटीरियल लगाया जाता है। इन खालों को पक्का करने के लिये किसान को पैसा देना पड़ता है और घटिया मैटीरियल लगने की वजह से जब वे टूट जाते हैं तो किसान को दुबारा मुरम्मत के लिये पैसा देना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि अगर खाल टूट जाता है और उसकी मुरम्मत होती है तो किसान से उसकी मुरम्मत के लिये पैसा नहीं लेना चाहिए बल्कि सरकार को उनकी मुरम्मत करानी चाहिए। अगली बात मैं दादरी

डालमिया सीमेंट फ़ैक्ट्री की बाबत कहना चाहता हूँ। उसका मालिक इस फ़ैक्ट्री को अच्छी तरह से नहीं चला रहा है। पता नहीं उसके मन में क्या बात है। इससे तीन चार हजार परिवारों पर असर पड़ रहा है। हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह दिल्ली की सरकार से इस बारे में बात करे और अगर इसका मालिक इस फ़ैक्ट्री को नहीं चलाना चाहता है तो सरकार को इसको ले लेना चाहिए। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। स्पीकर साहब, बस मैं इतना ही कहकर खत्म करता हूँ।

चौधरी नारायण सिंह(पटौदी अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पहली बात तो मैं चौपालों के बारे में कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री महोदय ने चौपाल बनाने का जो प्रोग्राम बनाया है उसके अधीन मेरी कांस्टीच्युएँसी में दो गांवों का नम्बर आया था एक ऊंचा माजरा का और दूसरा जनोला का। ऊंचा माजरा में तो चौपाल कम्पलीट हो गई है लेकिन जनोला में आधे हरिजन कहते हैं कि इधर होनी चाहिए ओर आधे हरिजन कहते हैं कि दूसरी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से कुछ झगड़ा पैदा हो गया है। स्पीकर साहब, जैसा कि चौधरी जगन नाथ ने कहा है कि जहां पर धानक भी हैं चमार भी और वहां पर अगर वे दो चौपाल चाहते हैं तो दो चौपाल बननी चाहिए। इससे समस्या का हल हो सकेगा और कोई झगड़े की बात नहीं होगी। दूसरी बात स्पीकर साहब यह है कि मेरी कांस्टीच्युएँसी में फलड का बारबार

जिक किया गया हैं। आप वहां के रहने वाले भी है और आप जानते भी है कि राठीबास, खलीलपुर और इच्छापूरी में अभी तक भी पानी खड़ा हुआ है और अभी तक उसको निकालने के बारे में कोई स्टैप नहीं लिए गए है.....

श्री अध्यक्ष: खलीलपुर में तो कोई ऐसी बात नहीं है।

चौधरी नारायण सिंह: स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब भी वहां पर गए थे और उन्होंने वहां की हालत देखी है और मैं भी खुद देखकर आ रहा हूं इच्छापूरी में तो यह हालत है कि इतने गड़ढ़े है कि पुरु भी उनको पार नहीं कर सकते इंसान की तो बात ही क्या। स्पीकर साहब अभी तक सदन में सफाई मजदूरों के बारे में कोई आवाज नहीं उठाई गई है और न ही उनकी हालत के बारे में यहां पर कोई जिक किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उन बेचारों को चौबीस-चौबीस घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी उनको पेट भर कर रोटी नसीब नहीं होती। स्पीकर साहब मैं अपने कस्बे की बात करता हूं कि वहां पर एन0ए0सी0 में तीस साल से सफाई मजदूर काम करते है लेकिन अभी तक वे परमानेंट नहीं किए गए है और उनकी तनख्वाह भी सिर्फ 150 रूपये है। अगर वे रिटायर हो जाएं तो गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं देगी।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, सारी कमेटियों के सारे एम्पलाईज परमानेंट कर दिए गए हैं। अगर किसी कमेटी के बारे में कोई केस है तो मैं उसे देख लूंगा।

चौधरी नारायण सिंह: स्पीकर साहब, इससे आगे मैं रोडवेज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गुडगांवां जाने वाली बस के लिये लगभग 1000 आदमी होते हैं और आमतौर पर वे कोर्ट टाइम के बाद जाते हैं लेकिन उन बेचारों कोई बस नहीं उठाती है जिससे उनको काफी कठिनाई होती है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बस सर्विस को ठीक किया जाए बड़ी पूअर सर्विस है। स्पीकर साहब इससे अहम एक और मसला है कि दिल्ली में एक इंटरनेशनल पालम एयरपोर्ट है वहां पर काम करने के लिये गुडगांव से बहुत से लोग आते जाते हैं लेकिन हमारे हरियाणा रोडवेज की बसें वहां पर नहीं रुकती हैं जिससे कि लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। परिवहन मंत्री यहां पर बैठे नहीं हैं इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर बस रुकवाने के लिये ट्रांसपोर्ट विभाग वालों को निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि जो सैकड़ों हजारों लोग वहां पर हरियाणा से आते जाते हैं उनको आने जाने की असुविधा न हो।

श्री अध्यक्ष: आप यह प्रोपोजल लिखकर संबंधित मंत्री को भेज दीजिए।

चौधरी नारायण सिंह: स्पीकर साहब, इससे आगे मैं सैल्ज टैक्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सैल्ज टैक्स इतना ज्यादा है कि लोगों पर इसका बड़ा भार है अतः इसको रिमूव किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, मेरा इससे अगला प्वायंट शिक्षा के बारे में है। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि मेरे हल्के में एक दो स्कूल जरूर अपग्रेड किये जाने चाहिए नूंह वाला मामला तो आपके नोटिस में है। इन कुछ बातों के साथ मैं आपके द्वारा एक बार फिर अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन बातों पर गौर करें और लोगों की जो मुश्किल है उनको दूर करे। स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और इसके साथ ही मैं अपना स्थान लेता हूँ।

डा० बृज मोहन गुप्ता(जगाधरी): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए मेरे दूसरे भाइयों ने जो-जो बातें कही हैं मैं उन को रिपीट नहीं करूंगा लेकिन कुछ बातें जोकि मेरे अम्बाला जिला से संबंधित हैं वह मैं कहूंगा। स्पीकर साहब, जब पंजाब था उस वक्त भी अम्बाला जिले के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता था और अब हरियाणा बन गया है तब भी इस अम्बाला जिले के साथ वैसा ही बर्ताव हो रहा है। जहां तक बाढ़ का ताल्लुक है अम्बाला जिले के किनारे पर यमुना नदी और दूसरे सिरे पर घग्घर दरिया पड़ता है और बीच में से अम्बाला का

मारकंडा टांगरी वगैरह नदियां गुजरती है और इसके साथ साथ छोटे छोटे नदी नाले जो पहाड़ों से आते है वह अम्बाला जिला के बीच में से होकर आगे जाते है और इसके साथ साथ अम्बाला जिले में बरसात का प्रभाव भी सब से ज्यादा पड़ता है। बाकी हरियाणा में तो सहिबी नदी वगैरह और दूसरी नदियों में पानी आने के कारण ही सैलाब का डर रहता है पर अम्बाला एक ऐसा जिला है जिसमें हर साल इन नदियों का प्रभाव पड़ता रहता है। आप यह समझ लीजिए कि अम्बाला के लोगों को हर तरफ से नुकसान ही उठाना पड़ता है।

चौधरी भाग मल: अध्यक्ष महोदय मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस का कोरम पूरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कोरम पूरा है।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब मैं कह रहा था कि अम्बाला जिला के लोगों को हर साल बारिश की वजह से जो बाढ़ आती है उसको बर्दा त करना पड़ता है। वहां के लोग कभी चीखों पुकार नहीं करते और इतनी भारी मुश्किलत को चुपचाप बर्दा त करते रहते है। स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अम्बाला की अपनी विशेषताएं है। यमुनानगर में एक कागज मिल है जो सारे भारतवर्ष को कागज देती है और वहां पर एक घी की फैक्टरी भी है जोकि भारत के नार्थ के एरिया

में घी की सप्लाई करती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहां पर एक भूगर मिल भी है चाहे किसी की भी है पर वह सारे एिया में सबसे बड़ी भूगर मिल है जिससे भूगर एक्सपोर्ट होती है। वहां पर एक रेलवे की बड़ी वर्क शाप भी है और साथ ही बर्तनों की एक बड़ी भारी मंडी है। यमुनानगर के बने हुए बर्तन सारे भारतवर्ष में भेजे जाते हैं। कालका में पत्थर का काम बड़ा होता है अम्बाला छावनी में साइंटीफिक रिसर्च वर्क का काम होता है अम्बाला की तहसील नारायणढ़ और सढौरा में बान का काम भी अपने में एक बड़ा भारी उद्योग है, इसके साथ साथ अम्बाला एक ऐसा जिला है जिसमें सेंद्रल ऐक्साईज ड्यूटी सबसे ज्यादा है जिसका हिस्सा सारे प्रदेश को मिलाता है। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद अम्बाला में रिाइड्यूल्ड कास्ट की परसेंटेज भी ज्यादा है, इसी कारण से अम्बाला की पार्लियामेंटरी की सीट रिजर्व रखी गई है। अम्बाला जिला के तीन मिनिस्टर हैं भायद चार भी हो जाएं और अम्बाला जिला के एक जनरल सेक्रेटरी भी है इन सारी विशेषताओं के बावजूद भी अम्बाला जिला को भेदभाव की नजर से देखा जाता है और उसी तरह से बर्ताव किया जा रहा है जिस तरह कि पंजाब के टाइम में अम्बाला जिला के साथ किया जाता था। केवल एक गवर्नमेंट कालेज अम्बाला जिला के अन्दर है और वह भी थोड़े ही सालों से बना है।

इससे आगे मैं यह बताना चाहता हूँ कि अम्बाला जिले में सड़कों की भी बहुत बुरी हालत है। अम्बाला से यमुनानगर को जाने वाली सड़क हाईवे जिसकी दोनों तरफ पुल भी है वह पुल अब टूट गये हैं और उस सड़क की अब बहुत बुरी हालत है दोनों सड़कों पर लगातार पानी चलता रहता है और वहाँ पर सड़क काफी ऊँची नीची हो गई है। आज भी आप अम्बाला से यमुनानगर की ओर जाने वाली सड़क की हालत देखें तो आपको पता लग जाएगा। दो नाले हैं उन पर इस साल पुल बन रहे हैं वहाँ पर भी सड़कों पर पानी की बुरी हालत है। बिलासपुर, सढौरा, छछरौली, जगाधरी और नारायणगढ में सड़कों की बुरी हालत है। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमारे अम्बाला जिले की इतनी इम्पार्टेंस है वहाँ हमारे अम्बाला जिला के साथ इतना भेदभाव क्यों बरता जा रहा है? इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे अम्बाले जिले का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार अब इस तरफ ध्यान देगी।

स्पीकर साहब, एक दो बातें इस ऐड्रेस में और कही गई है कि पिछमी यमुना नहर पर 48 मैगावाट क्षमता की बिजली पैदा करने की स्कीम की पहली स्टेज पर भी काम शुरू हो गया है और इसके इलावा जो दो-दो मैगावाट वाली चार यूनिटों वाली यमुना नगर ताप बिजली स्कीम मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजी हुई है मेरी प्रार्थना है कि उसकी मंजूरी जल्दी से जल्दी भारत सरकार से ली जाए और मुझे पूर्ण आशा भी है कि सरकार

इस काम को जल्दी करवायेगी। लेकिन स्पीकर साहब हमें कुछ भाक सा पड़ता जा रहा है और उसका कारण यह है कि जिस इलाके में यह थर्मल प्लांट लगना है वहां के कुद लोगों ने अपनी कुछ एप्रोच की है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह जो थर्मल प्लांट यमुना नगर जगाधरी को मिला है इससे इसी इलाके को फायदा नहीं होगा बल्कि सारे अम्बाला जिले को फायदा होगा इसलिये इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जल्दी से जल्दी लागू करवाने की कोशिश करें। इसके बाद मैं शिक्षा के संबंध में कुछ कहना चाहता था लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री जी इस समय नहीं हैं इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे इलाके में एक देहाती स्थान है जिसका नाम पंच तीर्थ है। वह एक धार्मिक स्थान है। वहां पर एक सन्यासी जी ने लड़कियों का स्कूल बनाया है जोकि बहुत ही अच्छा स्कूल है। उसके 13-14 कमरे हैं और उसके साथ जमीन भी काफी है लेकिन बदकिस्मती से उस महात्मा की मृत्यु हो गई। वे कैसे गुजरे यह कहानी बड़ी अजीब है। उस स्कूल के चारों तरफ देहाती इलाके लगते हैं और वह बड़ा अच्छा तीर्थ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और मैं पहले भी इस बारे में कह चुका हूँ और रिपोर्ट भी आ चुकी है कि अगर इस लड़कियों के स्कूल को जो काफी इलाके को कवर करता है सरकार अपने हाथ में ले ले तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि अभिभाषण में निष्पक्ष और स्वच्छ प्रशासन देने का

यकीन दिलाया गया है। इस बात में मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल् में नहीं जाऊंगा एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनों जब हम चुटाला में गये और जब वापिस आने लगे तो बदकिस्मती से डबवाली के पास हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरे साथ कुछ साथी भी थे। हमने अपने ड्राइवर को पेट्रोल लेने के लिए भेजा। उस समय अंधेरा हो चुका था। यह सन् 1977 की बात है। ड्राइवर को पेट्रोल लाने में करीब डेढ़ घंटा लग गया। इस दौरान हमने वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछा कि भाई यह इलाका कैसा है क्योंकि हम बिल्कुल निहत्थे थे। उन लोगों ने कहा यह इलाका बिल्कुल साफ इलाका है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से रात को हमको कई जगह और भी जाने का मौका मिला और हमारे पास कुद नहीं होता था। इस चीज को देखते हुए मित्रों के आग्रह पर मैंने पिस्टल के लाइसेंस के लिये जगाधरी के एस0डी0एम0 को ऐप्लीकेशन दे दी। लेकिन वह ऐप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। उसमें कारण यह बताया गया कि मैं हैंडीकेपड और उन-एक्सपीरिएंसड हूं। हैंडीकेप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता लेकिन ऐक्सपीरिएंस के बारे में बताऊंगा कि मेरे से पूछे बगैर ऐप्लीकेशन कैसे रिजेक्ट कर दी। मैंने तीन साल तक एटथ पंजाब मैडिकल बटालियन में ट्रेनिंग ली है और वहां से मैंने 'बी' सर्टीफिकेट भी पास किया हुआ है लेकिन मेरी ऐप्लीकेशन क्या रिजेक्ट की गई इस बारे में मैं ज्यादा डिटेल् में न जाते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि यह जो निष्पक्षता की बात अभिभाषण में

लिखी है हो सकता है पढ़ने में यह हर जगह आती हो लेकिन असल में होता कुछ और है। इन भाब्डों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अम्बाला जिला का भी पूरा ध्यान रखा जाये। अंत में मैं एक बार फिर राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्रीमती भांति देवी(कैलाना): अध्यक्ष महोदय राजपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैंने इस अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा है और मुझे तसल्ली हुई कि हमारी दो साल की यह जनता सरकार भायद किसानों और मजदूरों के लिये कुछ कर पाएगी। राज्यपाल महोदय ने वि शेषकर बाढ़ के बारे में जिक्र किया है और अध्यक्ष महोदय अपने भी देखा और हमने भी देखा कि किस तरह से प्रकृति के प्रकोपा का हमारी बहादुर सरकार ने डट कर मुकाबला किया। मुकाबला ही नहीं किया बल्कि क्या माननीय मुख्य मंत्री क्या मंत्रीगण और क्या हमारे जनता विधायकगण सब गहरे पानी में से गुजरते रहे और लोगों की कठिनाइयों को सुनते रहे। सब ने उन तक खाना पहुंचाया, बिस्तर पहुंचाये और दवाइयां पहुंचाई। यानि बाढ़ राहत कार्य सुचारु रूप से चलता रहा। इसलिये मैं अपनी सरकार को इस बारे में बधाई दिये बगैर नहीं रह सकती। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहती हूं कि पिछले साल यहां पर एक आ वासन दिया गया था कि आने वाले साल में हरियाणा में बाढ़

नाम की कोई चीज नहीं रहेगी लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस साल बाढ़ दोबारा आ गई और हम अपने पहले आ वासन को पूरा करने में असफल रहे। यह बात तो ठीक है कि इस साल भी हमने बाढ़ का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया लेकिन मैं जनता सरकार से कहना चाहती हूँ कि वायदा केवल वायदा बन कर नहीं रहना चाहिए। उस पर अमल भी होना चाहिए। इस साल बाढ़ रोकने के लिये जो पैसा बजट में रखा गया है अगर उसे ईमानदारी से इसी काम पर खर्च किया जाए तो मैं समझती हूँ कि वह बहुत है। लेकिन यह होता नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मेरे हल्के में पुरखास गांव के अंदर 35 किल्लों में एक लिंक ड्रेन है। कागजों के अंदर तो उसकी रि-मौडलिंग हो चुकी है क्योंकि मैंने ऐक्सीयन साहब के पास जाकर उसके कागज देखे हैं लेकिन जब प्रैक्टिकली उस ड्रेन को देखा गया तो मेरा सिर भार्म से झुका गया। क्योंकि वहां पर एक कस्सी भी नहीं चलाई गई थी। जैसे कांग्रेस सरकार आ वासन तो दती रहती थी और काम कोई भी नहीं होता था उस प्रकार के आ वासन हम नहीं चाहते। आपको पता है कि उस सरकार का अन्जाम क्या हुआ। इसके बाद मैं बिजली के बारे में दो भाब्द कहना चाहती हूँ। पहले बिजली के नाम से हरियाणा पर बहुत बड़ा कलंक था क्योंकि किसान 24 घंटे आई और गई के चक्कर में रहता था। बिजली आ जाती थी तो वह ट्यूबवैल पर जाने की तैयारी करता था और जब ट्यूबवैल पर पहुंचता था तो बिजली चली जाती थी। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार बिजली के सकंट

को दूर करने में बहुत कामयाब रही है और आज किसान को 24 घंटे बिजली मिल रही है। जो कारखाने पिछले 30 साल तक इस बिजली का प्रयोग करके अपना उद्योग चलाते रहे उनको आज काफी मायूस होना पड़ रहा है। अब चूंकि समय हो गया है इसलिये मैं अपनी बाकी की कहानी कल को सुनाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: कल श्रीमती भान्ति देवी का भाषण जारी रहेगा।

The House stands adjourned till 2 p.m. tomorrow,
the 6th March, 1979

(18.30*hours)

(The Sabha then *adjourned till 2 p.m. on Tuesday,
the 6th March, 1979).